हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 2003

खण्ड-1, अंक-2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 6 मार्च, 2003

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)19
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)24
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(2)36
वाक आउट	(2)37
स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(2)38
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2)39
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2)41
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)43
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	(2)70
शून्य	

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)71
बैठक का समय बढ़ाना	(2)77
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)77
बैठक का समय बढ़ाना	(2)79
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)79
बैठक का समय बढ़ाना	(2)84
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)84
बैठक का समय बढ़ाना	(2)92
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)92
बैठक का समय बढ़ाना	(2)99
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)99
बैठक का समय बढ़ाना	(2)109
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)109
बैठक का समय बढ़ाना	(2)113
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)113

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 6 मार्च, 2003

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Treatment Plant

***1240. Shri Jai Parkash Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Treatment Plant has been set up by the Government in Ram Nagar, Karnal ;

(b) whether the aforesaid Plant is in running condition ; and

(c) Whether it is also a fact that the Brota drain of the said plant is Katcha ; if so, the time by which it is likely to be made Pucca ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) जी हां, श्रीमान। यमुना एक्शन प्लान के अर्न्तगत, करनाल में रामनगर के पास, एक ट्रीटमैंट प्लांट लगाया गया है।

(ख) जी हाँ, श्रीमान।

(ग) बरोटा ड्रेन ट्रीटमैंट प्लांट का भाग नहीं है। इसे पक्का करने की कोई योजना नहीं है।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री रामपाल माजरा साहब से जानना चाहूंगा कि रामनगर का जो सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट है इसकी डिस्पोजल कौन सी ड्रेन द्वारा रखी गयी है और जो सिंचाई का पानी देते हैं वह कौन से रास्ते से देते हैं।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, यह ठीक है कि 8 किलोमीटर के फासले पर बरोटा ड्रेन पड़ती है और उससे पहले एक कच्चा नाला पड़ता है। इसके लिए हमने एक योजना तैयार की है जिससे सिंचाई की जा सके। इस ड्रेन तक 8 किलोमीटर नाले को पक्का करने के लिए फाईनांस के लिए नाबार्ड को केस भेज दिया है। यह केस टैक्नीकल एडवाईजरी कमेटी के समक्ष रखा जा चुका है और वह पास भी हो चुका है। धन की उपलब्धता होने पर इसे पक्का करके बड़ौता ड्रेन में डाल दिया जायेगा।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब को बताना चाहूंगा कि अढ़ाई साल पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस ट्रीटमैंट प्लांट का उद्घाटन किया था। जब

[श्री जय प्रकाश भुल्ला]

सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है उस समय ट्रीटमैंट प्लांट चलाया जाता है। जब सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती तो यह ट्रीटमैंट प्लांट बन्द रहता है और सारे टैंक भरे रहते हैं जिस कारण लाईन पार का एरिया ओवर फलो हो जाता है और घरों तथा सड़कों पर सारी गन्दगी आ जाती है। मेरी सरकार से मांग है कि इस ड्रेन को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाये ताकि लोगों को इस ट्रीटमैंट प्लांट का फायदा हो सके। अब इस ट्रीटमैंट प्लांट का फायदा न उठाते हुए इन्होंने पुराना सिस्टम, जो पम्प हाउस का है, उसे दुबारा चालू किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस ड्रेन को कब तक पक्की ड्रेन बना दिया जायेगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, माननीय साथी ने यह पूछा है कि यह ड्रेन कब तक पक्की हो जायेगी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि बरोटा ड्रेन तो पक्की होगी नहीं क्योंकि रीचार्जिंग के लिए भी नहरों का कच्चा रहना जरूरी है इसलिए ड्रेन कभी पक्की नहीं होती। सिंचाई के लिए एक एक बून्द पानी को प्रयोग में लाने के लिए एक स्कीम बनाई है लेकिन इसको टाईम बाऊंड नहीं किया जा सकता। जहां तक नाले को पक्का करने की बात है, उस बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि धन की उपलब्धता पर इसको पक्का कर दिया जायेगा। सरकार की कोशिश है कि पानी की एक एक बूंद खेती को सिंचित करने के लिए, खेत की हरियाली के लिए और किसानों की खुशहाली के लिए उपयोग करेंगे।

श्री कृष्ण लाल पवांर : स्पीकर साहब, मैं भी सी०पी०एस० साहब से पूछना चाहता हूं कि करनाल के अन्दर रामनगर का जो ई०टी०पी० प्लांट है, इसके पानी की जो आऊटलैट है क्या उसको बी०ओ०सी० व सी०ओ०डी० से चैक करवाते हैं, यदि करवाते हैं तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, इन्होंने जानना चाहा है कि यह ट्रीटमैंट प्लांट जो बना है, क्या यह चालू हालत में है या नहीं इसकी चैकिंग होती है या नहीं। मैं सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसको जो बी०एच०ई०एल० कम्पनी हरिद्वार में है उसे उनके इन्जीनियर्ज द्वारा हर महीने चैकिंग करवाते रहते हैं। जहां तक इसकी जांच की बात है उस बारे में मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 27-8-2002, 5-10-2002, 6-11-2002, 10-12-2002 व 1-2-2003 को इसकी जांच करवाई गई है। ठीक इसी प्रकार से उसके बी०ओ०सी० के बारे में मेरे साथी ने जानना चाहा है और एफ्लुिएंट के बारे में भी जानना चाहा है क्या इसको चैक करवाया गया है। स्पीकर सर, यह रिपोर्ट्स हैं इसमें रिपोर्ट यह आई है कि आऊलैट से 232 आता है तो 60 निकलता है जो सही पाया गया है। इसी प्रकार से बी०ओ०डी० जो चैक करवाया गया है वह 150 आता है और 28 निकलता है जो नॉर्मली 30 से नीचे होना चाहिए। स्पीकर सर, जो रिपोर्ट आई है वह ठीक आई है और वह प्लांट ठीक रूप से काम कर रहा है।

चौ० रामफल कुण्डु : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सफीदों शहर के अन्दर सफीदों डिब ड्रेन गुजरती है और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उसको पक्का करने का निर्णय लिया गया था। इस बारे में 4300 फुट पक्का करने का निर्णय हो चुका है और 4000 फुट के आसपास का काम बकाया बचा है क्या उसको भी पक्का करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री अध्यक्ष : गम्भीर साहब, आप भी अपनी सप्लीमैंट्री पूछ लें, मंत्री जी इकट्ठा ही जवाब दे देंगे।

डॉ० मलिक चन्द गम्भीर : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सी०पी०एस० महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आज तक यमुना ऐक्शन प्लान के तहत पूरे हरियाणा में कितने ट्रीटमैंट प्लांट्स लगाए गए हैं और फरदर कितने और लगाने की योजना है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक मेरे माननीय साथी ने यह पूछा है कि क्या सफीदों डिच ड्रेन को पक्की करने का सरकार का विचार है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि 'सरकार आपके द्वार' तो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो इस सरकार के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चलाया है। इस बारे में जब उनकी एनांउसमैंट हो गई है। तो उसके ऐस्टिमेट्स बन कर यहां पर आएंगे उसके बाद उस पर धन खर्च होगा। उस ड्रेन को तो पक्का किया ही जाएगा। जहां तक गम्भीर साहब के सवाल का ताल्लुक है, वह इससे सम्बन्धित नहीं है। यह सवाल करनाल के ट्रीटमैंट प्लांट से सम्बन्धित है। जो सवाल उन्होंने पूछा है उसके बारे में अलग से नोटिस दे दें उनको जवाब दे दिया जाएगा।

Subsidy on Fertilizer and Seeds

***1248. I.G. (Retd.) Sher Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide more subsidy on fertilizer and seeds to the farmers in the State during the current financial year ; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : नहीं श्रीमान।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की सरकार अपने आपको किसानों की हितैषी सरकार बोलती है। (विघ्न) भारत सरकार ने 10 या 12 रुपये यूरिया और डी०ए०पी० पर बढ़ाए हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस बारे में आपकी सरकार क्या सोच रही है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि गरीब किसनों को सरकार बीज किस प्रकार और कितनी कीमत पर दे रही है। पीछे जो कुछ चीजों का बीज दिया गया था वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। जुलाना हल्के में केवल 35 किलो बरसीन का बीज दिया गया था वह इतने आदमियों में और कैसे बांट सकते हैं। अगर सरकार किसान हितैषी सरकार है तो उसको किसानों के प्रति थोड़ा जैनरस होना चाहिए।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा खाद का भाव बढ़ाया गया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में पहले ही कह चुके हैं वे इस बारे में देश के प्रधान मंत्री जी से बात करेंगे और अपनी तरफ से उनसे रिक्वैस्ट भी करेंगे कि सबसिडी वगैरा दे कर उसके रेट को कम किया जाए क्योंकि हम समझते हैं कि ड्रॉट की वजह से इस बार फसल पकाने के लिए किसान का ज्यादा खर्च हुआ है। इसलिए इस बारे में हमारी सरकार देश के प्रधान मन्त्री जी से मिल कर बाकायदा बात करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार वैसे भी अपने आप को किसानों की हितैषी सरकार कहती है। अभी जो केन्द्र सरकार का बजट पेश हुआ है उसमें ऐ०सी० कारों इत्यादि का भाव काफी कम हुआ है जब कि डीजल फर्टिलाईजर्ज के रेट्स बजट में बढ़ गए है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में आपकी तरफ से इन पर सबसिडी वगैरा देने के बारे में सरकार से बात हुई है। अगर सरकार इन पर सबसिडी नहीं दे रही है तो किसान के हित के लिए क्या कर रही है ? आज हर चीज महंगी हो

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

रही है। क्या केन्द्र सरकार खाद, बिजली और सीडज़ जैसी चीजों पर कोई सबसिडी नहीं दे रही है अगर नहीं दे रही है तो क्या मन्त्री जी इसका कोई रीजन बताएंगे ? किसानों को अपनी उपज का इतना भाव नहीं मिल रहा है कि वे अपने बल पर सारे खर्च निकाल लें। मंत्री जी कृपया बताएं कि किसान को कोई सबसिडी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप भी अपना सप्लीमैंट्री पूछ लें मंत्री जी इकट्ठा ही जवाब दे देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जैसा कि कहा है मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में प्रधान मंत्री जी से बात की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महादेय जी से जानना चाहूंगा कि अगर प्रधान मंत्री जी इनकी बात पर गौर नहीं करेंगे, रोल बैक नहीं करेंगे तो क्या हरियाणा सरकार खाद और डीजल पर अपनी तरफ से कोई सबसिडी देगी ?

सरदार जसविन्दर सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कैप्टन अजय सिंह जी और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पूछा है तो इसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस बारे में प्रधान मंत्री जी से बात करेंगे। इनको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि फर्टीलाईजर के उपर राज्य सरकार सबसिडी नहीं देती है। भारत सरकार जो सबसिडी देती है उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं और यह सबसिडी सीधे कारखानेदार को दी जाती है। डी०ए०पी० के उपर कारखानेदार का रेट 11,941 रुपये प्रति मिट्रीक टन है और उस पर भारत सरकार सबसीडी 2591 प्रति मिट्रिक टन देती है। इससे अब तक 98.06 करोड़ रुपये की सबसिडी किसानों को मिल चुकी है। डी०ए०पी० इम्पोर्टिड है इसमें जो कारखानेदार का रेट है वह 10,680 रुपए है और 1330 रुपये भारत सरकार देती है और अब तक 8 करोड़ रुपए आ चुके हैं। एम०ओ०पी० का कारखानेदार का रेट है वह 7,592 रुपये है और भारत सरकार से 3137 रुपये मिलते हैं इससे अब तक 3.97 करोड़ रुपए आ चुके हैं। एन०पी०के० 20.20.0 का 9272 रुपये रेट है और इसके लिए भारत सरकार से सबसिडी 1992 रुपये आती है। अब तक 1.17 करोड़ रुपये आ चुके हैं। एन०पी०के० 12.32.16 का रेट 11096 रुपये है और इसमें 2616 रुपये की सबसिडी मिलती है अब तक इसमें 2.24 करोड़ रुपए आ चुके हैं। एस०एस०पी० का कारखानेदार का रेट 3600 रुपये प्रति मीट्रिक टन है और इसमें सबसीडी 650 रुपये आती है। इससे अब तक 1.82 करोड़ रुपये आ चुके हैं। इसके अलावा एस०एस० पाऊडर का कारखानेदार का रेट 3400 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से मिलता है। (शोर एवं व्यवधान) सैन्ट्रल गवर्नमैंट से जो सबसिडी मिलती है मैं उसके बारे में ही बता रहा हूं। (विघ्न) स्टेट गवर्नमैंट सबसिडी नहीं देती है। आपने कभी दी हो तो बताएं। (विघ्न) मैं यही कह रहा हूं कि स्टेट गवर्नमैंट सबसिडी नहीं देती है यह भारत सरकार देती है और उस बारे में ही मैं बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, हैव पेशैंस। (विघ्न) आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

सरदार जसविन्दर सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, खाद के उपर राज्य सरकार कोई सबसिडी नहीं देती है। इनकी सरकार ने कभी दी हो तो ये बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप मंत्री जी का जवाब सुनें । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्दर सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, टोटल 115 करोड़ 97 लाख 70 हजार रुपए हरियाणा सरकार को भारत सरकार की तरफ से सबसिडी आ चुकी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी तरफ से खाद और डीजल पर सबसिडी देने के बारे में सोच रही है ? इस बारे में बताएं। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा है कि स्टेट गवर्नमैंट अपनी तरफ से सबसिडी नहीं देती है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमैंट अपनी तरफ से सबसिडी देती है ।

सरदार जसविन्दर सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर इनकी सरकार ने कभी सबसिडी दी है तो बता दें। इसके अलावा श्री शेर सिंह जी ने इस वित्त वर्ष में किसानों को खाद तथा बीजों पर सबसिडी देने के बारे में पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस 31 मार्च को यह वित्त वर्ष खत्म होने वाला है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि * * * *

श्री अध्यक्ष : फौजी जी आप आपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न) बैठिए बैठिए (विघ्न) फौजी साहब, सबसिडी कैसे निर्धारित की जाती है उस बारे में आपको बताना चाहूंगा । (विघ्न) फौजी जी आप बैठ जाएं। आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) फौजी साहब, आपको क्या पता खाद बीज का ?

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे पता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, आप बैठें । कृषि मंत्री जी ने जो जबाव दिया है वह सही है। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी ने बताया है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब प्रधानमंत्री जी के पास जाकर उनसे मिले थे। अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बड़ा गंभीर है क्योंकि डीजल और खाद के रेट किसानों की चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी या कृषि मंत्री जी बताएं कि अगर भारत सरकार द्वारा इनका रेट कम न किया गया तो क्या ये भारत सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे ? * * * *

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब की इररैलेवैन्ट बात रिकार्ड न करें। अब वित्त मंत्री जी अपनी बात कहेंगे।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में ही मैम्बर्ज को, हुड्डा साहब को एवं कप्तान साहब को इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। इन्होंने समर्थन वापस लेने की बात बार बार कही है। यह बात इनके गले में अटक रही है। ये तो मान रहे हैं कि यह सरकार किसान हितैषी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं मान रहा है कि यह सरकार किसान हितैषी है। यह सरकार तो किसान विरोधी है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत लेकर बोलने के लिए खड़ा हूं। जहां तक किसान हितैषी की बात है अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है कि इन लोगों ने कितना

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो० सम्पत सिंह]

दुष्प्रचार इस बारे में किया है कि गेहूं के दाम पचास रुपये घटा रहे हैं । 580 रुपये दाम था लेकिन मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला के प्रयासों से ही सैंट्रल गवर्नमैंट ने गेंहू का रेट 610 रुपये किया था इसलिए यह किसान हितैषी सरकार है। अध्यक्ष, महोदय, हम प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में हमारे सुझावों को माना। उसके बाद खरीदबन्द के बारे में भी कहा गया कि खरीद नहीं की जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला जी ने दूसरे मुख्यमंत्रियों, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री एवं आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री को साथ लेकर इस बारे में बात की थी इवन पैडी के मामले में भी ये लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे। प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस बात को माना भी था और ड्राउट रिलीफ का पैसा अनाउंस किया था और दिया भी था । लेकिन अध्यक्ष महोदय, इनकी पंजाब में कांग्रेस की सरकार है उसने एक नया पैसा भी किसान को आज तक नहीं दिया है। जबकि हरियाणा सरकार ने बीस रुपये क्विंटल के हिसाब से पहली बार अपनी तरफ से किसानों को दिया है। चाहे सैंट्रल गवर्नमेंट से पैसा कभी आए या ना आए लेकिन किसान हितैषी होने के कारण हरियाणा सरकार ने बीस रुपये क्विंटल के हिसाब से अपने खजाने से खुद दिए हैं इसलिए यह किसान हितैषी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सबसिडी की बात है, आपको मालूम ही है क्योंकि आप खुद इफको के चेयरमैन रहे है, कि सैंट्रल गवर्नमैंट की सबसिडी की स्कीम्ज क्या क्या है। सबसिडी डायरैक्ट कारखानों को जाती है। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि सवा सौ करोड़ रुपये की सबसिडी खाद, सीड एवं जिप्सम पर दी गयी है यह कुल मिलाकर 129 रुपये की पड़ जाती है। इसका डायरैक्ट फायदा किसानों को ही जाता है। ये समर्थन की बात करते हैं लेकिन इनको बड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास कर लिया। धीरे धीरे कांग्रेस सब जगहों से समाप्त होती जा रही है। (शोर एवं व्यवधान) ये कभी एक म्यूनिसिपल कमेटी की बात करते हैं कभी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये बताएं कि देश के अंदर इनके कितने परसैंट एम०पीज० हैं। इनके दस परसैंट एम०पीज० भी नहीं है और अगली बार ये भी नहीं बचेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे चाहे ये कितना ही जोर मार लें। इनका तो सारे का सारा मामला साफ है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए। अब अगला सवाल होगा।

Number of Posts lying vacant in HVPN

***1380. Rajinder Singh Bisla :** Will the Chief Minister be pleased to state---

(a) the total number of sanctioned posts in Group 'A' 'B' 'C' and 'D' in Haryana Vidyut Prasaran Nigam at present, and

(b) the total number of posts out of those referred to in para 'a' above are lying vacant; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to fill up the said vacant post ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में ग्रुप क, ख, ग, तथा घ कर्मचारियों के लिए दिनांक 31-12-2002 तक स्वीकृत पदों तथा रिक्त पदों के बारे में स्तर स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(ए) स्वीकृत पद

श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या
क	270
ख	151
ग	4301
घ	1872

(बी) रिक्तियों की स्थिति

श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या
क	82
ख	36
ग	954
घ	190

(सी) रिक्त पदों को समय-समय पर लागू निगम के नियमों तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार भरा जाएगा।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी, आप बैठ जाएं। आप सो गये थे अब तो आपका क्वैशचन हो लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं देर से पहुंचा इसलिए विषय क्या था मैं पूरा समझ नहीं पाया। लेकिन इनको तो लम्बी चौड़ी लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो रिवाइयल की लड़ाई लड़ रहें हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें देखना है कि कौन आगे बढ़ रहा है अगर इसमें देखा जाए तो श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भजन लाल जी से बढ़कर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्य पर आधारित बात बताने जा रहा हूं। इन्होंने यमुना जल विवाद के मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक में सम्मिलित अख्तियार करके और प्रदेश के हित को ध्यान में न रखकर अलग से एक ढोंग रचा। श्री हुड्डा ने एक जल युद्ध का मुद्दा उठाकर प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की। इन्होंने जो चंदे के पैसे इकट्ठे किए थे उनको खर्च करके, भजन लाल जी आपके खाते में उन पैसों को ज्यादा दिखाने की दृष्टि से हुड्डा जी ने जरूर कुछ सफलता प्राप्त की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठ जाएं यह क्वैश्चन ऑवर है और इसमें इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं । हुड्डा साहब की कोई बात अब रिकार्ड नहीं की जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि * * * * *

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, असैंबली की प्रौसीडिंग में जो बात दर्ज की गई है उसको कायम रखें और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं और इसके लिए भजन लाल जी मुझे स्वयं बता दें कि पार्टी फंड का कितना पैसा इनके खाते में जमा हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक मनी का मिसयूज न हो। भजन लाल जी यदि कहेंगे तो हम इसकी इंक्वारी भी कराएंगे। पार्टी के प्रैजिडैण्ट श्री भजन लाल जी बताएं कि कितना पैसा पार्टी फंड में जमा हुआ है ?

चौ० भजन लाल : यह समय इस बात की बहस का नहीं है। क्वैश्चन ऑवर में ये बातें नहीं करनी चाहिए। यह बात बाद में करनी चाहिए। हम एक एक बात का जवाब देंगे और आप भी हमारी बात का जवाब देना।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप अलग से लिखित देंगे तो हम निश्चित रूप से इस की इंक्वायरी कराएंगे। पब्लिक मनी का मिसयूज आप कैसे करेंगे ?

चौ० भजन लाल : यह तो हमारी पार्टी का मामला है इससे आपने क्या लेना है हम तो आपकी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, आप अपना सवाल पूछें। भजन लाल जी आप बैठ जाएं। यह क्वैश्चन ऑवर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों में एच०वी०पी०एन० में जनरेशन, और ऑगमैंटेशन में बड़े सुधार का काम हुआ है। हमारे अपने फरीदाबाद जिले में दस 66 के०वी० के सब स्टेशन पूरे हुए और 50-60 नये फीडर बनाए जा रहे हैं। सरकार को बधाई देते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार काफी स्थान खाली पड़े हैं। इनकी काफी संख्या है। जो पोस्टें खाली पड़ी हैं यदि ये पद अति शीघ्र भर दिये जाते हैं तो इससे गुणवत्ता में और सुधार आएगा जिससे प्रदेश का बहुत भला हो सकता है। मैं माजरा साहब को बताना चाहूंगा कि कितनी ही आधुनिक मशीनें खाली पड़ी हैं और उन्हें चलाने वाला नहीं हैं। उन खाली पदों के कारण गुणवत्ता कम होती है। क्या माजरा जी आश्वासन देंगे कि खाली पड़े पदों को अति शीघ्र भर लिया जाएगा।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जुलाई 99 से लेकर अब तक 35 नये उपकेन्द्र बनाए हैं और 130 उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा चुकी है। इसके इलावा 75 नये केन्द्र, 55 उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि का कार्य चल रहा है तथा 28 नये केन्द्र, 27 उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि पूरी हो रही है। यह ठीक है कि स्टाफ में कमी आई है लेकिन फिर भी सुधार की कोशिश की गई है। जैसे बिजली के बिलों का वितरण चौकीदार के माध्यम से करवाकर तथा एक आदमी को डुआल चार्ज देकर और कोरियर की सेवा से बिलों का भुगतान किया गया है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तो पोस्ट आफिस का कार्य है। यह कोई प्रश्न का जवाब नहीं है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जब मैंने जवाब दिया था उस समय तो विपक्ष के सदस्य यह कह रहे थे कि छोटा सा जवाब है और इस समय यह कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया। आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश की सरकार 10 मंत्रियों के साथ बखूबी से चल रही है और इनकी सरकार के समय में तो झंडी ही झंडी थी। हमने बिजली की एफिशिएंशी को बढ़ाया है। जहां तक रिक्त पदों को भरने के बारे में सवाल है उनको समय समय पर निगम के नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार भरा जायेगा। स्पीकर सर, सारा काम इसी वजह से प्रभावित हुआ है। बिजली का सबसे ज्यादा काम प्रदेश में हुआ है जिस पर 700 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। नये सब स्टेशन बनाये गये हैं और काफी की क्षमता बढ़ाई गई है। खाली पदों को भरने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बिसला जी क्या आप सैटीस्फाईड हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : जी हां स्पीकर सर।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब ने अपने जवाब में कहा है कि "Vacant posts will be filled up as per Rules of the Nigam and instructions of the State Government in force from time to time" तो मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से जानना चाहता हूं कि क्या निगम में भर्ती मामले में सरकार कोई इंस्ट्रक्शंज जारी करने का एक्ट के मुताबिक अधिकार रखती है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जो इन्होंने प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास हर प्रकार का अधिकार है क्योंकि सरकार ही सब कुछ होती है। पहले भी सीधी भर्ती नियम के अनुसार ही होती रही है और प्रोमोशन भी नियम के अनुसार ही हुए हैं। इसलिए सीधी भर्ती निगम के नियमानुसार ही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास सारे राईट्स होते हैं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, रामपाल माजरा जी ने जवाब में वैकेंट पोस्टें दिखाई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो एम०आई०टी०सी० को बन्द किया है। . . . . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप सवाल पूछिये।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एम०आई०टी०सी० के कर्मचारियों को इस भर्ती के माध्यम से समायोजित किया जायेगा या उनको भर्ती करने का सरकार का कोई और प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप सवाल पूछिये।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, निगम में जो भर्ती होगी वह रूल्ज के मुताबिक ही होगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 1259

(इस समय माननीय सदस्य सरदार निशान सिंह सदन में मौजूद नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)

Ratio of Haryana Cadre Officials with U.T. Chandigarh

***1266. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the ratio of Haryana Cadre Officials to be posted in Union Territory Chandigarh on deputation is not being maintained as per Punjab Re-organization Act, 1966; and

(b) if the reply to part "a" above be in affirmative the cadre-wise officials who are on deputation with the Union Terriory Chandigarh at present vis-a-vis the cadre-wise strength of the Haryana Cadre Officials as per Punjab Re-organization Act, 1966 ?

Mr. Speaker : Regarding Starred Question No.1266 extension has been asked for by the Finance Minister for three months to give reply to the above said Question, the same has been granted. The letter reads as under :

"Interim Reply

Sampat Singh

D.O. No. 1-8-2003-1RN
Finance, Planning and
Parliamentary Affairs Minister,
Haryana, Chandigarh.
Dated : 05-03-2003

Respected Sir,

I would like to state that starred Assembly Question No. 1266 asked by Shri Anil Vij, M.L.A. about the total strength of Haryana Government officers/ officials in the U.T. Administration, has been listed for reply on 6-3-2003. The information regarding officers/officials on deputation with U.T. Administration is being collected from all the departments of Government which is likely to take some time. Also the information regarding total strength of officers/officials in the U.T. Administration is to be collected from the U.T. Administration, Chandigarh for which they have replied vide their letter No. IH(7)-2003/3937, dated 27-2-2003 that the required information is being collected from their respective departments.

2. In view of the above, it is not possible for the State Government to give specific reply of the aforesaid question on 6-3-2003. I would therefore, request that the question may kindly be deferred till for 3 months.

With regards.

Yours sincerely,

Sd/-
(Sampat Singh)

Shri Satbir Singh Kadian,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh."

Self-Employment Scheme

***1260. Ch. Ram Phal Kundu :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state whether there is any scheme namely 'Self-Employment' with the Dairy Development Department ; if so, the details thereof ?

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ० मोहम्मद इलियास) : हां श्रीमान् जी,राज्य में डेरी इकाईयां स्थापित करवाने हेतु एक विशेष स्व-रोज़गार स्कीम डेरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 से चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य देहात/शहरी क्षेत्र के सीमान्त किसानों, कृषि-मज़दूरों तथा अन्य कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों और विधवाओं को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, हरियाणा भूमि विकास बैंकों के माध्यम से डेरी ऋण उपलब्ध करवाकर सहायता और दुधारू पशुओं के मालिकों की आय-वृद्धि करके उनको स्वस्थ जीवन-यापन करवाना है। इस स्कीम के अन्तर्गत 3/5/10 दुधारू पशु डेरी इकाईयों के लिये पशु खरीद व दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के रख-रखाव हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सभी प्रकार की डेरी इकाईयों के लाभप्राप्तकर्त्ताओं को स्वीकृत इकाई लागत 16600/- रुपये प्रति दुधारू पशु 2.25 प्रतिशत की दर से 50 प्रतिशत बीमा प्रीमियम उपलब्ध करवाया जाता है। यह प्रीमियम केवल एक वर्ष के लिये है। अनुसूचित जाति एवं विधवा वर्ग के लाभप्राप्तकर्त्ताओं को तीन दुधारू पशुओं की डेरी पशुओं की डेरी इकाई में डेरी शेड के नवीनीकरण व दुधारू पशुओं की खरीद हेतु 2000/- रुपये की विशेष अनुदान राशि प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा स्थापित करवाई गई डेरी इकाईयां बहुत अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2002 के अन्त तक 5067 डेरी इकाईयां स्थापित करवाई जा चुकी हैं और यह संख्या इस वित्त वर्ष के 10800 डेरी इकाईयों के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध 27-2-2003 तक बढ़कर 6684 हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 27-2-2003 तक 1761 डेरी इकाईयों के केस स्वीकृत हो चुके हैं और लाभप्राप्तकर्त्ताओं द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद की जा रही है। वर्ष 2003-2004 के लिये 12000 डेरी इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभाग द्वारा स्कीम लागू होने से दिसम्बर, 2002 तक 34511 डेरी इकाईयां स्थापित करवाई जा चुकी हैं इस उपलब्धि में 9542 डेरी इकाईयां अनुसूचित जाति व 724 डेरी इकाईयां विधवाओं से सम्बन्धित हैं।

चौ० रामफल कुण्डु : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्व-
10.00 बजे | रोजगार योजना जो सरकार ने लागू की है उसका मापदण्ड पैमाना क्या है ?

चौ० मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री रामफल कुण्डु जी और पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि स्वरोजगार योजना के क्या-क्या मापदण्ड हैं। इसके मापदण्ड निम्नप्रकार से हैं :—

1. शिक्षित/अर्ध शिक्षित युवक एवं युवतियां जो दसवीं पास हों, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए शैक्षिक योग्यता मिडल पास तथा अनुसूचित वर्ग, विधवाएं एवं भूतपूर्व सैनिकों के हिन्दी/उर्दू का मात्र ज्ञान होना आवश्यक है।

[चौ० मोहम्मद इलियास]

2. पांच दुधारू पशुओं के लिए एक एकड़ भूमि होना जरूरी है।

3. तीन दुधारू पशु स्कीम, सामान्य वर्ग व अनुसूचित वर्ग तथा मेवात क्षेत्र व विधवाओं की स्कीम में एक एकड़ भूमि की शर्त हटा दी गई है। ग्रुप गारन्टी से ऋण दिलवाया जाता है।

4. आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है।

5. जो भी लोन लेता है उसका 21 दिन का विभागीय प्रशिक्षण होना चाहिए।

6. बेरोजगार होना चाहिए और लगभग देहात का रहने वाला होना चाहिए।

प्रो० रामभगत : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने पशु धन विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाये हैं। इसमें मिनी डेरियों के मार्फत पढ़े लिखे बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार दिलाने की बात है और काफी संख्या में मिनी डेरियों को ऋण दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो लोन डेरियों के लिए दिया गया है उनमें से कितनी डेरियां हकीकत में चल रही हैं और कितनी नहीं चल रही हैं। क्या इसका निरीक्षण किया गया है। दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज के दिन पशु पालकों को जो दूध की कीमत दी जा रही है वह उचित है ? आज के दिन पशु का चारा बहुत महंगा हो गया है और पशु पालकों को पशु रखने में पहले के हिसाब से अधिक खर्चा करना पड़ता है। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि पशु पालकों को जो दूध की कीमत इस समय मिल रही है क्या यह पूरी कीमत मिल रही है ?

चौ० मोहम्मद इलियास : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने पूछा है कि हरियाणा में इस वक्त कितनी डेरियां काम कर रही हैं, अगर ये इस बारे में वर्ष वार ब्यौरा जानना चाहते हैं तो वह भी मैं बता दूंगा लेकिन इसमें समय अधिक लगेगा। यदि ये पूरा ब्यौरा जानना चाहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हरियाणा में 34511 डेरियां काम कर रही हैं। जहां तक दूध के रेट का सवाल है जो कोआप्रेटीव सोसायटीज़ के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है उस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा जो दूध दूधिया पशु पालकों को देते हैं उससे अधिक रेट हमारी सरकार की इन कोआप्रेटीव सोसायटीज़ द्वारा पशु पालकों को दिया जा रहा है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कितनी डेरियां हरियाणा में काम कर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितना बजट पिछले साल सरकार के द्वारा डेरी डिवैल्पमेंट के लिए डेरी विभाग को दिया गया और जो बजट दिया गया उसमें से अब तक कितना खर्च हो चुका है। दूसरा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नई डेरियां खोले जाने से दूध का उत्पादन पिछले वर्ष से कितना अधिक हुआ है । कृपया मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें।

चौ० मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डेरी के बजट की बात है, उस बारे मे मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डेरी विभाग का करोड़ों रुपये का बजट सालाना का होता है। इस साल भी हमने हरियाणा प्रदेश में लगभग करोड़ों रुपये का लोन डेरियां खोलने के लिए वितरित किया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप यह बताएं कि कितना बजट आपका था और उसमें से कितना बजट आप खर्च कर चुके हैं।

चौ० मोहम्मद इलियास : कितना बजट था इसके लिए आप अलग से सवाल पूछ सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी सम्मानित सदस्य को किसी सवाल के प्रति जानकारी हासिल करनी है तो उसके लिए अलग से प्रश्न किया जाता है न कि जो प्रश्न है उसी में से बीच में से प्रश्न नहीं पूछे जाते। अगर सदस्य इस बारे में जानना चाहते हैं कि कितना बजट दिया गया, कितना पैसा किस साल में सैंक्शन हुआ, कितना ग्रान्ट के माध्यम से आया है और कितना लोगों को दिया गया है, इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिए ये सैपरेट प्रश्न करके सारी सूचना ले सकते हैं। ये इस सदन के पहले भी सदस्य रह चुके हैं और इनको इन सारी बातों का ध्यान होना चाहिए कि कौन सा सवाल किस ढंग से पूछा जाना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम इस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठें ।

Construction of PHC, Jakhal

***1296. Shri Jarnail Singh :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of PHC, Jakhal, district Fatehabad; if so, the time by which it is likely to be completed?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : जी हां, समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाखल 1973 से कार्यरत है। 1973 से लेकर अब तक इस बिल्डिंग को बने हुए 30 साल हो चुके हैं यानि यह बिल्डिंग 30 साल पुरानी हो चुकी है। इस बिल्डिंग को नई बिल्डिंग बनाये जाने का प्रस्ताव है यानि इसका नया निर्माण किया जायेगा। आदरणीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए घोषणा भी कर चुके हैं। इस बिल्डिंग को बनाये जाने के लिए नक्शे बनवा कर भेज दिए हैं। इसके लिए एस्टिमेट्स बनवाये जा रहे हैं और जैसे ही एस्टिमेट तैयार हो जाएंगे तो इस भवन का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त आर०सी०एस० प्रोजैक्ट के तहत 8 लाख 4 हजार 910 रुपये का ऐस्टिमेट तैयार करके भारत सरकार को भेजा जा चुका है जिसकी हमें 31 मार्च से पहले मन्जूरी मिल जायेगी। उसके तहत जाखल के प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर एक डाक्टर रूम, एक लेबर रूम और दो पोस्टमार्टम रूम्ज़ और प्री पोस्टमार्टम रूम तैयार किए जाएंगे।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाखल की बिल्डिंग बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो घोषणा की है, उस पर कब तक निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा और उस पर कितने पैसे का खर्च आयेगा।

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं सम्मानित सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास इसके ऐस्टिमेट्स तैयार हो कर आएंगे। ऐस्टिमेट है कि पी०एच०सी० पर लगभग 80 लाख रुपये के करीब खर्चा आएगा, उसमें से 8,04,910/- रुपये की प्राप्ति हमें भारत सरकार से होगी और बाकी पैसा हरियाणा सरकार उसमें लगाएगी। सम्भावना है कि 31 मार्च के बाद यथाशीघ्र भवन निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षों में पूरे प्रदेश में कितने पी०एच०सीज़० एवं कितने सी०एच०सीज़० आदि चालू किए हैं और कहां-कहां किए हैं ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सबसे पहले पत्थर रख कर जिनका शिलान्यास किया हुआ था उन कामों को पूरा करने का कार्य किया है। उसके पश्चात् 11 नई पी०एच०सीज़० तथा सी०एच०सीज़० का शिलान्यास भी किया गया है और उनका उद्घाटन भी किया है। कुल मिला कर तीन साल में 40 भवन पी०एच०सीज़०, सी०एच०सीज़० और अस्पताल आदि का निर्माण करवा कर हम जनता को समर्पित कर चुके हैं। उसकी जो सूची है वह भी मैं सम्मानित सदन के सामने बताना चाहूंगा। हमारे जो 40 भवन बने हैं वे इस प्रकार हैं— सामान्य अस्पताल, डबवाली, जिला सिरसा, सी०एच०सी० बहादुरगढ़, जिला झज्जर, पी०एच०सी० चुली बागड़िया, जिला हिसार, पी०एच०सी० अचीना, जिला भिवानी, पी०एच०सी० जोसांवाली, जिला सिरसा, अर्बन डिस्पैंसरी, सैक्टर-20, पंचकूला, पी०एच०सी० धारूहेड़ा, जिला रिवाड़ी, पी०एच०सी० काछवा, जिला करनाल, पी०एच०सी० मातनहेल, जिला झज्जर, पी०एच०सी० जाखौली, जिला कैथल, पी०एच०सी० पाई, जिला कैथल, अर्बन डिस्पैंसरी, सैक्टर-4, पंचकूला, पी०एच०सी० बलम्भा, जिला रोहतक, पी०एच०सी० लिलस, जिला भिवानी, 50 बिस्तर ऐडीशनल बिल्डिंग सामान्य अस्पताल, जीन्द, सी०एच०सी० कलायत, जिला कैथल, पी०एच०सी० दरियावाला, जिला जीन्द, अर्बन डिस्पैंसरी, सैक्टर-17, जगाधरी, अर्बन डिस्पैंसरी सैक्टर-10, पंचकूला, पी०एच०सी० पसरेड़ी, जिला अम्बाला, सी०एच०सी० लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र, ऐडीशनल बार्ड सी०एच०सी० गोहाना, जिला सोनीपत, पी०एच०सी० दड़बी, जिला सिरसा, पी०एच०सी० बराड़ा, जिला अम्बाला, अर्बन डिस्पैंसरी, सैक्टर-25, पंचकूला, फर्स्ट रैफरल यूनिट, 30 बिस्तर अस्पताल, सैक्टर-3 फरीदाबाद, लोजिस्टिक स्टोर एण्ड होस्टल भवन, भिवानी, फर्स्ट रैफरल यूनिट, बिल्डिंग 30 बिस्तर अस्पताल, सैक्टर-30 फरीदाबाद, पी०एच०सी० फिरोजपुर बांगड़, जिला सोनीपत, ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल रोहतक, एम०पी०एच०डब्ल्यू० ट्रेनिंग सैंटर गुड़गांव, पी०एच०सी० धोज, जिला फरीदाबाद, सामान्य अस्पताल भवन, रोहतक, पी०एच०सी० रोडी, जिला सिरसा, पी०एच०सी० अलखपुरा, जिला भिवानी, 100 बिस्तरों का नया अस्पताल भवन, पंचकूला, ट्रोमा सैंटर, करनाल सी०टी० सकैन सैंटर, सिरसा, लेटैस्ट पी०एच०सी०, कोट। यह हमने 40 भवन बना कर तीन साल के अन्दर जनता को समर्पित किये हैं।

श्री जसबीर मलौर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे हल्के माजरी और नग्गल में माननीय मुख्यमन्त्री जी ने "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत एक पी०एच०सी०, का शिलान्यास किया था तथा पी०एच०सी०, का कार्य जोरों है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि पी०एच०सी०, नूरपुर गांव की बिल्डिंग आज से 30 साल पहले बनाई गई थी और उसकी बिल्डिंग को हैल्थ डिपार्टमैंट ने अनसेफ

डिक्लेयर कर दिया है। क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनवा दिया जायेगा ? वहां पर सारा स्टाफ है, डॉक्टर्ज भी हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं है, क्या वहां पर बिल्डिंग बनवाने का आश्वासन मंत्री महोदय देंगे ?

डॉ० एम० एल० रंगा : जो भवन अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है उसको पहले गिराया जाए फिर बनवाया जाए यह तो सम्भव नहीं है। पंचायत यदि हमें इसके साथ में अलग से जमीन दे दे जो हमारे मार्ग्ज के हिसाब से हो तो हम उस पर ऐस्टिमेट्स बनवा कर नक्शे बनवा कर निश्चित तौर पर बिल्डिंग बनाएंगे।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे गांव में 1977-78 में चौधरी देवी लाल जी ने एक 30 बैड का अस्पताल मन्जूर किया था। जब कांग्रेस गवर्नमैंट आई तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया। अब 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में चौटाला साहब ने उसको दोबारा मंजूर किया है। मैंने उसके लिए जमीन की रजिस्ट्री भी महकमे के नाम करवा दी है और उसका नक्शा वगैरा भी सब बनवा दिया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह बिल्डिंग कब तक पूरी तैयार हो सकेगी ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, जैसे सम्मानित सदस्य ने पूछा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मुरथल में हमारे यहां 35 कनाल 8 मरले जमीन स्थानान्तरित की जा चुकी है, उसका नक्शा भी अप्रूव हो गया है और उसके एस्टिमैट्स भी 80 लाख रुपये के करीब बने हैं। वे ऐस्टिमैट्स भेजे हुए हैं। जब हमारे ऐस्टिमेट्स मन्जूर हो जाएंगे उसकी स्वीकृति के साथ हम चाहते हैं कि प्रि-प्लानिंग मीटिंग में रखकर 31 मार्च के बाद उसको शुरू कर दिया जाए।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी नहाड़ सी०एच०सी० के लिए शिलान्यास करने के लिए गए थे। वहां की बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया था। आज उसको दो महीने हो गए हैं लेकिन वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए कोई स्टैप नहीं उठाया गया और न ही कोई काम किया गया है। मेरे को तो डाउट लगता है कि यह सरकार केवल घोषणाएं और पत्थर रखने के काम ही कर रही है। वहां पर 70 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। मैं जानना चाहती हूं कि वहां पर काम कब तक शुरू हो जाएगा ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनिता यादव की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैं आधारशिला रखता ही नहीं बल्कि जो आधारशिला रखकर आया हूं या जो भी आधारशिलाएं रखी जाएंगी, वे हमारी सरकार के समय में ही मुक्कमल होंगी। अध्यक्ष महोदय, संयोग से हमारी सरकार में ऐसी हजारों स्कीमें होंगी जिनकी आधारशिलाएं मैंने ही रखी हैं और उनका उद्घाटन भी मैंने ही किया है। कांग्रेस की सरकारों के वक्त में, आज के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल ने 20-20 साल पहले कई आधारशिलाएं रखी थीं और उन आधारशिलाओं पर भी मैंने ही काम पूरा करने का काम किया है। हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं और लोगों के प्रति जो निर्णय लेते हैं उसको पूर्ण करने का काम किया है। निश्चित रूप से नहाड़ की सी०एच०सी० की जो आधारशिला रखी गई है इस पर काम इनके विधायकी कार्यकाल में ही पूरा कर दिया जाएगा।

श्री रमेश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि भजन लाल जी के टाईम में उनके द्वारा घरौंडा में एक अस्पताल बनाने के लिए पत्थर रखा गया था लेकिन वह चौधरी भजन लाल जी के और बंसी लाल जी के कार्यकाल में भी नहीं बन पाया था। मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने इस अस्पताल को बनाने की मंजूरी दे दी है। अब मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह अस्पताल कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां का नक्शा बना दिया गया है और एस्टीमेट बनाकर उसको स्वीकृति दे दी गई है। बजट सत्र के बाद जब भी विधायक साथी को फुर्सत होगी तो उनसे बात करके इस अस्पताल की बिल्डिंग का शिलान्यास कर दिया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार तथा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने हरियाणा के अन्दर स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रगतिशील कदम उठाए हैं। इसके अलावा चौधरी देवी लाल जी के नाम पर देवी रूपक स्कीम चलाई गई है। राज्य में 50 अस्पताल, 64 सामुदायिक केन्द्र, 400 स्वास्थ्य केन्द्र, 2299 उच्च स्वास्थ्य केन्द्र, 39 औषधालय, 64 सचल औषधालय कार्यरत हैं। यही नहीं 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दन्त चिकित्सा भी उपलब्ध करवाई गई है। मैं इस सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद में नांगलजाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन किया है तथा वहां पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है। उसका काम कब तक पूरा हो जाएगा, इस बारे में आदरणीय मंत्री जी बताएं। साथ ही इस बारे में भी बताएँ कि औरंगाबाद और उटावड़ रूपड़का में दो स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य भी कब तक पूरा हो जाएगा।

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी नांगलजाट के बारे में माननीय सदस्य ने सदन में कहा था। रूपड़का और औरंगाबाद के इलावा नांगलजाट का शिलान्यास हो गया है उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। जो इन्होंने रूपड़का की बात की है उस विषय में यह बताना चाहूंगा कि 1988 तक वह पी०एच०सी० तिलपत गांव में चल रही थी। तिलपत गांव ने इसके लिए जमीन स्थानांतरण नहीं की थी इसलिए हमने उसको साथ के गांव में शिफ्ट कर दिया था और बाद में उस गांव की पंचायत ने भी कह दिया कि हमारे पास जमीन नहीं है। स्पीकर सर, चौक रूपड़का गांव के समीप पड़ता है। रूपड़का गांव की पंचायत का प्रस्ताव अब आ चुका है और वे नॉर्मज़ के हिसाब से जमीन देने को तैयार है। हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से गांव की पंचायत को यह लिखा है कि आप यह जमीन हमारे स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानातरण करें ताकि विभाग इसका नक्शा बना करके आगे की कार्यवाही शुरू कर सके। जब इसका नक्शा बनकर पास हो जाएगा उसके बाद ही रूपड़का का कार्य शुरू होगा। जहां तक औरंगाबाद की बात है उसका हमने 52 लाख का एस्टीमेट एप्रूव करके साढ़े 16 लाख प्री प्लैनिंग में डाल दिया था। नक्शे में कोई टैक्नीकल समस्या थी। उस समस्या का समाधान करके प्रि-प्लैनिंग के तहत जो साढ़े 16 लाख रुपये की फर्स्ट इन्स्टालमैंट है उसको यथा शीघ्र जारी करवा दिया जाएगा।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मंत्री जी ने बताया कि जहां पर पी०एच०सीज० नयी बननी है या जहां पर उनकी बिल्डिंग खराब हो गयी है वहां पर अगर पंचायत लिखकर दे दे तो वहां पर सरकार द्वारा पी०एच०सी० बनायी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुढलाना गांव में एक तीस चालीस साल पुरानी बिल्डिंग पी०एच०सी० की है जोकि बहुत खराब हो चुकी है। वहां पर स्टाफ भी बैठता है लेकिन जब बारिश आती है तो वह बिल्डिंग बड़ी खतरनाक हो जाती है। वहां की पंचायत ने बाकायदा जमीन भी इसके लिए दे दी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वहां पर वह बिल्डिंग कब तक बन जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी, आप भी अपना सवाल पूछ लें। मंत्री जी इकट्ठा ही जवाब दे देंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, सवाल अलग अलग हैं तो जवाब इकट्ठा कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी बड़े काबिल हैं वे इकट्ठा जवाब दे सकते हैं।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने धरौंडा में पी०एच०सी० बनाने के बारे में एक पत्थर रखा था लेकिन मंत्री जी ने जो अब जवाब दिया है वह यह दिया है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने उस पी०एच०सी० का नक्शा बनवाया है और मंजूरी दी है। इसका मतलब उसकी मंजूरी भी अब दी है तो क्या चौधरी भजन लाल जी ने उस समय उसका जो पत्थर रखा था वह बिना मंजूरी के ही रखा था ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर इन्होंने बिना मंजूरी के ही उसका पत्थर रखा था तो उसका खर्चा किस के खाते में डाला गया और क्या उस खर्चे की रिकवरी इनसे की जाएगी ?

श्री कपूर चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शाहबाद कस्बा सबसे पुराना कस्बा है। 1865 से शाहबाद में अस्पताल है जोकि अब बहुत पुराना हो चुका है। यहां पर डाक्टर्ज के रहने लायक कोई स्थान नहीं है। वहां का भवन बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा वहां पर पशु घूमते रहते हैं। क्या सरकार इस ओर भी ध्यान देगी क्योंकि शाहबाद जी०टी० रोड पर है और वहां पर बहुत पेशेंट आते हैं। जब सरकार ने वहां पर दूसरी सारी सुविधाएं दी हुई हैं तो सरकार को इस बारे भी ध्यान देना चाहिए।

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो खटक साहब ने सवाल पूछा है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने मुढलाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग के बारे में जानना चाहा है। अध्यक्ष महोदय, सिविल सर्जन के माध्यम से हमने पंचायत से निवेदन किया था कि नोर्म्ज के हिसाब से वह हमें भूमि स्थानांत्रित करवा दें। इसी हिसाब से पंचायत ने हमें भूमि स्थानांत्रित करवा दी है। अब आगे की कार्यवाही के लिए हमने एक्सियन, पी०डब्ल्यू०डी० को लिखा है कि वह नक्शा वगैरह तैयार करवाएं। अध्यक्ष महोदय, जब यह सारा काम हो जाएगा तब हम इसका ऐस्टीमेट्स बनवाएंगे और जब ऐस्टीमेट्स आ जाएगा तो धन की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल भागीराम जी ने पूछा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो पत्थर लगवाए थे उनकी स्वीकृति थी या नहीं। अध्यक्ष महोदय, वे पुराने साथी हैं इसलिये वे पूछ रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने इन पुराने पत्थरों को भी सम्मान

[डॉ० एम० एल० खेरा]

प्रदान किया है और 29 भवन बनाकर जनता को समर्पित किए हैं। पिछले दस पन्द्रह सालों से जो पत्थर लगे हुए थे उनमें से आज के दिन 19 पी०एच०सीज० या सी०एच०सीज० पर निर्माण कार्य चल रहा है। अगर आप कहें तो उनकी सूची मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। जो काम बिल्डिंग पर चल रहा है उनके नाम हैं— ब्लड बैंक, फतेहाबाद, ब्लड बैंक, झज्जर, सी०एच०सी०, मथाना, पी०एच०सी०, बालसमंद, पी०एच०सी०, ओढां, पी०एच०सी० सढौरा, पी०एच०सी०, तरावड़ी, पी०एच०सी०, माजरी, पी०एच०सी०, पंजोखरा, पी०एच०सी०, सोरखी, पी०एच०सी०, नांगल जाट, 50 बिस्तरों का अस्पताल, सफीदों, पी०एच०सी०, अलेवा, पी०एच०सी०, भादसों, पी०एच०सी०, मोहना, पी०एच०सी०, हसनगढ़, सी०एच०सी०, नाहर, पी०एच०सी०, नांगल जाट, सी०एच०सी०, इसराणा तथा इन पर शिलान्यास के कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा सम्मानित साथी श्री वैद्य जी ने बताया है कि शाहबाद में होस्पीटल बहुत पुराने समय का है और आबादी शहर से बाहर आ गई है। यह सच है कि यह अस्पताल इस समय शहर के बीच में है। इसे शहर से बाहर बनाने के लिए हमें नगर पालिका से जमीन भी चाहिए और अगर नॉर्म्स के हिसाब से जमीन होगी तभी बात की जाएगी। इस समय जो अस्पताल की बिल्डिंग है वह इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं है कि गिर जाए। उस बिल्डिंग की रिपेयर भी कराई गई है। बिल्डिंग ठीक है अच्छा काम चल रहा है। जब नगर पालिका जमीन उपलब्ध कराएगी तभी इस पर विचार किया जा सकता है। जब तक जमीन उपलब्ध नहीं होगी तब तक अस्पताल को बाहर ले जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

Quality Control of Milk & Cattle Feed

***1263. Shri Balbir Singh :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state—

(a) Whether there is any laboratory in the state for checking the quality control of Milk and Cattle feed ; and

(b) whether any sample has been taken for checking the quality of Milk and Cattle Feed in the state during the period from 2002 to till date, if so, the details thereof ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौ० मोहम्मद इलियास) : हां श्रीमान् जी। दिनांक 1-1-2002 से 31-1-2003 तक की अवधि के दौरान, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ आदेश, 1992 के अन्तर्गत दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के 4 नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए। दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध गुणवत्ता एवं थनेला बीमारी की खोज करने हेतु जानकारी देने के लिये 5728 दुग्ध के नमूने लिए गए। पशु आहार आदेश, 1999 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2002 से 31-1-2003 तक कुल पशु आहार के 31 नमूने जांच हेतु लिए गए।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सालवार ब्यौरा अलग से बताएं हर साल दूध की गुणवत्ता की जांच के कितने नमूने लिए गए और पशु आहार के कितने लिए गए ?

चौ० मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु 1-1-2002 से 31-1-2003 तक की अवधि में 4 सैम्पल लिए गए। दुधारू पशुओं में थनेला बीमारी हेतु दूध की गुणवत्ता चैक करने के लिए 5728 दुग्ध नमूने लिए गए इनमें से 186 में दूध की थनेला बीमारी पाई गई जिसके बारे में

बचाव एवं इलाज के लिए आवश्यक मंत्रणा दी गई है। पशु आहार की गुणवत्ता चैक करने के लिए 1-1-2002 से 31-1-2003 तक पशु आहार के 31 नमूने लिए गए और इनमें से 11 नमूने भारतीय मानक स्तर के अनुसार निम्न स्तर के पाए गए । जो दोषी पाए गए इनको पशु आहार की गुणवत्ता में सुधार लाने की चेतावनी दी गई अन्यथा भविष्य में यदि ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, बलबीर सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन कंज्म्पशन में मिल्क और मिल्क प्रौडक्ट नंबर वन पर आता है। यह भी एक बहुत दुखद अनुभव है कि हम पूरे प्रयासों के बाद भी मिल्क और मिल्क प्रौडक्ट्स में मिलावट को रोक नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो कैटल फीड हैं उसमें मिलावट की वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने तीन सालों के शासन काल में प्रदेश को बहुत अच्छी पौलिसीज दी हैं क्या इस बारे में भी कोई ऐसी पोलिसी देंगे जिससे सिस्टम फुलप्रूफ हो और इन पदार्थों में मिलावट न हो पाए ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस बात के दृष्टिगत कि परिवार बढ़ने की वजह से भूमि कम होती जा रही है और देश में किसानों द्वारा ज्यादा अन्न उत्पादन की वजह से देश में अन्न के भण्डार भी भरे पड़े हैं। इसके दृष्टिगत सरकार डाईवर्सिफिकेशन की नीति के तहत डेयरी को बढ़ावा देने की पक्षधर है। उसके लिए हमने पशु विकास बोर्ड का गठन किया है। सरकार द्वारा दुधारू पशु पालक किसान को डेयरी के लिए एक हजार से छः हजार रुपये तक का ईनाम देने का निर्णय लिया गया है। 50 प्रतिशत बीमा योजना के तहत किसान का पशु अगर मर जाये सरकार आधी राशि वहन करती है। सरकार ने गारन्टी देकर 85 करोड़ रुपये बैंक से लोन लिया है ताकि किसान लोन से पशु लेकर उसको पाले। हम चाहते हैं कि दूध को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यदि जरूरी समझा जाये तो चिलिंग स्टेशन और मिल्क प्लांट और स्थापित किये जायें। हम चाहते हैं दूध के प्रोडैक्ट्स से संबंधित और चीजों को अच्छी और प्योर बनाया जाए उसके लिए अगर कहीं लैब भी स्थापित करनी पड़ेगी तो स्थापित करेंगे। हम किसान को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के पक्षधर हैं। इस प्रकार से हम प्रदेश के आम नागरिक के स्वास्थ्य सुधार की समुचित व्यवस्था करेंगे और सदन के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि सदस्यों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Shifting of Subzi Mandi

*1334. **Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Subzi Mandi, out side Dabwali City, if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : नहीं, श्रीमान् जी।

Supply of Power

***1326. Diwan Pawan Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government has taken steps to ensure better quality of power supply for Yamuna Nagar district, if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जिला यमुनानगर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2x100 एम०वी०ए० 220/66 के०वी० ट्रान्सफार्मरों की स्थापित क्षमता के साथ जोडियाँ (यमुनानगर) में एक नया 220 के०वी० उपकेन्द्र दिनांक 23-7-2002 को चालू किया गया है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान 2443 लाख रुपये की लागत से 9 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि भी की गई है।

तलाकौर में 279 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक नया 66 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण भी किया जा रहा है। गुलाबनगर में 296 लाख रुपये की लागत पर एक अन्य 66 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। उपकेन्द्र के वास्तविक स्थल के बारे में जिला प्रशासन से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

7 नं० 11 के०वी० फीडरों का पुनर्वास/द्विभाजन/त्रिविभाजन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 8 नं० 11 के०वी० फीडरों का द्विभाजन/त्रिविभाजन का कार्य प्रगति में है तथा 23 नं० 11 के०वी० फीडरों के कार्य को शीघ्र शुरु किये जाने की योजना है।

वर्ष 2003-2004 में 326 लाख रुपये की लागत से रादौर, चान्दपुर, लाडवा तथा सढौरा में चार 66 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है।

Police Training Centre, Bhondsi

***1270. Ch. Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the State Government has acquired any land at Bhondsi in district Gurgaon for setting up a Police Training Centre ; and

(b) If so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां।

(ख) चौधरी देवी लाल पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र भौंडसी में स्थापित करने हेतु 314 एकड़ और 17 मरले ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहण की गई है। इस जमीन की कीमत 12.56 करोड़ रुपये है।

Performance of Thermal Power Stations

***1359. Shri Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any improvement has been made in the performance of State Own Thermal Power Stations during the tenure of the present Government; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

हां श्रीमान। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार के आधीन पानीपत तथा फरीदाबाद स्थित थर्मल विद्युत केन्द्रों की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 2002-03 (फरवरी के अन्त तक) की कार्यकुशलता के आँकड़े निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	कार्यकुशलता पैरामीटर	1998-99	2002-03 (2/03 के अंत तक)			
			पानीपत में 210 मैगावाट यूनिट 6 को छोड़कर	प्रतिशत सुधार	पानीपत में 210 मैगावाट* यूनिट 6 सहित	प्रतिशत सुधार
1.	प्रतिदिन औसत विद्युत उत्पादन (लाख यूनिट)	96.31	116.50	20.96	162.81	69.05
2.	प्लांट लोड फैक्टर (%)	49.24	59.56	10.32	66.18	16.94
3.	कोयले की खपत (ग्राम/यनिट)	838	809	3.46	772	7.87
4.	तेल की खपत (मिली लीटर/यूनिट)	12.70	3.81	70.00	3.28	74.17
5.	आक्जलरी खपत (%)	12.04	11.16	0.88	10.57	1.47

नोट : पानीपत में 210 मैगावाट की छठी इकाई का कमर्शियल उत्पादन दिनांक 20-9-2001 से आरम्भ हुआ।

- कोयले की प्रति यूनिट खपत 886 ग्राम से 772 ग्राम घटने के कारण 143.89 करोड़ रुपये की संचित बचत हुई।
- तेल की प्रति यूनिट खपत 12.70 मिलीलीटर से 3.28 मिलीलीटर घटने के कारण 142.47 करोड़ रुपये की संचित बचत हुई।
- आक्जलरी खपत 12.04 प्रतिशत से 10.57 प्रतिशत घटने के कारण 14.717 करोड़ यूनिट ऊर्जा की संचित बचत हुई जिसकी कीमत 35.47 करोड़ रुपये है।

Recruitment of Police Constables

*1279. **Shri Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any recruitment of police constables has been made in the Haryana Police during the last three years, if so, the number yearwise thereof ; and

(b) whether proper representation has been given to the persons belonging to the Scheduled Castes, sportsmen and women in the aforesaid recruitments ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हाँ श्रीमान जी, हरियाणा पुलिस में सिपाहियों की भर्ती का वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष		की गई भर्ती	अनुसूचित जाति की भर्ती
2000	पुरुष सिपाही	1917	381
2001	(क) पुरुष सिपाही	1574	314
	(ख) महिला सिपाही	345	69
	(ग) पुरुष सिपाही	602	112
	(घ) पुरुष सिपाही (खिलाड़ी)	114	02

(ख) हां श्रीमान जी। जैसा कि ऊपर दर्शाया है अनुसूचित जातियों, खिलाड़ियों एवं महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया।

Covering of Channel

***1298. Ch. Jai Parkash Barwala :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to cover the Channel carrying drinking water to the water-works of Barwala, district Hisar ; if so, the details thereof, togetherwith the time by which it is likely to be covered ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान् जी। आगामी वित्तीय वर्ष अर्थ 2003-2004 में ढकी हुई चैनल को बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Benefit of Adhoc Services

***1284. Dr. Raghuvir Singh Kadian :** Will the Minister for Finance be pleased to State whether it is a fact that the benefit of one or two increments given earlier to group C and D employees by including their adhoc services is now being withdrawn ; if so, the reasons thereof ?

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : श्रीमान जी, राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 15-3-2002 द्वारा निर्णय लिया है कि 8/18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वृद्धियां) देने के उद्देश्य हेतु गिनी जाने वाली सेवा में तदर्थ सेवा के निम्नांकित जजमैंट्स के दृष्टिगत न गिना जाए :—

I. हरियाणा राज्य व अन्य बनाम हरियाणा वैटरनरी एवं ए०एच०टी०एस० एसोसिएशन व अन्य में दी गई जजमैंट दिनांक 19-9-2000 जो 2000 (8) एस०सी०सी० 4 में रिपोर्ट की हुई है और जिस द्वारा आर०के० सिंगला के केस-रिट याचिका नम्बर 15031/1993 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जजमैंट को निरस्त किया गया है।

II. पंजाब राज्य व अन्य बनाम गुरदीप कुमार उप्पल व अन्य के केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 20-2-2001.

Opening of DIET Centre

***1251. Shri Lila Ram :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a DIET Centre at Village Geong in District Kaithal ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

Construction of Rajlokha Minor in Palwal

***1272. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to complete the construction work of Rajlokha Minor in Palwal, district Faridabad ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed together with the expenditure to be incurred thereon ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) यह योजना 110.00 लाख रुपये की लागत से 30-6-2003 तक पूरी होने की सम्भावना है।

Increase in production of vegetables and fruits

***1293. Shri Ramesh Rana :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that there has been an increase in cultivation of vegetables, fruits and flowers in the State during the period 1990-91 to 2001-2002, if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हां श्रीमान। राज्य में सब्जियों, फलों एवं फूलों की काश्त में वर्ष 1990-91 से 2001-02 तक वृद्धि हुई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

वर्ष 1990-91 से 2001-02 तक सब्जियों, फलों एवं फूलों के क्षेत्र में अत्याधिक वृद्धि हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

(हैक्टेयर में)

फसल	1990-91	2001-02
सब्जियां	55,360	1,50,200
फल	12,640	31,317
फूल	50	3,250

Construction of Buildings in Violation of Building Bye laws

***1244. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that several multi storey buildings in the commercial/residential area in District Gurgaon outside the Municipal Limits have been constructed by violating the building bye-laws ; and

(b) whether any enquiry has been conducted by the Government in this regard, if so the details thereof ?

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) :

(ए) जी नहीं।

(बी) उपरोक्त "ए" के मद्देनज़र कोई जांच नहीं की गई।

Assistance received from Centre under Devirupak Scheme

***1311. Shri Hamid Hussain :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether the State Government has received any assistance from the Government of India under Devirupak Scheme ; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० मुनी लाल रंगा) : जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Upgradation of Schools

130. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the district-wise number of schools upgraded in the State during the year 2001-2002 ; and

(b) whether any criteria for the upgradation of schools has been laid down ; if so, the details thereof ?

राज्य शिक्षा मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह) :

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(क) वर्ष 2001-2002 में जिलावार स्तरोन्नत विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	जिला	प्राथमिक से मिडल	मिडल से उच्च	उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक	कुल विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	फतेहाबाद	2	—	—	2
2.	गुड़गांव	4	3	2	9

1	2	3	4	5	6
3.	हिसार	7	1	2	10
4.	जीन्द	1	—	—	1
5.	करनाल	6	—	1	7
6.	कैथल	2	4	—	6
7.	नारनौल	5	—	—	5
8.	पानीपत	5	2	—	7
9.	रोहतक	2	—	1	3
10.	सिरसा	—	2	5	7
11.	अम्बाला	—	—	1	1
12.	रिवाड़ी	2	6	1	9
13.	भिवानी	10	5	12	27
	कुल :	46	23	25	94

(ख) हां श्रीमान, स्तरोन्नत विद्यालयों को निर्धारित मानदण्ड का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	आवश्यकता	प्राथमिक से मिडल	मिडल से उच्च	उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक
1	2	3	4	5
1.	कक्षा	8	10	14 छठी से बारहवीं
2.	प्राचार्य कक्ष	—	—	1
3.	कार्यालय कक्ष	1	1	1
4.	स्टोर कक्ष	1	1	1
5.	विज्ञान प्रयोगशाला	—	1	3
6.	गृह विज्ञान कक्ष	—	1 केवल कन्या	1
7.	पुस्तकालय कक्ष	—	1	1
8.	स्टाफ कक्ष	—	1	1
9.	लिपिक कक्ष	—	1	1
10.	संगीत कक्ष	—	—	1

[चौ० बहादुर सिंह]

1	2	3	4	5
11.	शौचालय	2	2	4
12.	जमीन	2	2	4
13.	छात्र संख्या	150 (कक्षा 1 से 5)	100 (कक्षा 6-8)	100 (कक्षा 9-10)
14.	चारदीवारी	अवश्य	अवश्य	अवश्य

Share in Agra Canal

131. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the cusecs of water the State of Haryana is receiving per annum from Agra Canal in district Faridabad ; and

(b) whether it is a fact that the share of water in Agra Canal has been reduced as per new agreement reached between the Governments of Uttar Pradesh and Haryana ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हरियाणा राज्य आगरा नहर से जिला फरीदाबाद में 96151 क्यूसिक दिन पानी प्रति वर्ष (3 वर्षों की औसत के आधार पर) प्राप्त कर रहा है।

(ख) हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सरकारों के मध्य आगरा नहर के पानी के हिस्से पर कोई अलग समझौता नहीं है।

Amount Spent on Purchase of Medicines

132. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) the total amount spent on the purchase of medicines by the Health Department during the year 2001-2002 ; and

(b) the details of the medicines supplied to the Civil Hospital, Palwal and Badshah Khan Hospital, Faridabad during the period referred to in part "a" above ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डा० मुनी लाल रंगा) :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान औषधियों (मैटीरियल एण्ड सप्लाईज) की खरीद पर कुल 6,56,84,880/- रुपये खर्च हुआ।

(ख) वर्ष 2001-2002 में सिविल हस्पताल, पलवल तथा बादशाह खान हस्पताल, फरीदाबाद को औषधियों की आपूर्ति का विवरण क्रमश: अनुबन्ध क और ख पर सलंग्न है। इस अवधि के दौरान 2,35,955/ रुपये की औषधियां सिविल हस्पताल, पलवल को तथा 16,13,411/- रुपये की औषधियां बादशाह खान हस्पताल, फरीदाबाद को सप्लाई की गई थी।

अनुबन्ध क

List of Medicine of General Hospital, Palwal (Faridabad) for the year 2001 to 2002

Sr. No.	Name of Medicines	Quantity	Aproximate amount
1	2	3	4
1.	Tab Cotrimoxajole SS	20000	10000
2.	Tab Cotrimoxajole DS	6000	6000
3.	Tab Chlorphanerumine Meleate	30000	500
4.	Paracetamole	21000	2500
5.	Tab Ibumol	5000	1350
6.	Tab Multivitamino	10000	2400
7.	Tab Dependal M	3000	1500
8.	Tab Astemijole	2000	500
9.	Tab Albandajole	1800	1800
10.	Tab Colsprin	3000	300
11.	Tab Diclomine DCL+ Erthylomrytine	2500	4000
12.	Tab Disprin	10000	1500
13.	Tab Erythromycine	2500	3500
14.	Tab Monosorbitrate	1500	1500
15.	Tab Metronidajole 400 mg.	4000	800
16.	Tab Matelopromide	1000	80
17.	Tab Vir E	1200	1200
18.	Tab Ethamaylate	500	850
19.	Tab Disvol	2000	480
20.	Tab Maxyna Plus	1000	350
21.	Lurpcoe	3000	300
22.	Tab Defen MRK	1500	1200
23.	Tab Ero-Salbetol	4600	2050
24.	Tab Ciprofloxacin	4000	4400
25.	Tab Nemuailid DT	1000	200
26.	Purewell 0.9	20000	1100
27.	Tab Glipijmo	4000	4000
28.	Tab Salbutamole 4mg.	3000	230
29.	Cap Amoxyoiling	3100	4650
30.	Cap Doxycycline	3000	1450
31.	Cap Omprajole	1000	480
32.	Cap Cephalaxine	1000	2000
33.	Cap Cloxiciline	500	400

[डा० मुनी लाल रंगा]

1	2	3		4
34.	Cap Carbok	400		400
35.	I/v Dectons 5% 500 ml	1260		15220
36.	I/v DNS 500 ml	660		7920
37.	I/v Normal Salmic 500 ml	300		3600
38.	I/v Ringer Lactate 500 ml	405		4860
39.	Inj Colajokin	270		6000
40.	Inj Avil	300		600
41.	Inj Hepatitis B 10 ml	112		64000
42.	Inj Aurepine	100		70
43.	Inj Lignocain	220		900
44.	Inj Pan	260		320
45.	Inj Ciprofloxacine	200		1600
46.	Inj Procain Panciline	100		335
47.	Inj Methyl krgomerine	200		300
48.	Syp Albandazole	250		1000
49.	Syp Flood	150		1500
50.	Syp Furoxone	100		700
51.	Syp Diavol	190		3040
52.	Syp Paracetarmole	50		360
53.	I/v Sots	225		1350
54.	Disposable Syrings	2600		3600
55.	Gloves	700	Pairs	5000
56.	Bandage 10 CMX 4M	200	dojan	7500
57.	Bandage 15 CMX 5M	200	dojan	14100
58.	Cotton 500G	120	Rolls	3800
59.	Gauge Cloth	150	Than	10000
60.	Bleaching Power	2	Bags	420
61.	ORS	200		2800
62.	Povidon Iodine Oint. 250 G.	20	Jar	500
63.	Povidon Iodine Solution 500 ml.	20	Bottel	800
64.	Sulphacctamide Cye drop 20%	100		500
65.	Cortula M eye drops	400	vls	4000
66.	Isabgol Busk	80	Pkt.	2720
67.	Dexona eye drops	200	vls	1280
68.	Norfloxacin eye drops	100	vls	350
69.	2% Alkaline Glotra dohyde	4x5	ltr.	1320
	Total			Rs. 235955.00

अनुबन्ध ख

List of Medicine of B.K. Hospital, Faridabad for the year 2001 to 2002

Sr. No.	Name of Medicines	Quantity	Aproximate amount
1	2	3	4
1.	Cap. Amoxycyllin 250 mg	5000	5100
2.	Cap. Amoxycyllin 500 mg	5000	10200
3.	Tab Albandozal	4800	5000
4.	Cap Clozacillin 250 M	3000	1100
5.	Tab Cotmop SS.	10000	7000
6.	Tab Cipofloaxacline 250 mg	20000	11150
7.	Tab Ciprfloaxacline 250 mg	10000	10690
8.	Cap. Doxycycline	20000 Tab.	21000
9.	Tab Erothromycin 250mg	10000	28600
10.	Tab Ibrumol 250 mg	40000	10800
11.	Tab Mono Carb	5000	5000
12.	Tab. PCM	96000	25000
13.	Tab Tirudazole	2000	4600
14.	Nifidiplenc	10000	8700
15.	Cap cephalaxil 500 mg	6000	7660
16.	Tab Glupizaced	3000	200
17.	Tab Spratiozacline 200 mg	23000	82800
18.	Tab Falcigo	500	8500
19.	Tab Spasmiden	8000	11750
20.	Tab stamizine 10mg	2450	1250
21.	Tab defam mark	21350	17200
22.	Tab Lorozipan 5 mg	26500	4637
23.	Cap Fleminil	24000	19648
24.	Tab Stonzol	2200	2500
25.	Tab maxyna plus	23000	8050
26.	Tab Nimoslile DT	100000	20000
27.	Tab Roxithanoumyem	6000	35000

[डा० मुनी लाल रंगा]

1	2	3	4
28.	Inj Apropline Recipliots	500	600
29.	Inj Benzyl Peniline	500	2500
30.	Inj Dextris 5%	2205	26000
31.	Inj DNS	2300	27000
32.	Inj Normal Faline	380	4500
33.	Inj Procanl Pencillin 4 lacs	1500	5000
34.	Inj. Promethazine	500	500
35.	Inj paracitamol	1000	1240
36.	Inj Ringer lactate	2100	24000
37.	Inj Xylocanl 2%	400	1600
38.	Inj Fortwine	1000	3800
39.	Inj. Hepatist B	312	260000
40.	Inj Cloxcallin	1000	6000
41.	Inj ergomotrin	210	3450
42.	Inj. Manitol I/V	1160	16590
43.	Inj ciproflaxals I/V	1400	11000
44.	Inj Anti makevenon	40	17660
45.	Syp Cephlaxai	423	3000
46.	Formalin sol	240	4992
47.	POP Powder	449 kg	9969
48.	Sutramicine Eye drop	250	1100
49.	Uxa sound jell	100	4200
50.	Zytee lotion	375	8000
51.	Syp. Erthromycine	100	1100
52.	Povidon Sol	184 B	7200
53.	Povidon oint	250 Jar	6360
54.	Meftal Drop	1100	10300
55.	Syp Moftal P	1025	12300
56.	Syp Moftal P	1025	12300
57.	Dexnos Eye drop	525	2340
58.	Syp dompandom	50A	675
59.	Corto Quat Point	2500	20000

1	2	3		4
60.	Syp PCM	1600		11600
61.	Isabgol	727		24500
62.	Syp Ampicilin + cloxzcilline	150		1200
63.	Syp Cadiphlate	360		10575
64.	Syp Ibrufan	100		3500
65.	Micno zel oint	150		5850
66.	Lysol	106		9950
67.	Syp Cetrazine 100 ml	2000		40000
68.	Occucel Eye drop	500		3400
69.	Monogesic ml	1100		8800
70.	Bandage 15x 5ml	460		32423
71.	Bandage 10x4 ml	800		30000
72.	B.P. Blade	6000		8860
73.	Vain flow	418		10000
74.	Cotton	840	Pkt.	26250
75.	Cauge Than	430		26660
76.	I.V. Set	5300		20000
77.	Vain flow 20-22	462		10000
78.	Disposable Syp 5 cc	9200		18400
79.	Disposable Needle	100	box	9950
80.	Adhivai Plaster	200		9800
81.	Inj A.R.V.	2400		384000
82.	X-Ray Films 12x15	14	Pkt.	15512
83.	X-Ray Films 10x12	13	Pkt.	9610
84.	X-Ray Films 8x105	13	Pkt.	6500
	Total			Rs. 16,13,411.00

Sewerage Treatment Plant in Palwal

133. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the amount spent on the construction of the Sewerage Treatment Plant and the Sewerage work being carried out in Palwal, district Faridabad under Yamuna Action Plan during the year 2001-2002 ; and

(b) the time by which the aforesaid works are likely to be completed ?

मुख्यमन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) पलवल जिला फरीदाबाद में सीवरेज एवं सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट पर यमुना कार्य परियोजना के अधीन वर्ष 2001-2002 में किये गये खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	किये गये कार्य	खर्चा रुपये लाखो में
	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन सीवर	2.80
	सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट	59.30
	सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के लिये ली गई जमीन की बढ़ी हुई लागत	592.74
	कुल :	654.84

(ख) उपरोक्त कार्य मार्च, 2004 तक पूर्ण होने की आशा है।

Number of Schools Running with the Aid of Govt. Grant

145. Shri Krishan Pal : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the names and places of the Schools in Faridabad district which are running with the Govt. Grant;

(b) the year wise total amount of grant being given to the aforesaid schools which are running with the Govt. grant;

(c) the terms and conditions to give the grant to the schools referred to in part (a) above;

(d) whether all the terms and conditions are being fulfilled by all these schools ; and

(e) if the reply in part (d) be in negative, the action taken by the Government against the said schools ?

राज्य शिक्षा मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह) : विवरण निम्न रूप से विधानसभा पटल पर प्रस्तुत है :—

विवरण

(क) जिला फरीदाबाद में निम्नलिखित विद्यालयों को अनुदान सहायता दी जाती है।

1. विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (प्राईमरी विंग सहित) एन०आई०टी० नं० 2 फरीदाबाद ।
2. विद्या मन्दिर उच्च विद्यालय सैक्टर-15 (प्राईमरी विंग सहित) फरीदाबाद।
3. अग्रवाल उच्च विद्यालय, बल्लभगढ़
4. सरस्वती उच्च विद्यालय, पलवल (प्राईमरी विंग सहित)

5. डी०जी० खान वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पलवल
6. के०एल० मेहता दयानन्द पब्लिक स्कूल ब्लाक-5 ई०, एन०आई०टी०, फरीदाबाद
7. के०एल० मेहता दयानन्द पब्लिक स्कूल ब्लाक-1 ई०, एन०आई०टी०, फरीदाबाद
8. गुरु नानक उच्च विद्यालय, जवाहर कालोनी, फरीदाबाद
9. महादेव उच्च विद्यालय, जवाहर कलोनी, फरीदाबाद

(ख) उपरोक्त स्कूलों को वर्ष अनुसार (2002-2003) कुल राशि का ब्यौरा निम्न है :—

	कोठारी	अनुरक्षण	कुल राशि
उच्च /वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	82,52,783/-	48,40,883/-	1,30,93,666/-
प्राईमरी	19,56,000/-	9,53,000/-	29,12,000/-
	1,02,08,783/-	57,96,883/-	1,60,05,666/-

(ग) शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

1. अध्यापकों को 1-12-67 से सरकारी स्कूलों के समान वेतन देय है।
2. अध्यापकों को वार्षिक वृद्धि रैगुलर तौर पर दी जाती है।
3. मंहगाई भत्ता तथा अन्य लाभ भी विभागीय हिदायतों के अनुसार देय होता है।
4. अध्यापकों को वेतन की अदायगी क्रास चेक द्वारा की जानी होती है।
5. विद्यालय में ली जाने वाली फीस तथा अन्य छूट शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ली जानी होती है।
6. प्रबन्धक, समिति, विद्यालय का स्टाफ तथा विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से अनुशासन रखना होता है तथा वह विद्यार्थी किसी प्रकार की साम्प्रदायिक तथा द्वेष विद्रोह, आन्दोलन में भाग नहीं ले सकते तथा उनको पूर्ण रूप से अनुशासन रखना होता है एवं उनकी साख अच्छी होनी चाहिये।
7. स्कूल के अधिकारियों को शिक्षा विभाग हरियाणा के एक्ट 1995 तथा उसमें संदर्भित नियमों की सख्ती से पालना करनी होती है।
8. यदि कोई राशि स्कूल प्रबन्धकों को देय राशि से अधिक प्राप्त हो जाती है और विभाग द्वारा नोटिस में आ जाती है तो वह राशि प्रबन्धक कमेटी को वापस करनी होगी।
9. प्रबन्धक कमेटी तथा कर्मधारियों के मध्य किसी भी विवाद की हालात में शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा तथा स्कूल अधिकारी इसे मानने को बाध्य होगें।
10. दी जाने वाली सहायता की राशि का आडिट करने का अधिकारी होगा। जिसकी उपयुक्त पूर्व सूचना दी जायेगी।

[चौ० बहादुर सिंह]

11. अनुदान सहायता देने से पूर्व प्रबन्धक कमेटी को विभाग से अनुमोदित करवाना होता है।

(घ) हाँ, रिकार्ड के अनुसार आज तक सभी शर्तें पूर्ण करते हैं

(ङ) उपरोक्त उत्तर के (पार्ट डी) प्रश्न 145 के अनुसार किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

Amount of Interest to be Paid by Government on Loans

147. Shri Ram Kishan Fauji : Will the Minister for Finance be pleased to state the amount of interest which is to be given on the amount of various loans taken by the Haryana Government as on 28-2-2003 together with the percentage of revenue is to be given as interest ?

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) : 28-2-2003 को हरियाणा सरकार द्वारा लिये गये विभिन्न ऋणों की राशि पर ब्याज की 1539.61 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है जो कि राजस्व प्राप्तियों का 17.53 प्रतिशत है।

Guarantee Given by the Government

148. Shri Ram Kishan Fauji : Will the Minister for Finance be pleased to state the amount of loan taken by each Public Sector Undertaking of the Haryana Government as on 31-01-2003 the guarantee of which has been taken by the State Government ?

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) : राज्य के सार्वजनिक उद्यमों द्वारा राज्य सरकार की गारण्टी के विरुद्ध लिए गए ऋण में से 31-1-2003 तक 10446.86 करोड़ रुपये की राशि देय है, जिसका विवरण निम्न है :—

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वर्गीकरण		(राशि करोड़ों में)
(क)	सांविधिक निगम तथा बोर्ड	865.55
(ख)	सरकारी कम्पनियां	7991.98
(ग)	सहकारी संस्थाएं	1573.19
(घ)	नगरपालिकाएं, निगम टाऊनशिप और अन्य स्थानीय निकाय	16.14
	जोड (क-घ)	10446.86

Loan Against H.S.A.M.B.

149. Shri Ram Kishan Fauji : Will the Minister for Finance be pleased to state the amount of loan of Haryana State Agricultural Marketing Board outstanding against the Haryana Government as on 31-3-1999 and 31-01-2003 together with the purpose for which it was obtained and the place where it was utilized ?

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) : नहीं, जी।

Liability towards NABARD and L.I.C.

150. Shri Ram Kishan Fauji : Will the Minister for Finance be pleased to state the amount of liability of Haryana Government towards NABARD and L.I.C. as on 31-3-1999 and 31-01-2003 togetherwith the rate of interest thereon.

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) :

(क) हरियाणा सरकार द्वारा नाबार्ड की ओर देनदारी :

31-3-1999 तक हरियाणा सरकर की देनदारी 118.86 करोड़ रुपये थी तथा 31-01-2003 को हरियाणा सरकार की देनदारी 358.54 करोड़ थी। नाबार्ड के ऋणों पर ब्याज की दरें पृथक-2 रही हैं अर्थात् ट्रैंच 1-2 जो 1998-99 के समय में थे, उस समय 12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज था। इस समय ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत वार्षिक है।

(ख) हरियाणा सरकार द्वारा एल०आई०सी० की ओर देनदारी :

31.03.1999 तक हरियाणा सरकार की देनदारी 48.245 करोड़ रुपये तथा 31.01.2003 को हरियाणा सरकार की देनदारी घटकर 38.30 करोड़ रुपये रह गई। इन ऋणों पर ब्याज की दरें 8 प्रतिशत से 13 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

Construction of Bridge on River

152. Shri Jasbir Mallour : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on river Tangri in between the villages of Durana and Majri in district Ambala ; if so, the time by which it is likely to be constucted ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान् जी, यह पुल दिसम्बर, 2004 तक पूर्ण होने की संभावना है।

Setting up of 66 KV Power Station in Village Sonda

153. Shri Jasbir Mallour : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up 66 KV sub-station at village Sonda, district Ambala ; if so, the time by which it is likely to be set up ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान, गांव सोन्दा, जिला - अम्बाला में 442 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक नया 66 के०वी० उपकेन्द्र निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह कार्य वर्ष 2004-2005 में पूर्ण होना प्रस्तावित है।

Upgradation of 66 KV Sub-station of Chormastpur

154. Shri Jasbir Mallour : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 66 K.V. Sub-station of village Chormastpur district Ambala into 110 K.V. Sub-station ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : नहीं श्रीमान, आगामी वित्त वर्ष में इस उपकेन्द्र की क्षमता 12 एमवीए से बढ़ाकर 16 एमवीए करने की योजना बनाई गई है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 1996 में चौधरी बंसी लाल जी ने शराबबंदी का नारा देकर सत्ता हासिल की थी। शराबबंदी की जिस तरह से धज्जियां उनके मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने और उनके अपने आदमियों ने उड़ाई और किस तरह से शराबबंदी फेल हुई यह सभी को मालूम है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों, हरियाणा की महिलाओं और पुरुषों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किए गए। कुल मिला कर एक लाख 15 हजार लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये और चालीस लोगों को जहरीली शराब पीकर मरने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक लोक हित का प्रश्न है। (विघ्न) तीन हजार करोड़ रुपये का हरियाणा प्रदेश का लौस हुआ है। चौधरी बंसी लाल जी से जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सत्ता छीनी उससे पहले हम विपक्ष में बैठा करते थे। जब चौधरी बंसी लाल जी ने शराबबन्दी लागू की थी तो हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शराबबंदी की हिमायत की थी और पूरे सदन ने शराबबंदी को लागू करने का निर्णय लिया था। स्पीकर सर, शराबबंदी लागू करने और हटाने का यह एक अहम् मुद्दा है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आने के बाद शराबबंदी लागू करने और हटाने के बारे में जांच करने के लिए चहल आयोग का गठन किया गया था। उसके गठन के बाद चहल आयोग के खिलाफ माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिट डाली गई तथा माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अब हमने अखबारों में यह खबर पढ़ी है कि कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया है और अखबारों के माध्यम से पता चला है कि चहल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस चहल आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए कोई सरकार की तरफ से कार्यवाही चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय जवाब देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मानित सदस्य ने एक विशेष प्रश्न के आधार पर एक अहम् मुद्दा उजागर करने का प्रयास किया है। यह मुद्दा पूरे प्रदेश के आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है। पिछली सरकारों के समय के इस सदन में कई सदस्य बैठे हुए हैं मैं उनके नाम नहीं लूंगा। उस वक्त चौधरी भजन लाल जी भी इस सदन में थे। सदन में विपक्ष के पूरे विरोध के बावजूद उस वक्त के मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने जल्दबाजी में शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया और अध्यक्ष महोदय, हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, हम आर्य समाज कल्चर के लोग हैं। शराब एक बुराई है, एक अभिशाप है हम भी चाहते थे कि शराबबंदी हो लेकिन उस समय हमने एक शंका जाहिर की थी कि यदि सरकार ईमानदारी से शराबबंदी करने के पक्षधर है तो इससे प्रदेश के लोगों का बहुत फायदा होगा और यदि इसके पीछे सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी तो इसके परिणाम गलत निकलेंगे और ऐसा ही हुआ। उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर मैंने आंकड़ों के साथ यह वर्णित किया था कि अमेरिका में शराबबंदी की गई थी और उसके

दुष्परिणाम निकले। गुजरात में शराबबंदी की गई वहां पर परिणाम यह निकला कि गुजरात में शराब माफिया खड़ा हो गया है और आज देश के लोगों को परेशान करता है। अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते थे कि शराबबंदी हो लेकिन ठीक नीयत से हो। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार ने शराबबंदी लागू की लेकिन हमने जो शंका जाहिर की थी यह शत् प्रतिशत सही साबित हुई। यहां तक कि डी०आई०जी० (सी०आई०डी०) की रिपोर्ट में भी यह माना गया कि शराब की तस्करी हो रही है और सत्ता पक्ष की मिली भगत से हो रही है। यह शिकायत कई एस०पीज० की तरफ से भी आई थी। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार के मुखिया ने आरोपों की पड़ताल करने के लिए एक संस्था को जिम्मेवारी सौंपी थी। जब उस संस्था की रिपोर्ट आई तो वह सदन में प्रस्तुत नहीं की गई। जब शराबबंदी लागू की गई थी तब पूरे सदन से पूछ कर लागू की गई थी लेकिन जब शराबबंदी हटाई गई तब न सदन से पूछा गया और न अपने विधायकों से पूछा गया। मात्र सरकार के मुखिया ने अपने बेटे के कहने पर शराबबंदी को लिफ्ट कर लिया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब नई सरकार आई और जो शंका जाहिर की थी उसके आधार पर जो उस वक्त की सरकार ने इन्क्वायरी करवाई थी ताकि पूरे प्रदेश के लोगों को जानकारी मिल सके कि शराबबंदी के पीछे क्या सोच थी जिसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपये के रैवेन्यू का नुक्सान हुआ तथा इस सब के लिए दोषी कौन है। यह सब जानने के लिए हमने एक चहल आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस जी०एस० चहल हैं। इस आयोग का गठन केवल मात्र यह जानकारी हासिल करने के लिए किया गया कि शराबबंदी लगाने व हटाने के पीछे सिलसिला क्या था, सोच व मंशा क्या थी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने चहल आयोग को जांच में सहयोग देने की बजाय उसकी कार्यवाही में कदम-कदम पर बाधाएं डालने का काम किया और गवाहों को विन ओवर करने का भी प्रयास किया और आयोग के खिलाफ कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने किस आधार पर उसको निरस्त किया मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता और जब सरकार अपील में गई तो डबल बैंच ने हमारी बात मान ली, मुझे इस बात की खुशी है। अध्यक्ष महोदय, हम किसी बात को छुपाना नहीं चाहते, हम जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं। हमारी सरकार ने दुलिना के मामले में लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए एक कमीशनर से इन्क्वायरी करवाई और ज्यों ही कमीशनर की रिपोर्ट आई वह एक क्षण की देरी किए बगैर सदन में प्रस्तुत की गई। इसी तरह जहां तक जस्टिस चहल कमीशन की बात है उसे हम लीगली एग्जामिन करवा रहे हैं। उसे लीगली एग्जामिन करवाकर हम सदन के पटल पर रखेंगे और उस पर सभी सम्मानित सदस्यों को मिलकर चर्चा करने के लिए पूरा अवसर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, प्लीज, आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये।

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री राम किशन फौजी : अगर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे तो मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के माननीय सदस्य श्री राम किशन फौजी सदन से वाक आउट कर गये।)

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, हमने एस०वाई०एल० कैनाल की कम्पलीशन के बारे में एडजर्नमैंट मोशन दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपका एडजर्नमैंट मोशन सरकार के पास कमैंट्स के लिए भेज दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो कालिंग अटैंशन मोशन और एडजर्नमैंट मोशन मैंने दिये थे उनके बारे में भी तो बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एडजर्नमैंट मोशन और कालिंग अटैंशन मोशन के नोटिस दिये थे उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपका एक एडजर्नमैंट मोशन जो सूखे से ग्रस्त किसानों के बारे में था, वह सरकार के पास कमैंट्स के लिए भेज दिया है। दूसरा आपका जो एडजर्नमैंट मोशन सिंचाई के लिए पानी के बराबर बंटवारे के बारे में था वह डिसअलाउ कर दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, मैंने एस०वाई०एल० कैनाल की कम्पलीशन के बारे में जो एडजर्नमैंट मोशन दिया था उसका क्या हुआ। . . . . (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिये। मैं सभी सदस्यों के जो मोशंज आए हैं, उनका फेट बता देता हूं। आप कृपया शांति से बैठ कर सुनें। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य 16 विधायकों का एस०वाई०एल० कैनाल की कन्स्ट्रक्शन के बारे में जो एडजर्नमैंट मोशन आया था उसे गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेज दिया गया है। . . . . (शोर एवं विघ्न)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : सर, मैंने भी एक सूखे से संबंधित एडजर्नमैंट मोशन दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इस बारे मैं पहले ही कैप्टन अजय सिंह जी को बता चुका हूं कि वह गवर्नमैंट के पास कमैंटस के लिए भेजा गया है। उस पर आपके भी साइन थे। एक एडजर्नमैंट मोशन इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर के बारे में कैप्टन अजय सिंह और अन्य 7 विधायकों की तरफ से आया था, इस मोशन को डिसअलाउ कर दिया गया है। कर्ण सिंह दलाल ने भी नोन पेमेंट आफ शुगरकेन प्राईस टू दा फारमर्ज बाई कोपरेटिव एंड प्राईवेट शुगर मिल्ज के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन का नोटिस दिया था वह डिसअलाउ कर दिया गया है। एक अन्य कालिंग अटैंशन मोशन श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा नोन डिस्ट्रीब्यूशन आफ ड्राउट रिलीफ अमाउंट के बारे में दिया गया था वह भी गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेज दिया गया है। इसी प्रकार से

श्री कर्ण सिंह दलाल तथा श्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा डैमोलीशन आफ हाउसिज़ एंड शाप्स के बारे में काल अटैंशन मोशन आया था वह गवर्नमेंट के पास कमैंटस के लिए भेज दिया गया है। इसी प्रकार से श्री कृष्णपाल गुर्जर के एक और कालिंग अटैंशन मोशन रिगार्डिंग डिफिक्लटीज बींग फेस्ड बाई दी पीपल ड्यू टू कोलैप्स ऑफ पाला ब्रीज ऑफ आगरा कैनाल, आया था वह डिस अलाउ कर दिया गया है। श्री कर्ण सिंह दलाल तथा श्री कृष्णपाल गुर्जर का एक और कालिंग अटैंशन मोशन जो फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैंट द्वारा रिलिजिंग ऑफ टैण्डर ऑफ लोडिंग एण्ड अनलोडिंग आन हायर रेट्स के बार में था वह भी डिसअलाउ कर दिया गया है। मैंने सभी के एडजर्नमेंट मोशंज और कालिंग अटैंशन मोशन के बारे में बता दिया है, कृपया आप सब शांति से बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में प्राईवेट मैम्बर के तौर पर एक बिल भेजा है। न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में एक्सीडैंट्स होते हैं और उन एक्सीडैंटस से बहुत सी मौतें हो जाती है। जब एक्सीडैंट से किसी की मौत होती है तो चालक की जमानत हो जाती है क्योंकि यह बेलेबल अर्फेस है जबकि इसे नॉन बेलेबल अर्फेस माना जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह अण्डर कंसीड्रेशन है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, नॉन ऑफिशियल डे के माध्यम से सदस्य अपनी अपनी बात कह सकते हैं। इस दिन शिक्षा, इरीगेशन या पब्लिक हैल्थ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्य अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके बारे में आपने क्या फैसला किया है ?

श्री अध्यक्ष : गवर्नर साहब के एड्रैस पर स्पीचिज शुरू हो जाएंगी और अपनी बात कहने का सबको मौका मिलेगा। आपका प्राईवेट मैम्बर बिल डिकलाईन कर दिया है।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for suspension of Rule 30.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government Business on Thursday, the 6th March, 2003.

Sir, I also beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 6th March, 2003.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government Business on Thursday, the 6th March, 2003.

[Mr. Speaker]

And

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 6th March, 2003.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, नॉन आफिशियल डे पर प्राईवेट मैम्बर्ज का बात करने का पूरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, क्या आपने नॉन आफिशियल डे के लिए कुछ दिया हुआ है ? अब दलाल साहब बोलेंगे, आप बैठ जाएं (विघ्न) आप कैसे बोलेंगे ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : मैं आपकी इजाजत से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपको कोई इजाजत नहीं है इसलिए आप अभी बैठ जाएं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, अभी आपने मुझे इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने देखा तो आप खड़े थे। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी, आप तैयार हो कर आएं और कुछ लिखना पढ़ना भी सीखें (विघ्न) दलाल साहब, क्या ये आप के बिहाफ पर बोल रहे हैं ? यदि ये बोलेंगे तो आपको बोलने का समय नहीं मिलेगा। (विघ्न) भजन लाल जी आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न) नॉन आफिशियल डे पर ऐसा कोई भी बिजनैस मेरे सामने नहीं है जिसको मैं ट्रांजैक्ट करूं। जब कोई बिजनैस ही नहीं है तो क्या मैं दूसरा बिजनैस भी न करवाऊं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बिल आपको दिया है वह जनहित का मुद्दा है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को सरकार एडॉप्ट कर ले (विघ्न) मेरा बिल यह है कि जो ड्राईवर्ज एक्सीडैंटस करते हैं और उससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और बाद में ड्राईवर की जमानत हो जाती है हम चाहते हैं उसे नॉन बेलेबल ऑफैंस मानना चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूं कि यह जनहित की बात है। मेरे इस प्राईवेट बिल को लाने की कोई जरूरत नहीं है अगर सरकार खुद इस बिल को ले आए। आज शराब पी कर पैसे वाले लोग, धनी लोग पैसे की ताकत में गाड़ियां मनमस्त तरीके से चलाते हैं, और एक्सीडैंट करते हैं। पूरे हिन्दुस्तान में लोगों ने इस बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं और जनहित याचिकाएं डाली हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हरियाणा प्रदेश पहल करके देश के लोगों को एक रास्ता दिखा सकता है। अगर ड्राईवर से कोई मौत होगी तो ड्राईवर की जमानत नहीं होनी चाहिए और यह नॉन बेलेबल होना चाहिए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, जैसे उन्होंने कहा है कि इसमें अमैंडमैंट करके इसे नॉन बेलेबल ऑफैंस माना जाए। इससे पहले स्पीकर सर, सारा प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है और इसमें लॉ डिपार्टमैंट का भी ताल्लुक है इसलिए एल०आर० से राय ले कर ही अमैंडमैंट की जा सकती है लेकिन एल०आर० ने इसको डिसअप्रूव कर दिया है। एल०आर० की राय के बाद यह डिसअप्रूव कर दिया गया है। आपके पास सरकार की तरफ से जवाब भी आ गया है। इसके बाद प्राईवेट मैम्बर का कोई मैटर यहां पर नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं चौधरी भजन लाल जी ने और हुड्डा साहब ने भी कहा है और दलाल साहब भी कह रहे हैं कि तीन

साल हो गए हैं किसी भी नॉन आफिशियल डे को प्राईवेट मैम्बर बिल लाकर यूटिलाईज नहीं किया गया है यह हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ा ही अनफोर्चुनेट है। इस मामले में ओपोजीशन नॉन सीरियस है उसने कभी भी ऐसा बिल नहीं दिया जो पब्लिक इंट्रस्ट में हो। प्राईवेट मैम्बर बिल इनटाईम दिये जाते हैं और उनके लिए टाईम भी निश्चित होता है। अगर मोर दैन वन बिल हों तो उसमें लॉटस भी डालते हैं। अनफोर्चुनेटली किसी मैम्बर ने कोई प्राईवेट मैम्बर बिल नहीं दिया है और बाद में उस डे को नॉन ऑफिशियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार की दरियादिली है कि आपसे रिक्वैस्ट करके नॉन आफिशियल डे को आफिशियल डे में कन्वर्ट करवाते हैं ताकि मैम्बर्ज को अपनी अपनी बात कहने के लिए मौका मिल जाए। जब कोई नॉन आफिशियल काम ही नहीं था इसलिए नॉन आफिशियल डे को आफिशियल डे में कन्वर्ट किया गया है। इनको कुछ सीखना चाहिए, अपनी क्लास लगवानी चाहिए। अगर ये क्लास लगाएं तो कुछ सीखेंगे ही। इनकी तरफ से कोई नॉन आफिशियल-डे काम नहीं आया है इससे यह पता चलता है कि ये पब्लिक के बारे में कितने सीरियस हैं और ये यहां पर कितना कन्ट्रीब्यूट करते हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : In view of the reply from the Government, leave to introduce the Bill is declined.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर सरकार इस बिल को मेरे नाम से नहीं लाना चाहती है तो ये इस बिल को अपनी तरफ से ले आएं। आप खुद ही देखें कि आज देश में कितने लोग शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : यह सब कुछ पूरे देश में चल रहा है सिर्फ हमारे प्रदेश में ही नहीं चल रहा है। इसको हम अकेले इम्पलीमैंट करने वाले कौन होते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यूनियन गवर्नमैंट का लॉ है। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

Mr. Speaker : Question is—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government Business on Thursday, the 6th March, 2003.
>
> And
>
> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 6th March, 2003.

The motion was carried.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2003-2004 be suspended.

Sir, I also beg to move—

That this House Authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2003-2004, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2003-2004 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2003-2004, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2003-2004 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2003-2004, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, इस पर मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप इस पर हमारा सुझाव तो सुन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप कृपया बैठें। जब आपको बोलने का मौका मिलेगा उस समय आप अपनी बात कह लेना।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आपने अभी जो कमेटीज के गठन के बारे में कहा है उसके बारे में हम सुझाव तो दे सकते हैं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, अब तो वह मामला खत्म हो लिया है। जिस स्टेज पर इनको बोलना चाहिए था उस स्टेज पर तो ये बोले नहीं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब गवर्नरज़ ऐड्रैस पर चर्चा होगी। श्री उदयभान जी अपना मोशन मूव करें।

श्री उदयभान (हसनपुर-अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

महामहिम राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए—

"कि इस सदन में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 6 मार्च, 2003 को इस सदन में देने की कृपा की है।"

अध्यक्ष महोदय, कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्ताव हाउस में रखा और उसमें जो सरकार के सराहनीय कार्यों का लेखा-जोखा रखा उसके लिए मैं इस सदन के नेता

[श्री उदयभान]

माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इतने अल्पकाल में बहुत ही छोटे मंत्रिमंडल के साथ जो इतने सराहनीय कार्य किये हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, अब से लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले जिस समय हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी उस समय पूरे प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता छायी हुई थी राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी कानून-व्यवस्था पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी और शराब माफिया पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा पनप चुका था। कानून एवं व्यवस्था एकदम बुरी हालत में थी। ऐसी परिस्थितियों में जो विरासत माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला को सरकार में मिली उसको उन्होंने बड़ी बखूबी से संभाला। चौधरी देवीलाल, जन नायक जोकि हमारे आदर्श हैं हमारे मार्गदर्शक हैं पथ प्रदर्शक हैं उनके इस नारे को कि सत्ता सुख भोग का साधन नहीं बल्कि जन मानस की सेवा का माध्यम है, को उन्होंने चरितार्थ किया है। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है उनके इस कथन को इस सरकार ने चरितार्थ करते हुए प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में चाहे शिक्षा का हो, चाहे सड़क परिवहन का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे जन स्वास्थ्य का हो या चाहे दूसरे जितने भी विभाग हैं उनका हो, सभी में चहुंमुखी विकास किया है। इसके लिए ये वाकई बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने, मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने "सरकार आपके द्वार" नामक कार्यक्रम चलाकर पूरे देश को एक राह दिखायी है। यह कार्यक्रम न केवल हमारे प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो गया है। दूसरे प्रदेश भी हरियाणा के इस कार्यक्रम के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं और इस कार्यक्रम की सफलता को देखकर अचम्भित होते हैं कि किस प्रकार से चौटाला साहब ने "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम चलाया है। अध्यक्ष महोदय, खुद मुख्य मंत्री जी लोगों के दरवाजों पर जाकर पूछते हैं कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर विकास की लहर दौड़ रही है। चौटाला साहब को विकास पुरुष की संज्ञा इसलिए ही दी जाती है। साढ़े तीन साल पहले प्रदेश की बहुत बुरी हालत 11.00 बजे थी। आज तो हर गांव विकास के नये आयाम छू रहा है। चाहे स्कूल के कमरे हों, चाहे सड़कें हों, चाहे पी०एच०सी० हों और चाहे पशु अस्पताल हों ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर किसी न किसी रूप में कोई काम न चल रहा हो। "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के माध्यम से प्रथम चरण में 920 करोड़ रुपये के रिकार्ड 12687 निर्माण कार्य पूरे कराए गए थे और दूसरे चरण में 596 करोड़ रुपये के 9282 कार्य सम्पन्न कराए गए और 5855 पर कार्य जारी है। तीसरे चरण में कुल मिलाकर 33 हजार विकास कार्य आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे कराए हैं और इन पर अब तक 2 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं (थम्पिंग) इस समय हर गांव में और शहरों में सड़कों का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। चाहे स्कूल के कमरे हों या स्कूल के साथ लगते शमशान घरों में दीवारें खड़ी करने का काम हो, या मवेशी अस्पताल और डिस्पैंसरीज हों सभी में तेजी से काम जारी है। मेरे अपने हल्के का मुझे ज्ञान है जहां कभी सारे के सारे विकास के काम ठप्प थे। मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 32 करोड़ रुपये के काम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूरे हुए हैं इसके लिए वे धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। इस सरकार ने हर मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है यह सरकार किसानों की सरकार है और इस सरकार ने सिंचाई को हमेशा सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। सूखे के बावजूद सरकार ने नहरों के माध्यम से 21 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की है और बेहतरीन सिंचाई सुविधा उपलब्ध

करवाने व पानी की निकासी हेतु 163 करोड़ 35 लाख की सिंचाई की 129 स्कीमें व जल निकासी की 13 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इसके लिए इस सरकार की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। साथ ही पश्चिमी यमुना नहर की सिरसा शाखा, हांसी शाखा, दिल्ली शाखा तथा अन्य संबंधित नहरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पहले की सरकारें किसानों के खालों को पक्का करने के लिए किसानों से ही पैसा लेती थी लेकिन अब चौटाला साहब की सरकार किसानों से कोई भी पैसा लिये बगैर किसानों के खालों को मुफ्त में पक्का करवाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन पूरी तरह से जानता है और हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि एस०वाई०एल० हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है हर आदमी का और हर किसान का यह सपना है कि रावी व्यास का पानी एस०वाई०एल० के माध्यम से हरियाणा को मिले। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की बड़े बेहतरीन ढंग से पैरवी की है और उनके प्रयासों की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार को आदेश दिया कि 15 जनवरी, 2002 तक यह एस०वाई०एल० कैनाल पूरी हो जानी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पंजाब सरकार की हठधर्मी से उन्होंने अभी तक भी इस नहर पर कोई भी किसी प्रकार का काम अब तक नहीं किया है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि वे इसके लिए कितने गंभीर हैं। वे इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए हैं और पंजाब सरकार व केन्द्र सरकार को नोटिस दिया है। मुझे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 24 तारीख लगी है। हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के किसानों को एस०वाई०एल० कैनाल का पानी अवश्य मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जब-जब भी पानी का बंटवारा हुआ है तब-तब हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है। जहां तक रावी व्यास और यमुना जल के समझौतों की बात है, पूर्व मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी अभी यहां बैठे थे, अब नहीं हैं मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरह से हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात किया है। अध्यक्ष महोदय, यमुना जल का बंटवारा 12 मार्च, 1952 को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ था जो उस समय पंजाब में था। इसमें दो हिस्से पानी पंजाब को मिलना था और एक हिस्सा पानी उत्तर प्रदेश को मिलना था। यानी यमुना का कुल पानी 12 बिलियन क्यूबिक मीटर था जिसमें से हरियाणा के हिस्सा का 8 बिलियन क्यूबिक मीटर था और **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** 4 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से का था। लेकिन उसके बाद 12 मई, 1994 को कांग्रेस पार्टी के कमजोर नेतृत्व के कारण एक यमुना जल समझौता करके एक आत्मघाती समझौता किसानों के खिलाफ हुआ। उसमें जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उसको तो 4 बिलियन क्यूबिक मीटर ही बरकरार रखा गया और जो हमारे हरियाणा के हिस्से का 8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी था उसमें से हरियाणा के हिस्से में केवल 5.7 बिलियन क्यूबिक मीटर रखा गया और बाकी जो 2.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को, मैं कहता हूं कि बेच दिया। उस सरकार ने 12 मई, 1994 को हरियाणा के हितों को बलि चढ़ा दिया । उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से हरियाणा के किसानों के साथ उस समय बड़ी बेईनसाफी हुई थी। उसके बाद 29 फरवरी, 1996 को एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जस्टिस कुलदीप सिंह का कि दिल्ली को पानी हरियाणा पहले देगा इसमें कहा गया पहले दिल्ली को पूरी तरह पानी दे दिया जाये तब हरियाणा को पानी मिलेगा। उस फैसले की वजह से पहले मानवीय आधार पर हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए 200 क्यूसिक पानी प्रतिदिन

[श्री उदयभान]

छोड़ती थी और उसकी एवज में दिल्ली सरकार से पैसे वसूल करती थी लेकिन अब कोई पैसा नहीं मिलता और आज 800 क्यूसिक पानी प्रतिदिन सरकार को देना पड़ रहा है। जिसकी वजह से हरियाणा में पानी की बहुत कमी है जिससे विशेषकर हमारा जिला बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार एक तो हमारा पानी रोक रही है और दूसरी तरफ जो हमें पानी मिल रहा है वह सारा पोल्यूटिड पानी मिल रहा है। दिल्ली के करीब 22 गन्दें नाले यमुना के अन्दर पड़ रहे हैं जिससे फरीदाबाद और गुड़गांव के लोगों को जो पानी मिल रहा है वह गन्दा पानी मिल रहा है। उससे तरह-तरह की बिमारियां फैल रही हैं। दूसरा पोल्यूशन की वजह से बड़ी भारी दिक्कत है इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा के दिल्ली सरकार को मजबूर किया जाये कि इस पानी को ट्रीट करके यमुना में डाला जाए ताकि जो पानी हम लोगों को मिल रहा है वह शुद्ध मिले। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में इस सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिजली के मामले में इस सरकार ने सराहनीय काम किया है। बिजली हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। बिजली के उत्पादन में जो प्रतिस्थापित क्षमता है उसमें 792 मैगावाट की रिकार्ड वृद्धि हुई है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। 1998-99 की तुलना में बिजली की उपलब्धता में 43 प्रतिशत अधिक बढ़ौत्तरी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 प्रतिशत अधिक उपलब्धता बढ़ी है। हमारे फरीदाबाद जिले में गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट स्टेशन 143 मैगावाट और 146 मैगावाट की दो यूनिटस चालू की गई हैं। इस सरकार के कार्यकाल में जनवरी, 1999 से बंद पानीपत थर्मल प्लांट की 110-110 मैगावाट की दो यूनिटों के आधुनिकीकरण का काम पूरा हो चुका है और सातवीं और आठवीं यूनिटस जो 250-250 मैगावाट की पानीपत थर्मल प्लांट की हैं इनका कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2001-2002 में 40 प्रतिशत अधिक बिजली पैदा की गई है और 24 हजार नये ट्यूबवैल कनैक्शन दिए गये हैं जो कि बहुत सराहनीय काम है। इससे पहले हरियाणा विकास पार्टी की सरकार के तीन साल के शासन काल में केवल मात्र 3690 ट्यूबवैल कनैक्शन दिए गए थे जबकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में 24 हजार नये कनैक्शन ट्यूबवैल के दिए गए हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली और कृषि के दूसरे साधन भी मुहैया करवाये हैं जिसके कारण हरियाणा में इतना ज्यादा सूखा होने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के उत्पादन पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा । तिलहन और गेहूं का उत्पादन पहले से अधिक हुआ है। सूखा होने के कारण धान के उत्पादन में कुछ कमी जरूर हुई है। पिछले वर्ष जहां तिलहन का 8 लाख 7 हजार टन का उत्पादन हुआ वह बढ़कर इस साल 8 लाख 80 हजार टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष गेहू का उत्पादन 94 लाख 37 हजार टन हुआ जबकि इस वर्ष 95 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष धान का उत्पादन 40 लाख 86 हजार टन हुआ था जो इस वर्ष सूखे के कारण कुछ कम होने का अनुमान है तथा इस वर्ष 37 लाख 2 हजार टन धान होने का अनुमान हैं । जिस हिसाब से हरियाणा में सूखे की मार थी उसको देखते हुए यह भी बहुत अच्छी पैदावार है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बार सहकारी चीनी मिलों ने भी सराहनीय काम किया है। हरियाणा में 12 सहकारी चीनी मिलें काम कर रही हैं, इन सहकारी मिलों ने जो सराहनीय कार्य किए हैं उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को जितनी बधाई दी जाये वह कम है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने किसानों को गन्ने के भाव 110

रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया है जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी चीनी मिलों ने 361.38 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 34.77 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। इन अच्छे और उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमारे प्रदेश की तीन सहकारी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रथम पुरस्कार मिले हैं और करनाल की कोआपरेटिव शुगर मिल को पूरे भारत वर्ष में सर्वप्रथम पुरस्कार मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए भी बहुत सराहनीय कार्य किए हैं । पहले सड़कों पर चार-चार फिट के गड्डे पड़े हुए थे और पहले वाली सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती थी। बसें और दूसरे वाहन उन सड़कों पर नहीं चल सकते थे और लोग बसों और दूसरे साधनों में जाने की बजाय पैदल जाना पसन्द करते थे। उन सड़कों की तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा ध्यान दिया और 4187 कि०मी० लम्बी नई सड़कें बनवाई तथा 15700 कि०मी० लम्बी सड़कों की मुरम्मत करवाई। इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 550 कि०मी० लम्बे स्टेट हाई-वे को सुदृढ़ करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और केन्द्रीय सड़क कोष योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड से 63 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने करवाया है। इसके अतिरिक्त राज्य में 20 पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड से 20 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत करवाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो विकास के कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जन-स्वास्थ्य के मामले में यह सरकार बहुत गम्भीर रही है। सरकार की तरफ से पूरे प्रयास रहे हैं कि किसी भी गांव में पीने के पानी की कोई दिक्कत न रहे। मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा और उन्हें बधाई दूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने 2090 गांवों में पेय जल सप्लाई की वृद्धि की है। 239 गांवों में नये जल घर लगाये हैं तथा 488 जल घरों की सप्लाई में वृद्धि की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में 107 करोड़ रुपये जन-स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए रखे हैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। पाईपों द्वारा जो हरियाणा में पेय जल आपूर्ति की जा रही है इस मामले में हरियाणा पूरे देश में प्रथम स्थान पर है इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री महादेय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैं परिवहन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने परिवहन का सारा ढांचा ही बदल दिया है। इन्होंने हरियाणा परिवहन के बेड़े में 1571 नई बसें शामिल की हैं, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यदि मैं सरकार द्वारा किए गए एक-एक कार्य को गिनाऊं तो काफी समय लग जायेगा। हमारी सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देकर शिक्षा के बजट को 3 गुणा कर दिया है। शिक्षा के तहत सरकार ने 126 प्राईमरी पाठशालाओं को बदल कर उन्हें मीडिल स्कूल बनाया है। 69 मीडिल स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उनको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया है और 106 हाई स्कूलों को गवर्नमेंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार से 56 गवर्नमैंट कालेज और 120 गैर सरकारी कालेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार किया गया है। अब हरियाणा प्रदेश में पहली कक्षा से अंग्रेजी सिखाई जायेगी और छठी कक्षा से कम्प्यूटर की शिक्षा चालू की गई

[श्री उदयभान]

है। पूर्ण साक्षरता अभियान भी सभी के सभी 19 जिलों में चल रहा है। जहां पर पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक टाट का भी प्रबंध स्कूल में बच्चों के लिए नहीं था वहां अब इन बच्चों को डैस्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्या श्रीमती वीना छिब्बड़ पदासीन हुई।)** चेयरपर्सन महोदया, इसी प्रकार से हमारी सरकार ने टैक्नीकल एजूकेशन के क्षेत्र में भी काफी सुधार किया है। हमारी सरकार ने आधुनिक तकनीकी शिक्षा के तहत लोगों को रोजगार के अवसर बढाए हैं। हमारी सरकार का 4 इन्जीनियरिंग कालेज, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये का लोन विश्व बैंक से लेने का प्रस्ताव है। सरकार ने टैक्नीकल एजूकेशन में डिग्री और डिप्लोमा करने वालों के लिए जहां पहले 9 हजार छात्रों की सीटें थी अब उनको बढा कर 25 हजार सीटों में बदल दिया है, इसके लिए भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदया, जनसंख्या नियन्त्रण में भी इस सरकार का कोई जवाब नहीं है। आज देवी रूपक योजना को दूसरे प्रदेश भी अपनाने के लिए लालायित हैं। वे इस स्कीम से बड़े अचम्भित हैं। दूसरे प्रदेश हमारी इस स्कीम से बहुत प्रभावित हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी यह एक शानदार योजना लाये हैं कि पहली संतान अगर लड़की होती है और उसके बाद वह नसबंदी करा लेता है तो उसको 20 साल तक 500 रुपये प्रतिमास प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। अगर दूसरी लड़की होती है और दो लड़कियों के बाद नसबंदी करा लेता है तो उसको 200 रुपये मासिक के हिसाब से प्रोत्साहित राशि दी जायेगी। अगर एक लड़का होता है और उसके बाद वह नसबंदी कराता है तो उसको भी 200 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जायेगी।

ऐसी योजना लाकर सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और यह एक बहुआयामी योजना है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं समझता हूं कि इससे निश्चित तौर पर जो लड़के और लड़कियों के अनुपात में अन्तर हो रहा था उसको दूर करने में सफलता मिलेगी और जनसंख्या नियंत्रण में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

सभापति महोदया, औद्योगिक क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े भरसक प्रयास किये हैं। मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों को हमारे प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए काफी सुविधाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर बाहर के लोग भी हमारे यहां पर अपने उद्योग लगाने में रुचि लेने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी की कोशिश के कारण ही हमारा एक्सपोर्ट पहले से दो गुणा बढा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा यह एक्सपोर्ट 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्रयास से हरियाणा प्रदेश के अन्दर 140 बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। लघु उद्योग की हमारे प्रदेश में लगभग चार हजार इकाईयां स्थापित हुई है जिनमें लगभग एक लाख 54 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है तथा इनमें आठ हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। जिला गुड़गांव में गढ़ी हरसाऊ में दो हजार एकड़ ज़मीन ऐक्वायर करके वहां पर इकोनोमिक ज़ोन विकसित किया जा रहा है जहां उत्पादन शुल्क की छूट होगी इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी बधाई

के पात्र हैं कि गुड़गांव के अन्दर ऐसा जोन स्थापित किया जा रहा है जिसमें उत्पादन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में एक सवाल के जवाब में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि किस प्रकार से 40 भवन बने हैं और 26 भवनों में अभी काम चल रहा है जनरल अस्पताल, पी०एच०सीज० तथा सी०एच०सीज० के भवन बन रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त होने पर तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए करनाल में ट्रोमा सैंटर खोला गया है। फरीदाबाद, रिवाड़ी तथा सिरसा में ऐसे सैंटर खोले जाने की योजना है। महाराज अग्रसेन मेडिकल इंस्टीच्यूट, अग्रोहा की ग्रान्ट पिछली सरकारों ने रोक दी थी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आते ही इस ग्रान्ट को खोला और अभी ग्रान्ट देने के लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा है उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं (इस समय मेजें थपथपाई गई) चेयरमैन महोदया, इस सरकार ने सामाजिक न्याय किया है एस०सीज० और बी०सीज० लोगों के कल्याण के लिए इस सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहली बार जननायक माननीय चौधरी देवी लाल जी ने गरीबों, दलितों और पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी। मुजारों के लिए सब से पहले लड़ाई लड़ने वाले चौधरी देवी लाल जी थे। इस प्रदेश में हरिजन चौपाल की कोई योजना चलाई तो वह चौधरी देवी लाल जी ने चलाई। इस से पहले कहीं पर भी हरिजन चौपाल की कोई योजना नहीं थी। जच्चा-बच्चा को खुराक भोजन की योजना भी माननीय चौधरी देवी लाल जी ने चलाई। जिसका पहला या दूसरा बच्चा हो उसको खुराक के रूप में राशि दी जाएगी। विद्यार्थियों का वजीफा भी इस सरकार ने दुगना कर दिया। आरक्षण नीति पर चौधरी देवी लाल ने बहुत ही सकारात्मक रूप अपनाते हुए जनता को सुविधा दी। चौधरी देवी लाल जी एक व्यवहारिक आदमी थे और उनको पता था कि लोगों की जरूरत क्या है। उन्होंने रोस्टर प्रणाली को भी लागू किया ताकि उनके साथ किसी किस्म का भेदभाव न हो और जो बैकलॉग है वह पूरा हो। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए माननीय मुख्यमन्त्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस दलित वर्ग, गरीब पिछड़े वर्ग के लिए बहुत अधिक काम किया है। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के लिए चौपालों के मामले में ऐलान किया जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने जहां गांव-गांव में वृद्धाश्रम खोलने का काम किया है वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी भी दलित के लिए 5100/- रुपये की कन्यादान की योजना लागू की उसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। ऐसा कहीं पर नही है कि 5100/- रुपये का कन्यादान सरकार की तरफ से दिया जाता हो। इसके अलावा वृद्धावस्था में पैंशन, विधवा पैंशन तथा विकलांग पैंशन भी चौधरी देवी लाल जी ने शुरु की थी। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने इस पैंशन को दुगना करके बहुत उपकार किया है। वृद्धों की चिकित्सा के लिए सरकार ने मुफ्त इलाज की व्यवस्था की तथा उनको मुफ्त चश्में भी दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों का वजीफा भी दुगना किया गया है।

10वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए 700 रुपए का वजीफा, किताबों के लिए 2000/- रुपए तथा 1500/- रुपए लेखन सामग्री के लिए दिए गए हैं। एस०सी०, बी०सी० स्व-रोजगार स्कीम के तहत पिछले 40 मांह में 84 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश का हरिजन, दलित सब लालायित होकर इस सरकार की तरफ देख रहे हैं। वे आपसे बहुत उम्मीद रखे हुए हैं। पिछली सरकारों ने दलितों को बांटने का काम जरूर किया है लेकिन उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है। मेरी मांग है कि भारत सरकार द्वारा यह जो 81वां और 85वां संविधान में संशोधन किया है वह हरियाणा सरकार द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए।

[श्री उदयभान]

यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली और राजस्थान की सरकारों ने यह पहले ही लागू कर दिया है। अगर यह यहां पर भी लागू होगा तो जो कमियां बैकलॉग पूरा करने में आती हैं वह नहीं आएंगी और बैकलॉग पूरा हो जाएगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यह जो एस0सी0, बी0सी0 के कर्मचारियों की छंटनी हुई है उस बैक लॉग को भी इसके माध्यम से पूरा किया जाए।

चेयरमैन महोदया, खेल और युवाओं के मामले में इस सरकार का कोई सानी नहीं है। भाई अभय सिंह चौटाला और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस सरकार ने इस बारे में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 14 अगस्त, 2001 को नई खेल नीति निर्धारित की गई है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों में पदक पाने वाले को 8 हजार रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के इनाम रखे हैं। हाल ही में राष्ट्र मण्डल में 11 पदक और एशियाड में 14 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। हैदराबाद में राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 74 पदक प्राप्त करके सातवां स्थान प्राप्त किया है। हमारी यह सरकार बधाई की पात्र है कि वर्ष 2002-03 में 2 करोड़ 13 लाख रुपए इनाम की राशि बांटी है। गांव जौशी चौहान में भारतीय खेल प्राधिकरण के चौधरी देवी लाल उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है। हाकी के दो एस्ट्रोट्रफ भी गुड़गांव व शाहबाद में बिछाए जा रहे हैं। इसके लिए भी यह सरकार बधाई की पात्र है। इससे लगता है कि यह सरकार खेलों के प्रति कितनी जागरूक है, कितनी संवेदनशील है। इस सरकार ने ड्वैल्पमैंट ऑफ पंचायत के लिए फ्री स्कीमें चलाई हैं। इस सरकार ने एच०आर०डी०एफ० से 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से ही 31 जनवरी, 2003 तक 197 करोड़ 63 लाख रुपए ड्वैल्पमैंट पर खर्च किए हैं। स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना पर 7 करोड़ 8 लाख रुपए हरिजन महिलाओं पर खर्च किए हैं।

इसके लिए भी सरकार बहुत बधाई की पात्र है। चेयरमैन महोदया, एस०आर०वाई० के तहत 65 करोड़ रुपए दिसम्बर तक खर्च किए हैं और इन्दिरा आवास योजना के तहत 6 हजार 88 मकानों का निर्माण किया गया है उसके लिए भी यह सरकार बधाई की पात्र है। चेयरमैन महोदया, इसके साथ मैं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगा कि होडल के अन्दर मुख्यमंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत सीवरेज सिस्टम डालने के बारे में घोषणा की थी। यह यमुना एक्शन प्लान के तहत बनना था लेकिन पता नहीं उसके बनने में क्या अड़चन आ रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि होडल में कहीं पर भी कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। वहां पर बिना सीवरेज के बहुत ही परेशानी हो रही है। मेरा सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस सीवरेज सिस्टम को प्राथमिकता के आधार पर यमुना एक्शन प्लान के तहत किसी दूसरे हैड से किसी भी तरह जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाने का कष्ट करें।

मिनी सचिवालय की होडल में बहुत शीघ्र आवश्यकता है। मिनी सचिवालय के बगैर वहां पर सभी ऑफिसर्ज, चाहे वह तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो या डी०एस०पी० हो एक बिल्डिंग में नहीं बैठ सकते। मिनी सचिवालय के बगैर वहां पर बड़ी भारी परेशानी है। हम बड़े आभारी हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इसको शीघ्र ही बनवाने का आश्वासन दिया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसका शीघ्र ही पत्थर रखवाकर काम शुरु करवाने की अनुकम्पा करें। चेयरमैन महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और अनुरोध करूंगा कि होडल के अंदर जो मंडी

है वह बहुत ही कंजैस्टैड है जिस कारण वहां पर माल नहीं आ सकता । खुद मुख्यमंत्री जी इस तथ्य से परिचित हैं इसलिए उन्होंने घोषणा की थी कि सवा सो एकड़ में वहां पर एक अनाज मंडी बनायी जाएगी। दक्षिणी हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी होडल मंडी है इसलिए इस तथ्य को देखते हुए शीघ्र अति शीघ्र इस मंडी को वहां पर बनवाया जाना आवश्यक है। इस बारे में एक प्रपोजल भी आया हुआ है, इस प्रपोजल को सिरे चढ़ाने की अनुकम्पा करें। चेयरमैन महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि पलवल की जो यमुना रोड़ है उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। उसकी आधी की तो मरम्मत हो गयी थी लेकिन आधी जो पलवल साईड में है उसकी हालत बहुत खराब है इसलिए इसको भी शीघ्र बनवाया जाए। इसी तरह से पलवल रेलवे क्रासिंग पर पलवल यमुना रोड़ पर मुख्य मंत्री जी ने एक रेलवे क्रासिंग पर पुल बनवाने का आश्वासन दिया था। उसको भी प्राथमिकता के आधार पर लेकर रेल मंत्री श्री नीतिश कुमार जी से मिलकर पहले फेज में क्लीयर करवाया जाए और इस पुल को बनवाने की अनुकम्पा की जाए। इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले की आबादी संभवत: इस समय हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से ज्यादा है, इस समय लगभग साढ़े अठारह या 19 लाख की आबादी फरीदाबाद की है। आबादी ज्यादा होने की वजह से वहां पर लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि होडल, हथीन और पलवल की सब-डिवीजन्ज को मिलाकर पलवल को नया जिला बनाने की भी अनुकम्पा करें। चेयरमैन महोदया, हसनपुर ब्लाक में कोई भी सी०एच०सी० नहीं है जबकि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से हर ब्लाक में एक सी०एच०सी० होनी चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हसनपुर की पी०एच०सी० का दर्जा बढ़ाकर सी०एच०सी० किया जाए। एक और अनुरोध मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा। जो आगरा कैनाल है उसको लेकर बड़ी भारी समस्या हमारे जिले की रही है। इस कैनाल से वहां पर जो रजबाहा निकलता है उससे होडल और हथीन एरिये की सिंचाई होती है लेकिन इसका कंट्रोल यू०पी० सरकार के हाथ में है जिसकी वजह से वहां पर बड़ी भारी दिक्कत होती है, लोगों को पानी ही नहीं मिलता। अगर गुडगांव फीडर से लेकर पिठवारी फीडर तक एक छोटी कैनाल बना दी जाए तो हमेशा के लिए आगरा कैनाल की समस्या से निजात मिल सकती है। अगर अपनी नहरें हों और अपनी सारी व्यवस्था हो तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि इस काम को भी शीघ्र किया जाना चाहिए। चेयरमैन महोदया, अंत में मैं इस गरिमामय सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव हाउस में रखा गया है उसको एक मत से पास करके महामहिम के पास भेजा जाए। धन्यवाद।

सभापति : अब रामबीर जी इस मोशन को सैकेन्ड करेंगे।

श्री रामबीर सिंह (पटौदी-अनुसूचित जाति) : धन्यवाद, आदरणीय चेयरमैन महोदया, जो चौधरी उदयभान जी ने धन्यवाद प्रस्ताव आज इस हाउस में रखा है मैं भी उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण कल सदन में पढ़ा उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो हरियाणा सरकार ने पिछले वर्षों में हरियाणा का विकास किया है उसकी विस्तृत रिपोर्ट व जानकारी राज्यपाल महोदय ने इस सदन में रखी है। इसके लिए मैं पूरे सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाए। आप सभी को पता है कि आज से साढ़े तीन साल पहले किन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम-प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली थी। उस समय कानून-व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक

[श्री रामबीर सिंह]

व्यवस्था छिन्न-भिन्न थी और राजनीतिक व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। उस समय हरियाणा में शराब माफिया पनपा हुआ था और कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। प्रदेश में अस्थिर राजनीतिक माहौल था। प्रदेश की जनता भय और आतंक में जीवनयापन कर रही थी। जिन बच्चों के हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए थी उनके हाथों में उस समय शराब के पाउच होते थे। ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने इस साढे तीन साल के दौरान में इस हरियाणा प्रदेश को जो लगातार विनाश की ओर बढ़ रहा था, उसको विकास की नई दिशा दी। अब हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश में हरियाणा प्रदेश विकास की गति अग्रणी है और विकास की दृष्टि से हरियाणा एक नंबर का राज्य है, इसके लिए मैं विशेष रूप से चौटाला साहब का आभार प्रकट करना चाहूंगा। जो स्थितियां पिछले दिनों सामाजिक और धार्मिक परिवेश में हुई उनमें भी हरियाणा प्रदेश कानून और व्यवस्था की दृष्टि से बिल्कुल शांत रहा और बिल्कुल ठीक ठाक रहा और किसी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ। जब गुजरात में और अन्य राज्यों में धार्मिक दंगे हो रहे थे उस समय भी हरियाणा शांत रहा और मुझे गर्व है कि जिस विधान सभा क्षेत्र पटौदी का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां मुस्लिम समुदाय की आबादी भी काफी है। हमारी जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा दशहरे पर रामलीला आदि आयोजन होते हैं। हमारे यहां मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी के रोल किए और हमारे यहां किसी तरह का उन्माद पनपने नहीं दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर शांति और व्यवस्था कायम की । एस०वाई०एल० का जो मुद्दा है उसमें हमारे मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को जो ऐतिहासिक फैसला दिया कि एक वर्ष के भीतर पंजाब सरकार उस एस०वाई०एल० का निर्माण कार्य पूरा करे और यदि ऐसा नहीं होता तो केन्द्र सरकार उस एस०वाई०एल० को बनवाएगी। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के आभारी हैं। सदन के सभी सदस्य जानते है कि एस०वाई०एल० हरियाणा के लिए जीवन रेखा है। इस मसले को हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। पहली बैठक में तो हमारे कांग्रेस के सभी साथी शामिल हुए और यह निर्णय लिया गया था कि सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, एकजुट होकर हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए संघर्ष करेंगे और अपने हक के एस०वाई०एल० के पानी को लेकर रहेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि जब दोबारा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो हमारे कांग्रेस के साथियों ने उसका बहिष्कार किया और दिल्ली में जाकर माननीय प्रधान मंत्री के आवास पर धरना दिया। अगर उन्होंने धरना ही देना था तो कैप्टन अमरिन्द्र सिंह के निवास पर धरना देना चाहिए था या श्रीमती सोनिया गान्धी के निवास पर धरना देना चाहिए था या कांग्रेस के मुख्यालय पर धरना देना चाहिए था। जिनकी वजह से , जो नहर हमारी जीवन रेखा है, उसका पानी हमें नहीं मिल रहा है। बार-बार कैप्टन अमरिन्द्र सिंह जी अखबारों में ब्यान देते रहे हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। लेकिन हम एक जुट होकर यह एलान करते हैं कि हरियाणा के हक का पानी हम लेकर रहेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अगर ऐसा है तो फिर स्पोर्ट विदड्रा कर लें । (विघ्न)

श्री सभापति : कैप्टन साहब, आप बैठिए ।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : चेयरपर्सन महोदया, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि स्पोर्ट विदड्रा कर लो। ये क्यों नहीं सोनिया गान्धी जी से निवेदन करके पंजाब सरकार को डिजोल्व करवाते, जिसने कोर्ट का कहना नहीं माना। ये सोनिया गांधी पर प्रैशर डालें और कहें कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है, कोर्ट के फैसले को नहीं माना है और उस आदमी को डिसमिस किया जाये। ये क्यों नहीं कहते इनको ऐसा करने में तकलीफ होती है। ये जाकर सोनिया गांधी जी से कहें और पंजाब सरकार को डिसमिस करायें।

आई० जी० रिटायर्ड शेरसिंह : यह सोनिया गांधी के हाथ में नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह : यह सोनिया गांधी के हाथ में है। सोनिया गांधी के बिना तो एक दिन भी मुख्य मंत्री नहीं रह सकता। सोनिया की इजाजत के बगैर कांग्रेस का कोई नेता एक सैकिंड भी मुख्य मंत्री नहीं रह सकता। अगर सोनिया कहे कि रिजाईन करो तो करना पड़ेगा। अगर सोनिया कहे कि उल्टे खड़े हो जाओ तो खड़ा होना पड़ेगा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: चेयरपर्सन महोदया, इन्होंने इस बात की चर्चा की है हमारे को सुझाव दिया है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : सारी पावर सोनिया के हाथ में है वरना कैप्टन यहां बैठा होता ? (विघ्न)

श्री सभापति : रामबीर जी आप अपना भाषण शुरु कीजिये। आप सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठिये आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा।

प्रो० सम्पत सिंह : चेयरपर्सन महोदया, कांग्रेस पार्टी के सदस्य सोनिया गांधी को जाकर कहें कि जिस आदमी ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है वह मुख्य मंत्री रहने के लायक नहीं है । ये सोनिया गांधी से यह कह सकते हैं कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह का इस्तीफा तुरन्त मांगे। जिस आदमी ने कानून की अवहेलना की है, हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात किया है और जिस के कारण हरियाणा के किसानों और मजदूरों की गर्दन पर तलवार लटक रही है, उस आदमी को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। (विघ्न)

श्री सभापति : जो सदस्य चेयर की परमिशन के बिना बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

(इस समय कांग्रेस के बहुत से सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लग गये)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : चेयरपर्सन महोदया, * * * * *

श्री रामबीर सिंह : मैं तो इनको ये सुझाव दे रहा हूं कि ये जो धरना प्रधानमंत्री जी के निवास पर दे रहे थे उसकी बजाये इनको सोनिया गांधी जी के निवास पर धरना देना चाहिये था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : चेयरपर्सन महोदया, * * * * *

श्री सभापति : आप सभी सम्मानित सदस्य हैं मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। ऐसी भाषा पर नियंत्रण करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : चेयरपर्सन महोदया, * * * * *

श्री सभापति : आप सुनने की क्षमता रखें। आप अपनी जगह पर बैठें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रो० सम्पत सिंह : चेयरपर्सन महोदया, मैं आपकी ईजाजत लेकर बोल रहा हूं। क्या मुझे इजाजत है ?

श्री सभापति : बैठिये, प्लीज बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : सभापति महोदया, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदया, हरियाणा के लोग इनको माफ नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज आप लोग बैठें । आप सभी एक साथ खड़े होकर बगैर इजाजत लिये बोलते हैं यह गलत है। प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : सभापति महोदया , मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी हुड्डा साहब ने शोर शराबे में बोलते हुए अंत में एक बात यहां कही है और बाहर भी बार-बार यह बात कहते हैं कि पंजाब में बादल साहब की सरकार थी इसलिए हम नहीं बोले। सभापति महोदया, पूरे हरियाणा प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को पता है कि हरियाणा सरकार ने देश के टोप मोस्ट वकील पंजाब में बादल सरकार के खिलाफ किये जो अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में डिफैंड कर रहे थे और हरियाणा सरकार ने बाकायदा उस केस में जीत हासिल की। जब बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे। (शोर एंव व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदया, राजीव-लौंगोवाल फैसले का विरोध भी इन्हीं भाईयों ने किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज आप सभी बैठिये ।

प्रो० सम्पत सिंह : सभापति महोदया, हरियाणा के हितों के मामले में चाहे बादल सरकार हो या किसी ओर की सरकार हो, हम पहले अपने प्रदेश के हित देखेंगे। (शोर एंव व्यवधान)

श्री सभापति : हुड्डा साहब प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब आप सम्पत सिंह जी की बात तो सुनें। आपको जवाब देने का समय मिलेगा। आपके सभी सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। प्लीज आप सभी को बैठायें। (शोर एवं व्यवधान) ऐसे काम नहीं चलेगा।

प्रो० सम्पत सिंह : सभापति महोदया, आप इन्हें कहें कि ये मुझे मेरी बात तो पूरी कर लेने दें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : सभापति महोदया, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : हुड्डा साहब प्लीज आप अपने सभी सदस्यों को बैठायें। आप हाउस के अंदर हैं, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। पहले सम्पत सिंह जी को तो अपनी बात पूरी कर लेने दें। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब आप इतने सीनियर सदस्य हैं और आप ऐसे करें, यह ठीक नहीं है । आपकी बात मुझे ही नहीं सुन रही और किसी को कैसे सुनेगी। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनिता यादव : सभापति महोदया, * * * (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री सभापति : अनिता जी प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) अनीता जी की कोई बात रिकार्ड न की जावे।

प्रो० सम्पत सिंह : सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था कि हमने पहले पंजाब की सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और उस कानूनी लड़ाई में हम जीते। यह फैसला 15 जनवरी को आया और पंजाब सरकार को अगली 14 जनवरी तक एक साल का समय नहर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद फरवरी में पंजाब में चुनाव आ गये थे और बादल साहब चुनाव में व्यस्त हो गये थे आप ही बतायें कि 15 जनवरी से फरवरी तक सरकार के पास कितना समय बचा था। उसके बाद कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब के मुख्य मंत्री बन गये और जो समय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया था उस समय तक कैप्टन साहब ने एक इंच भी नहर का निर्माण नहीं करवाया वे टस से मस नहीं हुए। सभापति महोदया, कैप्टन साहब इस समय कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं। हमारे विपक्ष के भाईयों ने उनके द्वारा नहर न बनवाने पर भी उनका विरोध नहीं किया। नहर बनवाने के लिए मेरे विपक्ष के भाई न तो कैप्टन अमरिन्दर सिंह से मिले और न ही उनसे रिक्वैस्ट की कि वे नहर बनवायें। सभापति महोदया, पहले इनको कैप्टन साहब से नहर बनवाने के लिए रिक्वैस्ट करनी चाहिए थी यदि वे रिक्वैस्ट नहीं मानते तो उनको दूसरे तरीके से समझाते । मेरे कहने का मतलब यह है कि ये उनका विरोध करते। हम भी इनका साथ देते, इनको स्पोर्ट करते। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन इन लोगों को उस समय हरियाणा के हितों का अहसास नहीं हुआ और आज इनको अहसास हो रहा है। आज ये प्रधान मंत्री के आगे धरना देते हैं। सभापति महोदया, ये लोग सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ देखते हैं इनको लोगों की भलाई से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ अपने स्वार्थों में ही लिप्त हैं और केवल राजनीति की स्टंटबाजी करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। इनका एस०वाई०एल० नहर से कुछ भी लेना देना नहीं है। केवल मात्र स्टंटबाजी के लिए ये दिल्ली गए थे। एस०वाई०एल० से इनका कोई सरोकार नहीं है।

चौधरी भजन लाल : सभापति महोदया, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। आप मेरी बात सुनिये ।

श्री सभापति : चौधरी साहब, अभी रामबीर जी बोल रहे हैं, अभी आप बैठिये। आपको भी इनके बाद बोलने का मौका मिलेगा। इनके बोलने के बाद आप जी भर कर बोल लेना। अभी आप बैठिये। रामबीर जी आप बोलिए।

श्री रामबीर सिंह : सभापति महोदया, मैं एस०वाई०एल० के मुद्दे की बात कर रहा था। एस०वाई०एल० के मुद्दे पर पिछले सत्र में यहां पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस सर्वदलीय बैठक में हमारे कुछ साथी सुझाव देने की बजाये जल युद्ध रैली कर रहे थे और उस जल युद्ध रैली से इनकी फूट उजागर होती है। उसमें ये एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं कि यहां पर जो हाजिर नहीं है वह कांग्रेसी नहीं है। यह मंच से बाकायदा डिक्लेयर किया गया है। इनका यह जो जल युद्ध था हमारी समझ में नहीं आया। इनका यह जल युद्ध था या जन युद्ध था या मल युद्ध था हम समझ नहीं पाये। (विघ्न)

श्री सभापति : रामबीर जी आप कन्टीन्यू करें । (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती सरिता नारायण : सभापति महोदया, ... (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती अनिता यादव : सभापति महोदया, ... (शोर एवं विघ्न)

श्री सभापति : सरिता जी आप बैठिये। . . . . . (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती सरिता नारायण : सभापति महोदया, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : सरिता जी आप भी बैठिये।

श्रीमती अनिता यादव : सभापति महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष : अनिता जी आप बैठिये । (शोर एवं विघ्न)

श्री देवराज दिवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं . . . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देवराज जी आप बठिये। (शोर एवं विघ्न) अनिता जी आप भी बैठिये। दिवान साहब आप भी बैठिये। (शोर एवं विघ्न) सरिता जी आप भी बैठिये। अनिता जी आप चेयर को एड्रैस करके बात करें। अभी आप बैठें। आपकी बात हो गई है।

श्री भागी राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अभी तो हाउस में मात्र चार महिलाएं हैं और यह हाल है अगर हाउस में 33 महिलाएं हो गई तो क्या हालत होगी ? (हंसी)

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भागी राम जी ने ठीक ही कहा है यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी महिला सशक्तीकरण वर्ष चल रहा है इतना जोश तो आ ही जाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एस०वाई०एल० की बात कर रहा था। यह नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। विशेषतौर पर हमारा दक्षिणी हरियाणा इस वर्ष सूखे की चपेट में रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हरियाणा को एस०वाई०एल० का पानी मिलेगा तो खेतों को पानी मिलेगा इसलिए मेरी सदन से यह अपील है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर पूरे प्रदेश के हितों के लिए प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें सहयोग करें और माननीय मुख्य मन्त्री जी जो प्रयास करें उनका साथ दें। मान्यवर, हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों में विकास को जो गति दी है वह निस्संदेह सराहनीय है। जितने विकास कार्य इस साढ़े तीन साल में हुए हैं इतने विकास कार्य पिछले 40 साल में भी नहीं हुए। 33 हजार विकास के कार्य हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमन्त्री जी के नेतृत्व में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत किए हैं जो गिनीज बुक में भी लिखवाए जा सकते हैं। हरियाणा पहला प्रदेश है जो विकास की दिशा में आगे है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि की बात है, कृषि के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने बहुत विकास किया है। सूखे की स्थिति होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में तिलहन के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-2002 में तिलहन का 87,000 टन उत्पादन हुआ है जब कि गेहूं का 94 हजार 37 लाख टन उत्पादन हुआ है। इस वर्ष भी 95 लाख टन गेहूं का उत्पादन होने की आशा है। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्रयासों से केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव डाल कर किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिलवाया और किसान का एक एक दाना हरियाणा सरकार की मण्डियों में हरियाणा की ऐजैंसियों ने खरीदा। हमारे विपक्ष के भाई कहते हैं कि सरकार ने किसानों का अनाज नहीं खरीदा। कुछ साथियों ने मीटिंग करके कहा कि अगर किसानों को गेहूं का उचित मूल्य नहीं दिया गया तो हम धरना देंगे हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर धरना देना

ही है तो दिल्ली में जा कर दो, अगर धरना देना है तो राजस्थान में जा कर दो। दिल्ली और राजस्थान के विरोध में धरना दो जिनका गेहूं हमारे हरियाणा की मण्डियों में आ कर बिका। यह गेहूं हरियाणा की मण्डियों में इसलिए बिका क्योंकि वहां पर गेहूं खरीदने की व्यवस्था ठीक नहीं थी और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब तो उल्टे बांस बरेली को वाली बात हो रही है। हमारे यहां का गेहूं, सरसों और अन्य कृषि की उपज गुड़गांव से आ कर दिल्ली की 12.00 बजे नजफगढ़ मण्डी में बिकती थी। अब की बार मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से नजफगढ़, दिल्ली और राजस्थान का गेहूं हमारे रिवाड़ी, पटौदी और जितने भी गुड़गांव के आस पास जैसे महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आदि की मण्डियां हैं उनके अन्दर आकर बिका है। उन जगहों की सरकारों की अनाज खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे भी तो सरकारें है लेकिन अनाज को खरीदने के लिए हमारी सरकार की अच्छी व्यवस्था थी तभी वे यहां पर आए। आज हमारे देश में कृषि मूल्य भारत सरकार तय करती है। हम मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं कि इन्होंने इतनी बढ़िया खरीद की व्यवस्था की कि किसान के अनाज का एक एक दाना उचित मूल्यों पर खरीदा गया है और किसान को मण्डी में किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने दी। स्वयं मुख्य मंत्री जी मण्डियों के अन्दर जाकर दौरा करते थे। इस प्रदेश में बहुत से मुख्य मंत्री आए हैं और इनसे पहले आज तक किसी भी मुख्य मंत्री ने मण्डियों के अन्दर झांककर नहीं देखा कि मण्डियों के अन्दर किसान की क्या दुर्दशा होती थी। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी किसान मण्डी में जाकर किसानों से पूछते थे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत ही आभारी हूं कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और कृषि के क्षेत्र में हरियाणा के किसानों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि इन्होंने प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए नई मण्डियों का निर्माण किया और बहुत सी नई मण्डियां बनाई। मेरे विधान सभा क्षेत्र हैली में एक सब्जी मण्डी और एक अनाज मण्डी की घोषणा की है। पटौदी और भौंड़ाकलां में भी नई सब्जी मण्डी बनाने की घोषणा की है। फरूखनगर में हमारी मण्डी जो छोटी पड़ गई थी उसका विस्तार करने के बारे में भी घोषणा की है। हमारे यहां पर चार मण्डियां हैं और मुख्य मंत्री जी ने उन चारों मण्डियों के विस्तार करने की घोषणा की है। इसके लिए मैं विशेष तौर से मुख्य मंत्री जी का अपने पूरे क्षेत्र के लोगों की तरफ से, सभी हरियाणा वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात अवश्य अपने माननीय साथियों को कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जून के महीने में हम विदेशों के दौरे पर गए थे। (विघ्न) हम अपने पैसे से गए थे। इस पर किसी को कमैन्टस कसने की जरूरत नहीं है। हमें जो सवा लाख रुपये यहां से मिलते हैं उनको निकलवाकर गए थे। हम कहीं पर भी अपने पैसों से जा सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। (विघ्न) लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वह बात आप कृपा करके ध्यान से सुनें। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आज विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। मैं पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि वहां पर खेती के लिए रासायनिक खाद का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। वहां पर जैविक खाद का प्रयोग होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार को आपके माध्यम से यह बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर भी रासायनिक खाद को बंद करके जैविक खाद का प्रयोग करने की प्रणाली को चालू किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे किसानों को अच्छी फसल मिल सकेगी और उनका उत्पादन अधिक हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर जी, आप जल्दी से वाइंड-अप करें।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तो शुरु ही किया है। मेरा ज्यादा समय तो ये लोग बीच बीच में बोलकर ले गए हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यहां पर अवश्य कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने कृषक उपहार योजना, जो गांधी जयन्ती पर लागू की है, उससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। इसके लिए मैं कृषि मंत्री जी का भी आभारी हूं जिन्होंने इतनी बढ़िया योजना बनाई। आज जो किसान मण्डियों में जाते हैं वे वहां पर अपना जे-फार्म लेकर जाएं। इसकी वजह से मार्किट फीस की चोरी पर अंकुश लगा है और इससे किसानों को भी फायदा हुआ है। इसकी वजह से किसानों को यह भी पता लगा है कि मण्डियों के अन्दर कितने पैसे कटते हैं। मण्डियों के अन्दर इसकी वजह से कोई अनियमितताएं नहीं हुई हैं।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने बहुत विकास कार्य किए हैं। विशेष तौर पर 8 लाख 98 हजार 565 किसानों को जो क्रैडिट कार्ड दिए हैं। ये इसलिए दिए हैं ताकि किसानों को एम०सी०एल० बनाने में कोई दिकक्त न आए, बार-बार बैंकों में या उनके अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़ें। इसकी वजह से किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकता है।

अब मैं सिंचाई के बारे में विशेषतौर पर हरियाणा सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो वर्षा के पानी का उपयोग होता है उसके लिए हरियाणा सरकार ने जो योजनाएं परियोजनाएं स्वीकृत की हैं उसके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं क्योंकि बरसात का जो हमारा पानी है वह ऐसे ही वेस्ट जाता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते और जब हमें पानी की जरूरत होती है तो हमें पानी नहीं मिलता। मैं हरियाणा सरकार का आभारी हूं कि इसने वर्षा के पानी का उपयोग करने के लिए सिंचाई की अनेकों परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समय हमारे क्षेत्र में जो पठौदा, लहारी, मुज्जफरनगर और हांसावास की लिफ्ट स्कीम्ज का निर्माण कार्य चल रहा है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए क्योंकि हमारे आधे क्षेत्र में खारा पानी है जिसकी वजह से किसानों को पीने के पानी की एवं खेतों के लिए पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसी तरह से विद्युत के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। नये नये बिजली के यूनिट लगाये गये हैं और पिछले वर्षों की तुलना में यानी 1998-99 में 43 परसैंट बिजली का अधिक उत्पादन किया है इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का और विशेष तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी 48 परसैंट बिजली दी गयी है। इसके इलावा सूखे की स्थिति में भी किसानों को बिजली मिली है जिससे उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया और अपनी खेती बाड़ी के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने 26 फरवरी को हमारे विधान सभा क्षेत्र के जटौली में एक सब-स्टेशन मंजूर किया है। इसके लिए मैं अपने इल्के के लोगों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी मुख्य मंत्री जी "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में जाते हैं तो वे सभी से पहले ही अपने सम्बोधन में कह देते हैं कि सड़कों की रिपेयर के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। सड़कों की रिपेयर हम इस हिसाब से करवा देंगे कि अमरीका की सड़कें भी हमारी सड़कों के सामने फीकी पड़ जाएंगी। जिस हालत में हरियाणा सरकार को प्रदेश की सड़कें मिली थीं वह आप सब जानते ही हैं लेकिन अब उन सड़कों के गड्ढों को भर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी

नेशनल हाई वे की तर्ज पर इन सड़कों का निर्माण करवाया गया है इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं। इसी तरह से जन-स्वास्थ्य विभाग ने पाईप लाइनों के द्वारा चालीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की मात्रा से बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन करके हरियाणा के नागरिकों को पानी देने का जो काम किया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही सरकार द्वारा पांच कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई की डिग्गी मंजूर की हैं इसके लिए भी मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं। केवल एक विधान सभा क्षेत्र में ही 18 करोड़ रुपये जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा खर्च किए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां खारा पानी था वहां के लिए कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई की डिग्गी मंजूर करना और एक ही हल्के में 18 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। अब इन पर कार्य भी चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है इसलिए वहां के लोगों को पीने के पानी की दिक्कत होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से परिवहन के मामले में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सरकार को और खास तौर पर परिवहन मंत्री श्री अरोड़ा जी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो पुराना ढांचा था और पुरानी बसिज थीं उनको उन्होंने बदलकर नयी बढ़िया बसिज हरियाणा के लोगों को दी हैं। विशेष तौर पर दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में जो उन्होंने डीलक्स बसिज और ए०सी० बसिज चलाकर लोगों को सुविधाएं दी हैं उसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। अगर इसी तरह की बसिज दिल्ली और जयपुर के बीच बाया रिवाड़ी होकर चला दी जाएं तो दक्षिणी हरियाणा के लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। रिवाड़ी और नारनौल से भी चंडीगढ़ के लिए इस तरह की ज्यादा बसिज चलायी जानी चाहिएं। पटौदी में जो बस स्टैण्ड की आधारशिला मुख्य मंत्री जी रखकर आए हैं उसका निर्माण जल्दी कराया जाए। यह मैं परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं और हरियाणा की शिक्षा की जो दिशा बिगड़ी हुई थी, उसे सुधारा है और इसके लिए जो प्रयास किए हैं वह सराहनीय हैं। साढ़े तीन साल पहले हरियाणा के जिन छात्रों के हाथों में और उनके स्कूल के बस्तों में शराब के पाउच होते थे उनकी जगह आज बच्चे किताबें पढ़ते हैं, खेलों में भाग लेते हैं और कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आजकल बच्चे जब सुबह घर से निकलते हैं तो ट्रैक सूट पहनकर निकलते हैं और सड़क पर दौड़ लगाते नजर आते हैं। इस प्रकार जो युवावर्ग दिशाहीन हो गया था उसे हरियाणा सरकार ने दिशा दी है और हरियाणा में विकास के नये आयाम स्थापित किए गए हैं। (विघ्न) हरियाणा की एक महिला अंतरिक्ष-यात्री कल्पना चावला का गत मास निधन हो गया उसके बाद हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि हरियाणा की जो भी लड़की दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम आएगी उसको कल्पना चावला मैमोरियल गोल्ड मैडल दिए जाएगा। हालांकि यह योजना अगले साल से लागू होनी चाहिए थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा बोर्ड का काम मुझे दिया हुआ है हमने अपने प्रयासों से 23 फरवरी को ही हरियाणा के ऐसे बच्चों कुमारी बबीता और दूसरी एक और बच्ची जिनके दसवीं में लगभग बराबर अंक थे उनको दोनों को गोल्ड मैडल और 25-25 हजार रुपये के चैक दिये गए। (विघ्न) शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास निसंदेह सराहनीय हैं। हमारे विपक्ष के साथी बार-बार अखबारों के माध्यम से यह आरोप लगाते रहते हैं कि मुख्य मंत्री जी विदेशों की सैर करने जाते हैं लेकिन असलीयत यह है और सबको पता भी है कि विदेशों से जो कंपनियां भारत में आकर अपने उद्योग स्थापित करना चाहती हैं उनको उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। यदि मुख्य मंत्री जी के टूर प्रोग्राम को देखा

[श्री रामबीर सिंह]

जाए तो पता चलेगा कि वे एक दिन एक शहर में कभी नहीं रुके, मीटिंग की और अगले दिन अगले शहर या किसी और देश में चले गए। अगर उनकी सैर सपाटे की नीयत होती तो वे चार-चार, पांच -पांच दिन एक शहर में रुकते। विदेशों में जाने का यह परिणाम हुआ कि गुड़गांव में मानेसर के अंदर . . . . (विघ्न)

श्री भागी राम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां जब भी किसी एयरपोर्ट पर हम उतरते थे वहां के रहने वाले लोग बाकायदा हमें लेने के लिए या हमारे स्वागत के लिए अपनी गाड़ियां लेकर आते थे और सही मायने में हमें वहां ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम अपने गांव में या हमारे घर में ही ठहरे हुये हैं। वहां पर सरकार के बारे में बता रहे थे कि चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार बहुत ही डिवलैपमैंट के काम कर रही है (थम्पिंग) विदेशों में भी इस सरकार की सराहना की जा रही थी। जहां तक एम०एल०ए० की बात आती थी तो एक दिन मुझे नहीं मालूम कहां की बात है वहां यह कहा जा रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में एम०एल०एज० की जो टीम है वह बहुत ईमानदार है और उनकी छवि अच्छी है। * * * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : जो यह * * * बात कही गई है यह रिकार्ड न की जाए।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के कार्यकाल में दिसम्बर, 2002 तक 140 बड़े उद्योग हमारे हरियाणा में स्थापित हुए हैं और चार हजार लघु उद्योग हरियाणा के अन्दर स्थापित हुए हैं जिनसे 1,54,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है और 8000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है जोकि एक रिकार्ड की बात है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेषतौर पर आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से रेवाड़ी के अन्दर कारगो कन्टेनर रेलवे विभाग की ओर से उसके उद्घाटन के केवल मात्र 83 दिन के अन्दर बनकर तैयार हो गया जोकि एक रिकार्ड की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। जिससे दक्षिणी हरियाणा के उद्योगपतियों को एक नई दिशा मिलेगी और सुविधायें प्राप्त होंगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। Sir, I am trying to put him straight. जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। इस कंटेनर का शिलान्यास तो पहले ही हो गया था। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठो आपको बाद में समय मिलेगा उस वक्त आप अपनी बात कह लेना।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो पहले कंटेनर डिपो का शिलान्यास रखा गया था वह रद्द हो गया था और अब नये सिरे से मौजूदा सरकार ने प्रयास करके उसको शुरु कराया और फिर उसकी आधारशिला मैं रख कर आया और हमारे यहां परम्परा नहीं रही है कि एक आधारशिला को दो बार रखा जाए। पहले वाली आधारशिला रद्द हो चुकी थी और इसके बारे में सदन जानकारी हासिल

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कर ले। आपके लिए तो यह फख्र की बात है कि 16 करोड़ रुपये की लागत से एक चीज ड्राई पोर्ट की शक्ल में केवल मात्र 83 दिन में कम्पलीट हो गई और उससे आपके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इनको तो स्टेट के हित की जो बात अच्छी हो उसकी सदन में सराहना करनी चाहिए।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में विश्व में बहुत क्रान्ति आई है और हरियाणा प्रदेश ने गत वर्ष 8000 करोड़ रुपये का रिकार्ड तोड़ निर्यात सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से किया है और उसमें से 3200 करोड़ रुपये का निर्यात सिर्फ सोफ्टवेयर का हुआ है। इसके लिए विशेषतौर से मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव देश का प्रमुख शोफ्टवेयर निर्यात करने वाला शहर है और यह देश के प्रमुख साफ्टवेयर निर्यात स्थलों में तीसरे नम्बर पर है। इसके लिए भी मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी विस्तार से सारी बातें बताई हैं। देवी रूपक योजना जो हरियाणा में महिला और पुरुषों में बढ़ते जा रहे अंतर को ठीक करने के लिए शुरु की गई है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इनका यह कार्य निसन्देह सराहनीय है। इस योजना के तहत पहले लड़की होने पर जो दम्पति नसबन्दी करवायेगा उसको 500 रुपये प्रति माह 20 वर्ष तक दिये जायेंगे। इस पैसे से उस लड़की की पढ़ाई-लिखाई और शादी बड़ी अच्छी तरह हो जायेगी। इस तरह से लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलेगा और लड़कियां हरियाणा प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। इसके अतिरिक्त इससे जो अनुपात लड़के और लड़कियों का हरियाणा में बढ़ता जा रहा है उसको भी दूर करने में हमें नई दिशा मिलेगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, भाई रामबीर जी जो कह रहे हैं उस बारे मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि लड़के और लड़कियों के अनुपात के बारे में सरकार गंभीर नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार ने पिछले साल 'अपनी बेटी अपना धन' स्कीम discontinue कर दी जो कि discountiue नहीं करनी चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह स्कीम discountinue क्यों की गई है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, शायद सम्मानित सदस्य को इस बात का ज्ञान नहीं है। यह स्कीम discontinue नहीं की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको कहें कि ये इस तरह की गलत इन्फार्मेशन सदन में न दें।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भाई कर्ण सिंह दलाल कह रहे थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत अधिक दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि लोग शराब पीकर ड्राईव करते हैं। दलाल साहब ने अपनी सरकार के समय में शराबबंदी करके देख लिया कि शराबबंदी के दौरान भी लोग शराब पीते थे और इन्होंने शराब का बिजनेस भी किया। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए करनाल में एक ट्रोमा सैंटर स्थापित किया इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय व स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे यहां जो हाई वे पट्रोलिंग व्यवस्था है वह पूरे देश में एक मिसाल है। दूसरे राज्य भी इसे एडोप्ट कर रहे हैं कि हरियाणा के हाई वे पट्रोलिंग से दुर्घनाएं बहुत कम हुई हैं। इसका श्रेय भी माननीय स्वास्थ्य श्री जी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जाता है।

[श्री रामबीर सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि करनाल की तर्ज पर दिल्ली से हिसार हाई वे पर, दिल्ली से जयपुर हाई वे पर और दिल्ली से आगरा हाई वे पर ट्रोमा सैंटर खोले जायें ताकि वहां पर जो लोग दुर्धटनाग्रस्त हो जायें उन्हें जल्दी उपचार सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर जी प्लीज आप समाप्त करें। आपको बोलते हुए 50 मिनट हो गये हैं।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाई मुझे बार-बार बीच में टोकते हैं। मेरे आधे समय में तो ये ही बोले हैं। अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो कार्य हरियाणा सरकार ने किए हैं वे निसन्देह सराहनीय हैं। विशेषतौर से बुढ़ापा पैंशन जो स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने शुरु की थी उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री महादोय ने इसे 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया जो हरियाणा के बुजर्गों को उनके सम्मान में दी जाती है उपाध्यक्ष महोदय, जिनके पास जमीन है, व्यापार है या जिन बुजर्गों के बच्चे नौकरी में है उनके लिए तो यह 200 रुपये चाहे विशेष महत्व न रखते हों और इससे उन पर कोई फर्क न पड़ता हो लेकिन जिस बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग आदमी के पास कमाने का कोई साधन नहीं हो और जब पैंशन के रूप में हर महीने ताऊ को और ताई को 200 रुपये मिलते हैं तो उससे उनको बहुत फर्क पड़ता है। यह योजना पूरे देश के अन्दर हरियाणा की एक मिसाल है। इसी प्रकार से कन्यादान के रूप में 5100 रुपये की राशि जो दी जा रही है यह हरियाणा के एक अग्रणी प्रदेश होने की मिसाल है। ऐसी योजना से हरियाणा का नाम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में ऊंचा हुआ है। यानि कहने का मतलब यह है कि भारत में ही नहीं विश्व में भी कहीं पर ऐसी योजना नहीं है जिसके तहत 5100 रुपये की राशि किसी गरीब हरिजन की बेटी को दी जाती हो। यह राशि लेकर एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी सम्मानजनक तरीके से कर सकता है और उसे दूसरों के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : यह राशि सभी को नहीं मिलती। यह राशि केवल उन्हीं को मिलती है जो गरीबी लाईन से नीचे रहने वाले लोग हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

श्री रामबीर सिंह : मैंने गरीब आदमी की बात कही है।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी आप बैठिये, बीच में न बोलें। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। रामबीर सिंह जी आप कन्टीन्यू करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, * * * * * * * *

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं विकास एवं पंचायत के मामलों से संबंधित बात कहना चाहता हूं। सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत काफी पैसा गांवों की पंचायतों को गावों के विकास के लिए दिया है। पहले हमेशा यह होता रहा कि गांव के लोग छोटी छोटी ग्रान्टों के लिए बी०डी०ओ० के पास अपने अधिकारी के पास, अपने एम०एल०ए० के पास और अपने मंत्रियों के पास चक्कर लगाते रहते थे तब जाकर उनको कहीं 10,15 या 20 हजार रुपये की ग्रान्ट

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मिलती थी। अब हरियाणा के मुखिया मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी हर विधान सभा क्षेत्र में जाकर 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत उनकी समस्याओं को सुनते हैं और इसमें किसी अधिकारी की जरूरत नहीं होती। अब जनता और मुख्यमंत्री जी के बीच में सीधा संवाद होता है और वहीं मौके पर जनता की समस्याओं का समाधान करके उनका निपटारा किया जाता है। मुख्य मंत्री जी ने यह एक निश्चित ही बहुत अच्छा कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत से दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने अलग अलग नाम से इस स्कीम को चलाया है। कई प्रदेशों ने नाम दिया है 'चलो गावों की ओर'। कहने का मतलब यह है कि नाम अलग दिया है, जबकि कार्यक्रम हमारा ही अमल में लाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाकर पूरे विश्व में निश्चित तौर पर एक अनूठी मिसाल कायम की है।

श्री अध्यक्ष : रामबीर सिंह जी आप वाईंड अप करें।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। हरियाणा के अन्दर जब माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने बागडोर संभाली थी उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। आये दिन बैंक डकैतियां, बलात्कार, लूटमार, डैकती और कारें छीनें जाने जैसी वारदातें होती थी। जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए थी और जिनके द्वारा हरियाणा के विकास में उनका योगदान होना चाहिए था वे ही दिशाभ्रमित होकर शराब माफिया, गाड़ियों के माफिया के गिरोह में शामिल हो गए थे और यह माफिया पूरे जोरों पर पनप गया था। माननीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने प्रयासों से हरियाणा को इन सब लोगों से बचाया है, इसके लिए पूरा सदन मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि हरियाणा के अंदर किसी की मजाल नहीं कि वह यहां पर अपराध करके बच कर चला जाये। इसी प्रकार से मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए अलग थानों की व्यवस्था की है। सरकार ने पुलिस में भर्तियां करके कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा है। इन सब कामों के लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। स्पीकर साहब, अन्त में मैं हाउस के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो प्रस्ताव चौधरी उदयभान जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखा है, उसको ध्वनिमत से पारित करें, जयहिन्द।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That an Address be presented to the Governor in the following terms :—
>
> > "That the Members of the Haryana Vidhan Sabha Assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 5th March, 2003."

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कल सदन में अपना जो अभिभाषण दिया उस पर मैं अपनी बात कहने के लिए आपकी इजाजत से खड़ा हुआ है । मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जो दो महानुभाव यहां पर अभिभाषण पर बोले हैं, एक तो प्रस्ताव रखने वाले और दूसरे प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले या सैकण्ड

[चौधरी भजन लाल]

करने वाले, उन दोनों ने ही बोलते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय का एक बार भी जिक्र नहीं किया है। सिवाय मुख्य मंत्री की तारीफ के पुल बान्धने के उनका और कोई काम नहीं था। वे उनकी तारीफ के पुल बान्धें, हम यह नहीं कहते कि वे उनकी तारीफ के पुल नहीं बांधें लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने अपना जो अभिभाषण दिया है उसमें उनका जिक्र तो करते। उन्होंने जो अभिभाषण दिया है उसमें उन्होंने सरकार की कारगुजारी बताई है। (विघ्न) अरोड़ा साहब, आप बैठें और मुझे कुछ बताएं नहीं (विघ्न) आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं मैम्बर हूं। हम सब कुछ जानते हैं (विघ्न) क्या मैं इस बात को नहीं जानता हूं। मैंने जो कहा है वह जानबूझ कर ही कहा है (विघ्न) क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं (विघ्न) यह क्या तरीका है? (विघ्न) मुख्य मंत्री जी, आप बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इन पर कुछ कण्ट्रोल तो रखें। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : भजन लाल जी, यह आपको सुझा रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : ये मुझे सुझा रहे हैं, क्या मैं पहली बार मैम्बर बन कर आया हूं। (विघ्न) ये कुछ नहीं जानते हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, इनका काम है गलतब्यानी करने वाले को सही रास्ते पर लाना।

चौधरी भजन लाल : क्या यह गलतब्यानी है, यह तो रिकार्ड की बात है (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी साहब, आप रिकार्ड देखें, प्रोसीडिंग्ज़ देखें। सर्वप्रथम गवर्नर साहब के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव से शुरू किया गया है, आपको इसका ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से विपक्ष को पूरा साथ मिलेगा और हमारी तरफ से कोई भी इन्टरप्ट नहीं करेगा। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है महामहिम राज्यपाल महोदय ने जहां कहीं भी इस बात का जिक्र किया गया है "मेरी सरकार का" वह पेज उन्होंने पढ़ा ही नहीं । क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार के काम तो ठीक है नहीं मैं क्या जिक्र करूं । महामहिम राज्यपाल महोदय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जब कैसीनो जैसा बिल असैम्बली से पास करके महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा गया तो राज्यपाल महोदय से हम सभी विधायक मिले और उनसे प्रार्थना की कि जुए और अयाशी के अड्डे हरियाणा प्रदेश में नहीं होने चाहिएं इसलिए इस बिल को आपको मन्जूरी नहीं देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, बिल में कोई अयाशी शब्द नहीं है। कैसीनो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देखा न जा सके (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : यह बात तो आप गर्वनर साहब से पूछें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आपने तो खुद यह खेल रखा है। (विघ्न) यह ठीक है कि उनकी यह संवैधानिक जिम्मेदारी है जो उन्हें पूरी करनी है।

चौधरी भजन लाल : यह आप गवर्नर साहब से पूछें। (विघ्न) महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस बिल को मन्जूरी देने की बजाय यह ऐतराज लगा कर कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए

राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। क्या सरकार को इस तरह का बिल पास नहीं करना चाहिए जिसको महामहिम राज्यपाल महोदय न मानें ? (विघ्न) मुख्य मंत्री जी, आप अपनी सारी बात बाद में कह लेना मैं यहीं पर ही रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गाली तो देता नहीं रिकार्ड की बात ही कहता हूं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमारी मन्शा यही है कि आप यहां पर बैठें। आप यह आश्वासन दें कि जब इसका जवाब दिया जाएगा तब आप इस सदन में ही रहेंगे। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : मैं इस सदन में ही रहूंगा (विघ्न) जब आप जवाब देंगे मैं उसको सुनूंगा भी। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह ठीक है लेकिन विपक्ष के नेता आश्वास्त करें कि आया रिप्लाई सुनते वक्त आपके सारे सदस्य हाजिर होंगे (विघ्न) यह दोनों की बात है यह तीसरा पतंग बीच में कहां से यूं ही आ गया है। (विघ्न) मैं तो आप दोनों की बात कर रहा हूं (विघ्न) सदन में हैसियत तो विपक्ष के नेता की होती है पार्टी अध्यक्ष की नहीं। भजन लाल जी, पहले आप यह बताएं कि सदन में हुड्डा साहब आपके नेता हैं या नहीं (विघ्न) यह आपके नेता हैं या नहीं (विघ्न) आपको यह बात बतानी चाहिए (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : इससे आपका क्या ताल्लुक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय की दूसरी बेइज्जती यह सरकार करने जा रही है जैसे इन्होंने यह कहा है कि प्रो-वाईस चान्सलर की सारी पोस्टें हम खत्म करेंगे। अब ये पी०वी०सी० की पोस्ट को खत्म करने जा रहे हैं। जो अच्छा काम करता है उनको ये खत्म करने जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय इनकी कोई रबर की स्टाम्प नहीं हैं। उन्होंने कैसीनो की मंजूरी नहीं दी तो अब ये बदले में कार्यवाही करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेन मुद्दा एस०वाई०एल० कैनाल, हरियाणा का है। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं और बाकी बातें बाद में करूंगा। एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में ये कभी कुछ कहते हैं और कभी सोनिया जी का नाम लेते हैं। जो कि इन्हें नहीं लेना चाहिए और न ही ये ले सकते हैं। कभी ये पंजाब में जाकर धरने की बात कहते हैं। एस०वाई०एल० कैनाल के काम का * * * * * * * * * * *।

श्री अध्यक्ष : यह जो बात भजन लाल जी ने कही है वह रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) आपने सोनिया जी का नाम हटाकर मुख्यमंत्री जी का नाम ले लिया यह क्या सही बात कही है? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आप इसको पढ़ लें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं राजीव-लौंगोवाल एकोर्ड की बात करना चाहूंगा कि वह हरियाणा के हितों के लिए अच्छा फैसला था। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं चौधरी देवी लाल जी का जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फैसले के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि यह फैसला गलत है और उन्होंने सभी मैंबर्ज से राजीव-लौंगोवाल फैसले के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया था। अगर उस वक्त यह फैसला लागू हो जाता तो आज हरियाणा में पानी की समस्या नहीं होती। उन्होंने उस फैसले को लागू नहीं होने दिया। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, 1995 में सुप्रीम कोर्ट

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[चौधरी भजन लाल]

में केस किया गया और वह केस भजन लाल की सरकार ने किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमने यह बात कही कि हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। उसी बात को मानकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी, 2002 को फैसला दिया कि एक साल के अंदर पंजाब सरकार यह नहर बनाए। जब यह फैसला आया था मैंने उसी वक्त इस सदन में कहा था कि यह नहर एक साल में बनकर तैयार नहीं होगी। इसलिए यह सरकार लिटिगेशन की बात करें और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाए कि एक साल की बजाय कोई तारीख निश्चित की जाए। लेकिन आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जिसमें हम भी शामिल हुए। आपने कहा कि हम सबको इस बारे में मिलकर पंजाब के राज्यपाल से मिलना चाहिए। हम आपके कहने पर उनसे मिले लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। आपने कागज पर कुछ लिखा हुआ था उस पर साईन करने को कहा तो हमने उस पर बिना पढ़े ही साईन कर दिए। लेकिन रिजल्ट कुछ निकला नहीं। सब बातें आपके सामने हैं। इस तरह नहर बनना मुश्किल है इसके बाद हमने फिर फैसला किया कि अगर गवर्नमैंट नहर नहीं बनाती तो 15 जनवरी, 2003 को हरियाणा की कांग्रेस पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करेगें और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उसके बाद हरियाणा के लाखों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए और प्रदर्शन किया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारा शिष्ट मंडल प्रधानमंत्री जी से मिला और उन्होंने पौने घंटा तक पूरी बात को सुना और उन्होंने यह भी कहा कि आपकी बात में तो वजन है अब देखते हैं कि क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि उनको लिमिटेशन में रहकर ऐसा कहना ही पड़ता है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया ?

चौधरी भजन लाल : काफी हद तक।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या आपकी तसल्ली हुई ?

चौधरी भजन लाल : काफी हद तक। लेकिन यह हमारी कोशिशों की वजह से हुआ आपकी वजह से नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप नहर बनवा दो हम आपको ही सारा क्रेडिट दे देंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे उनसे मिलने से पहले ये भी 14 तारीख की रात को उनसे मिले थे क्योंकि यह सोचते थे कि यह तो सारा श्रेय भजन लाल ले गया, कांग्रेस ले गयी इसलिए तुम भी चलो। ये बंसीलाल जी को भी अपने साथ ले गये । वे बेचारे बाद में पछता रहे थे कि मेरे से गलती हो गयी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कई दफा आदमी गलती कर बैठता है। इनकी बात को बंसी लाल जी ने मान लिया था लेकिन मानकर गलती कर बैठे। (विघ्न)

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल ने कोई गलती नहीं की। यह पानी का मुद्दा था, एस०वाई०एल० का मुद्दा था और हमारे जीवन मरण का मुद्दा था इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर कोई गलती नहीं की ।(विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको कोई गाली नहीं निकाली है। मैंने यही कहा है कि ये बेचारे बंसी लाल जी को भी अपने साथ ले गये। (शोर एवं व्यवधान) बेचारा कहना कोई गाली नहीं है। बेचारे कहने को भजन लाल कोई गाली नहीं मानता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे

अर्ज कर रहा था कि उसके बाद केन्द्र की सरकार हिल गयी। बाकायदा 15 दिन के अंदर चीफ सैक्रेटरीज एवं सैक्रेटरीज की मीटिंग उन्होंने बुलायी और मीटिंग में बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पानी तो एस०वाई०एल० नहर का देना पड़ेगा और नहर बनानी पड़ेगी । (शोर एवं व्यवधान) पानी के बगैर जीवन ही नहीं है। पानी बहुत जरूरी है इसलिए हम रो रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नहर के काम के बारे में ये श्रेय लेते हैं इस बारे में 31 दिसम्बर, 1981 का रिकार्ड मेरे पास है, देखना हो तो देख सकते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने तीनों मुख्य मंत्रियों को बुलाकर पानी का फैसला किया था। इस पर मेरे साइन हैं, दरबारा सिंह, मुख्य मंत्री पंजाब के साईन हैं व शिवचरण माथुर मुख्य मंत्री, राजस्थान के साईन हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : 1985 वाले समझौते के बारे में भी बता दें क्या उस पर भी आपके साइन हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च, 1982 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एस०वाई०एल० कैनाल की आधारशिला रखी थी। लाखों आदमी हरियाणा के वहां गए थे। अम्बाला के कपूरी गांव में उन्होंने खुद वह आधारशिला रखी थी और उसके बाद वहां नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ था और 95 प्रतिशत नहर का काम हम पूरा करवा कर गए थे। उसके बाद से इन्होंने एक रोड़ी भी वहां रखी हो तो ये लोगों को ईमानदारी से बता दें क्योंकि बादल की दोस्ती की वजह से इन्होंने यह काम नहीं किया इन्होंने यह सोचा कि बादल को इस तरह से ताकत मिल सकती है। ये सोचते थे कि बादल कैसे मुख्य मंत्री यहां रह सकता है। (विघ्न) अब आप 1985 की सुनें। 1985 में केस वापस लिया है हाईकोर्ट में केस था लेकिन जब ऐग्रीमैंट हो गया तो केस तो वापस लेना ही था। ऐग्रीमैंट न होता तो केस वापस लेने का सवाल ही नहीं था। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 1979 में केस किया गया था उस समय चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे, उसके बाद 1983-84 में भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे उस समय केस वापस लिया गया था।

चौधरी भजन लाल : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप वाइंडअप करें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा गला भी गर्म नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि खुलकर बोलना।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : 1985 वाले समझौते के बारे में आप फिर बताना भूल गए हैं।

चौधरी भजन लाल : 1985 में राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ था।

प्रो० सम्पत सिंह : आप यह बताएं कि लौंगोवाल कौन थे ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, लौंगोवाल साहब, अकाली पार्टी के हैड थे। मेरे पास बाकायदा समझौते की कॉपी है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उस पर आप अपने दस्तखत दिखा दें।

चौधरी भजन लाल : चण्डीगढ़ हरियाणा का अभिन्न अंग है इस पर मेरे दस्तखत हैं। यहां से दस्तखत कौन देखेगा, मेरे नजदीक आकर देखें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ये राव इन्द्रजीत को दिखा दें।

प्रो० सम्पत सिंह : राजीव-लौंगोवाल समझौते पर यदि उस समय के मुख्य मंत्री के दस्तखत हों तो हम मान लेंगे। अगर राव इन्द्रजीत जी कहेंगे कि साईन हैं, हम मान लेंगे। हुड्डा साहब को साईन दिखा दो हम मान लेंगे। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : 1981 के समझौते पर इन्दिरा गांधी, भजन लाल, शिवधरण माथुर और दरबारा सिंह के साईन हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी भजन लाल जी 1985 में इन्दिरा गान्धी इस संसार में नहीं थीं। आप ऐसा करिये चौधरी भजन लाल जी आपके अगल बगल में तो आपके विरोधी बैठे हैं इसलिए आप यह कापी चन्द्रमोहन जी को दिखा दें।

चौधरी भजन लाल : मेरे विरोधी तो सामने वाले भी नहीं हैं ये भी तैयार हैं लेकिन इनकी मजबूरी है। यह फैसला 1981 में ही हुआ था दुबारा 1985 में दूसरा फैसला राजीव-लौंगोवाल का था वह अलग है जिस पर मेरे साईन नहीं हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अगर चन्द्रमोहन भी यह कह दें कि इस पर मुख्य मंत्री के दस्तखत हैं तो हम मान लेंगे। 24 जुलाई, 1985 को राजीव-लौंगोवाल एकार्ड पर अगर हरियाणा प्रदेश के उस वक्त के मुख्य मंत्री के दस्तखत हों तो चन्द्रमोहन पढ़कर बता दें तो हम मान लेंगे।

चौधरी भजन लाल : उस वक्त जरूरत नहीं थी। राजीव-लौंगोवाल एकार्ड भारत सरकार और पंजाब वालों के बीच था। उस पर दस्तखत की जरूरत नहीं थी। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : फैसला सरकारों के बीच हुआ करता है प्रादेशिक हितों का फैसला सरकारों के बीच होता है लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का था कि उस वक्त के मुख्य मंत्री को कोई मान्यता ही नहीं मिली।

चौधरी भजन लाल : मान्यता तो मिली हुई थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यही तो हम कह रहे हैं कि आपको मान्यता नहीं मिली। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य था।

चौधरी भजन लाल : बड़ा दुर्भाग्य है। असली फैसला 1981 का यह है जो मैं दिखा रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह नहीं है फैसला। 1985 वाला फैसला सरकार का नहीं है, आप मान क्यों नहीं रहे।

चौधरी भजन लाल : सरकार का है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं है, 1985 वाला यह सरकार का फैसला।

चौधरी भजन लाल : यह सरकार का फैसला है 1981 में उस समय इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी भजन लाल जी, जुलाई 1985 का फैसला सरकार का नहीं है।

चौधरी भजन लाल : यह राजीव-लौंगोवाल एकार्ड है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप कांग्रेस पार्टी वालों से कहलवा दो कि यह सरकार का फैसला है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। कौन था लौंगोवाल, क्या हैसियत थी लौंगोवाल की ?

चौधरी भजन लाल : यह तो राजीव गान्धी से पूछो। लौंगोवाल अकाली पार्टी के हैड थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे।

चौधरी भजन लाल : उनसे पूछो। * * * *

श्री अध्यक्ष : यह * * * स्वर्ग वाली बात रिकार्ड न की जाये।

चौधरी भजन लाल : क्या फर्क पड़ सकता है।

श्री अध्यक्ष : हुडा साहब, एक बात बतायें कि एग्रीमेंट दो पार्टियों के बीच होता है अगर पार्टी कम्पीटैंट नहीं है तो वह वॉइड एग्रीमेंट है। अकाली पार्टी कोई सरकार नहीं है। यदि हरियाणा और पंजाब के सी०एमज० के बीच फैसला होता तो उसको एकोर्ड कह सकते थे void agreement is no agreement.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिये। राजीव-लौंगोवाल एकार्ड के आधार पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर फैसला किया है जोकि रिकार्ड में है उसकी कापी भी मेरे पास है। किसी ने देखना है तो वह भी देख सकते हैं। अब रह गया सवाल इस नहर को बनाने का। इस नहर को कौन बनायेगा। ये तो बना नहीं सकते। बादल की दोस्ती में पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। अभी कल-परसों के पेपर में पढ़ा कि जिस बादल को 700 करोड़ रुपये की जमीन दे सकते हैं उसके खिलाफ क्या बोल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में कानून-व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है जिसका कोई अन्त नहीं। मैं ज्यादा नहीं कहता थोड़ी सी बातें आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर (विघ्न) आप जितना कहें मैं उतना ही कह देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ नवम्बर महीने की बात बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय के जिला गुड़गांव में 16 नवम्बर, 2002 को गांव सिधरावली के पास राष्ट्रीय राज मार्ग पर डैकतों ने पीट-पीट कर एक चालक की हत्या कर दी। 23 नवम्बर, 2002 को करनाल के नगर पार्षद योगेश गाबा के भाई जितेन्द्र गाबा को करनाल के भाडल टाऊन की भीड़ भरी मेन मार्किट में मोटरसाईकल सवार दो लोगों ने मार दिया। 25 नवम्बर, 2002 को रोहतक जिले के गांव डीगाणा निवासी, हलवाई रमेश पुत्र बुधराम की तीन लोगों ने लोहे के सरीयों से मारकर हत्या कर दी। इसी तरह से 28 नवम्बर, 2002 को सोनीपत जिले में गांव ढकेड़ी निवासी, धर्मबीर सिंह पुत्र जिले सिंह की हत्या कर दी। इसी तरह से जींद जिले के अनुपगढ़ निवासी और सोनीपत जिले के गांव नहराड़ा के सात व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। सोनीपत जिले के गांव नारायणा निवासी, कमल हसन पुत्र रफूदीन की हत्या कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसा रिकार्ड है अगर इसको मैं सारा पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जायेगा। यह तो मैं आपको मिसाल बता रहा हूं कि इतने बुरे हाल आज ला एंड आर्डर के हरियाणा में हो गये हैं। आज के दिन हरियाणा में फिरौती, डकैती और

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[चौधरी भजन लाल]

चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। आम नागरिकों को टैलीफोन पर डकैती और चोरी की धमकियां मिल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आगे बताता हूं कि इनके शासनकाल के दौरान और कितनी घटनाएं लूटपाट, डकैती और चोरी की हुईं। इससे पता लग जायेगा कि इनके शासनकाल में घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई है। 1 नवम्बर, 2002 को करनाल निवासी श्री श्रवण कुमार आढ़ती से जनता ग्रेन मार्किट से सशस्त्र लुटेरों ने चार लाख रुपये लूट लिए। 2 नवम्बर, 2002 को कस्बा मुलाना के विजय शर्मा नाम के व्यक्ति के घर से एक लाख रुपये की कीमत के जेवर चुरा लिए गये। 5 नवम्बर, 2002 को करनाल जिले के कस्बा घरौंडा में अज्ञात चोरों ने एक ट्रक से डेढ़ लाख रुपये की कीमत की जीरी चुरा ली। इसी दिन जिला कैथल में गांव हाबड़ी स्थित सहकारी बैंक से अज्ञात चोरों ने बैंक की अलमारी का ताला तोड़कर 64940 रुपये चुरा लिए। इसी तरह की नवम्बर के महीने में 20 वारदातें हुई हैं जिनका पूरा रिकार्ड मेरे पास है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी को यह बताना चाहूंगा कि यह इनका नैतिक अधिकार नहीं है कि ये कानून व्यवस्था पर बात करें। (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि इनके समय में तो इससे भी ज्यादा घटनाएं हुई थीं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सत्तापक्ष के भाईयों का क्या तरीका है जो मुझे बीच में बगैर किसी बात के टोकते हैं।

श्री अध्यक्ष : रावत साहब, नो-नो, प्लीज आप बैठें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री गोपी चन्द गहलौत, द्वारा

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलौत) : स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। चौधरी भजन लाल जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं बस अफसोस यह है कि अब बीच में हुड्डा साहब आ गये हैं। पहले हम एक साथ बैठते थे। इन्होंने ला एंड आर्डर पर बात करते हुए मेरी तरफ इंगित किया है। मैं गुड़गांव की नुमाईंदगी करता हूं। मैंने पहले भी चौधरी भजन लाल जी को कहा था जब ये बादल साहब के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने गुड़गांव के बारे में चर्चा की है ये बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और दूसरे सदस्य भी यहां बैठे हुए हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी सरकार के समय में 29 लाख रुपये गुड़गांव के सहकारिता बैंक से लूटे गये थे। वे पैसे कहां हैं, किसने लूटे, आज तक भी इसकी खबर नहीं लगी है। अध्यक्ष महोदय, जो मैं यह जिक्र कर रहा हूं यह हमारी सरकार के समय की बात नहीं है और इस तरह की अनेकों घटनाएं मैं गुड़गांव के बारे में पहले की बता सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ला एंड आर्डर के बारे इतना जरूर कहूंगा कि गुड़गांव और फरीदाबाद में अपराधिक घटनाएं घट रही हैं तो इस बात के लिए मैं हरियाणा पुलिस की प्रेज किए बगैर नहीं रह सकता। जो भी इस सरकार की टर्म में लूटपाट, चोरी और डैकेती की घटनाएं हुई हैं वे दिनों-दिन रिकवर भी हुई हैं और यह बात ध्यान रखने वाली है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल
13.00 बजे बेकार है लेकिन जो वारदातें हुई हैं उनके बारे में बता रहा हूं। मैं सारे प्रदेश की बात कर रहा हूं। यह बात केवल गुड़गांव की नहीं है। गुड़गांव में जहां इतना मोटा ताजा आदमी रहता है वहां पर चोरी कैसे हो सकती है। * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो अनपार्लियामेंटरी शब्द हैं, उनको रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी भजन लाल : फिरौती की घटनाएं प्रदेश में अजीब ढंग से हो रही हैं, इसलिए कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। बदमाश पैसा मांगता है, सरकार के संरक्षण की वजह से कि इतना रूपया दो। इतना रूपया न दोगे तो तुम्हें कल तक उठा लेंगे, ऐसा वातावरण प्रदेश में बना हुआ है। मैं एक-एक बात की चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जायेगा। इसी तरह से प्रदेश के अन्दर सूखे की हालत इतनी बुरी है जिसका कोई अन्त नहीं। आज क्या स्थिति है, सूखे की वजह से कहीं अढ़ाई रुपये, कहीं तीन रुपये, कहीं पांच रुपये और कहीं पर दस रुपये मदद के तौर पर दिए जा रहे हैं। (विघ्न) आपके इलाके में बाढ़ आई थी। आपको याद होगा कि जहां-जहां पर उस वक्त फसल भी नहीं बोई गई थी हमने तीन हजार रूपया पर एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया। (विघ्न) कमाल हो गया, क्या मैं गलत कह रहा हूं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, ये किसानों के हितैषी बनते हैं। किसानों का कितना बुरा हाल है। जब से यह सरकार बनी है तब से आधा हरियाणा सूखे की चपेट में है। राजा अच्छा नहीं होगा तो न तो बरसात होगी और न ही अच्छा काम हो सकता है। चौटाला साहब सब के सब को मार कर सोता है कि यह भी मर जायेगा वह भी मर जायेगा तो शायद तू ही रह जायेगा। ऐसा मन में विचार है लेकिन ऐसे विचार से काम चलता नहीं। बड़ा घमण्ड है इनको हर बात का। जहां जाते हैं वहीं घमण्ड की बात करते हैं। कहते हैं कि बीस हजार आदमियों को नौकरी देंगे। ये बीस हजार को हटा तो देंगे बाद में आधे रख लेंगे। ये कहते हैं 15 हजार आदमियों को ये नौकरी देंगे तो यह बता दो कि अब तक कितनों को नौकरी दी है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने समय पर सूखे के लिए भारत सरकार से मदद नहीं मांगी। हरियाणा में सूखे के कारण किसानों को बहुत मुसीबत है लेकिन इन्होंने पैसा नहीं मांगा। ये कहते हैं कि हम नहीं मांगेंगे पैसा। देश के कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह 3 बार हरियाणा में आये, क्या मैं गलत कह रहा हूं। यह बात अखबारों में आयी है। मैं ये बातें ईमानदारी से बोल रहा हूं। श्री अजीत सिंह ने बोला कि हरियाणा की गवर्नमैंट ने एक बार भी कभी दरख्वास्त नहीं दी कि हरियाणा में सूखा है, हमारी मदद की जाये। मांगे बगैर तो मां भी बालक को चूची नहीं देती। आप जानते हो कि जब जब दिक्कत आती है भारत सरकार से आर्थिक मदद मांगनी पड़ती है। यह मैं नहीं कहता कि देश का कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह का बेटा कोई छोटा व्यक्ति नहीं है जो गलत बोले। आप मांग भी न करो, क्योंकि अगर हरियाणा के किसानों को कुछ मिल गया यानि हरियाणा के किसानों के खेत में पानी आ गया तो तुम्हारी चौधर खत्म हो जायेगी। इनके दिमाग में यह वहम है और यह वहम रहेगा, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। पहले तो इन्होंने किसानों को बहकाया कि बिजली के बिल मत दो, फलां बिल मत दो। हमारा राज आयेगा तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[चौधरी भजन लाल]

घासी राम जो इनका बड़ा भाई था और इनका सरोकार था और हमें गालियां देता था और इनकी मदद करता था। आज उसको भी पता लग गया, उसको भी रगड़ा लगा दिया। देओ पकड़ कर के अन्दर। वह बेचारा आज अन्दर पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : यह केस सबज्युडिस है, इसका जिक्र आप न करो।

चौधरी भजन लाल : मैंने तो इतना ही कहा है कि वह अन्दर पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : हां, कोई बात नहीं।

चौधरी भजन लाल : मैंने यह तो नहीं कहा कि उस छोड़ दो। मैंने गलत क्या कहा है। अध्यक्ष महोदय, जो पैसा भारत सरकार से इन्हें लेना चाहिए था ये लेने नहीं गए। ये लेने इसलिए नहीं गए क्योंकि ये किसानों के हितैषी नहीं हैं। अगर ये कोशिश करते तो इनको ज्यादा मदद भारत सरकार से मिल सकती थी। लेकिन वह मदद नहीं ले पाए। इसी तरह से किसानों को फसल का समर्थन मूल्य कितना मिला। कितनी बुरी हालत आज किसानों की हो गई है और ये कहते हैं कि मैंने कोशिश की और उन्होंने कह दिया कि 10/- रुपये बोनस की शक्ल में दे दो। अध्यक्ष महोदय, किसानों को गन्ने का पैसा टाईम पर मिलना चाहिए। (विघ्न) अभी तक किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला और यह सरकार किसानों का हितैषी होने का दम भरती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से डीजल, पैट्रोल, खाद, सीमैंट आदि के भाव कितने बढ़ गए हैं लेकिन यह सरकार इसका कोई जिक्र तक नहीं करती और यह कहते हैं कि प्रधान मन्त्री जी से मिलेंगे। ये उनसे कब मिलेंगे ? भाव बढ़ाने से पहले इनसे पूछना चाहिए कि इतना भाव बढ़ेगा। अव्वल तो यह भाव बढ़ना नहीं चाहिए था और अगर इनसे पूछे बिना बढ़ाया गया है तो भाव बढ़ने के बाद कम से कम इतना तो कर सकते थे कि सपोर्ट वापिस ले लेते। अगर ये सरकार से अपनी सपोर्ट वापिस लेते तो कुछ बात समझ में आती लेकिन इससे ये लोग डरते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक खागड़ होता है। किसी ने पूछा खागड़ से कि छेरे क्यों करता है तो वह कहता है कि गऊ का जाया हूं दुलकता क्यों है, कहता कि खागड़ हूं। ये तो दुलकते हैं दिखाने के लिए वरना तो भारत सरकार से डरते हैं। यह इनका हाल है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये लोग स्वर्गीय देवी लाल जी की प्रशंसा करते हैं। उनकी बड़ी भारी प्रशंसा कर दी जहां जाओ वहीं पर चौधरी देवी लाल का स्मारक, जहां जाओ वहां पर पार्क चौधरी देवी लाल के नाम पर है। क्या चौधरी देवी लाल महात्मा गांधी से बड़े थे ? क्या वे सरदार पटेल से बड़े थे ? जाइये, गुजरात में जा कर देखिए गांधी जी के नाम पर कोई स्मारक नहीं है सिवाय एक आश्रम के। गांधी जी के नाम पर कहीं पर कुछ नहीं है, अगर है तो बता दो। सरदार पटेल के नाम पर कुछ नहीं है, अगर है तो बता दो। हम उनके खिलाफ नहीं हैं लेकिन लोग चर्चा करते हैं। मरने के बाद किसी आदमी के बारे में चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। यह तो इनकी नीयत खराब है, पार्क बना कर बाद में उन पर कब्जा करना चाहते होंगे नहीं तो पार्क के कोई मायने नहीं हैं। इतने पार्क और स्मारक बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार फेल होने के कगार पर है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी जब जवाब देंगे तो बता दें। बिजली बोर्ड ने कितना लोन ले रखा है और कितना कर्जा बिजली बोर्ड के सिर पर है ? सड़कों के लिए कर्जा स्टेट गवर्नमैंट ने ले रखा है। स्माल सेविंग, मार्कीटिंग बोर्ड, भारत सरकार का जनरल प्रॉविडैंट

फण्ड और अन्य जितने भी इन्स्टीच्यूशन्ज हैं उनसे आपने कितना लोन ले रखा है ? सरकार के ऊपर कितना कर्जा है ? सरकार दिवालिया होने को तैयार हो रही है। जो बॉण्ड सरकार ने लिये हैं वे 12-13% के इन्ट्रस्ट पर बॉण्ड की शक्ल में कर्जा लिया है। आजकल आम लोन 8-9% के ब्याज पर मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब कोई दिवालिया होता है तो वह फालतू ब्याज दे कर लोन लेता है। यह रिकार्ड की बात है मुख्यमन्त्री जी जब जवाब दें तो वे इस बारे में बता दें कि आज के दिन हरियाणा पर कितना कर्जा है और किस तरह से उस कर्ज को उतारेंगे। कर्मचारियों के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कितने ही कर्मचारी हैं जो बेकार होने को तैयार बैठे हैं। कभी ये कहते हैं कि अध्यापकों का रैशनेलाईजेशन करेंगे। (विघ्न) और इन्होंने यह फैसला कर दिया कि 60 विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा। (विघ्न) मैं यह कह रहा था कि ये कहते हैं कि हम कर्मचारियों का रैशनेलाईजेशन करेंगे। ये कर्मचारियों की संख्या घटाना चाहते हैं। 60 विद्यार्थियों पर एक मास्टर होगा पहले 40 पर एक टीचर था अब 60 विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा। अगर 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर करते तो बात कुछ समझ आती लेकिन अब 60 विद्यार्थियों पर एक टीचर करेंगे तो ऐजुकेशन क्या रहेगी इस बारे में इनको सोचना चाहिए। ये कुछ लोगों को निकालना चाहते हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं है। आज हरियाणा में कर्मचारियों और अधिकारियों की स्थिति ठीक नहीं है। ये बोर्डज़ और कारपोरेशंज से कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, 1600 पुलिस कर्मी इनकी जान को रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने उनको निकाल दिया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, वे आपकी जान को रो रहे हैं क्योंकि आपने उनको लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इसलिए हटाने के लिए यह फैसला दिया था क्योंकि वे सारे के सारे गलत ढंग से व उनमें से कई तो पैसे लेकर लगाए गए थे।

चौधरी भजन लाल : अगर आप यह प्रूव कर दें या कोई यह कह दे कि भजन लाल ने उस भर्ती में पैसा लिया था तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, आपके अगल बगल में बैठने वालों ने आपको राजनीति से इस्तीफा दिलवाने का फैसला कर लिया है।

चौधरी भजन लाल : ओम प्रकाश जी मैंने आपका अगल, बगल तो क्या पीछा भी देख रखा है और रगड़ भी रखा है। जो भजन लाल के हत्थे एक बार चढ़ जाए क्या वह बच सकता है। (विघ्न) मैं आपके लिए कह रहा हूं इनको नहीं कह रहा हूं। (विघ्न) (हंसी) अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ये कहते हैं कि हम हरियाणा में इन्डस्ट्रीज़ को विदेशों से ला रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में जो इन्डस्ट्रीज हैं वे ही छोड़ कर जा रही हैं और क्या इन्डस्ट्रीज आएंगी (विघ्न) महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख 54 हजार आदमियों को नौकरियां दी हैं। हरियाणा में नए उद्योग लगाए, अध्यक्ष महोदय, कोई नया उद्योग नहीं लगाया है। अगर कोई उद्योग लगाने आता है तो उसको पूछते हैं कि कितने का लगाएगा तो वह कहता है कि 100 करोड़ रुपये का, तो ये उसको कहते हैं कि 1 करोड़ रुपये यहां पर रख दे। अध्यक्ष महोदय, उद्योग अभी लगा नहीं और पैसे पहले ही मांगने लग गए तो वह आदमी यहां पर क्यों उद्योग लगाएगा। इसके अलावा "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में यह क्या करते हैं। ये इस प्रोग्राम के तहत घर-घर जाकर देखते हैं कि किसके पास क्या है, कितना सामान है और कैसा कैसा समान है और वहां से क्या क्या मिल सकता है। इन्होंने तो ब्रेक फास्ट, लन्च, शाम की चाय, शराब

[चौधरी भजन लाल]

और डिनर के अलग अलग रेट फिक्स कर रखे हैं। इस बारे में अब लोग समझ चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब इनको अपने घर नहीं बुलाएंगे। इससे अच्छा तो वे भैंस गाए ही खरीद लेंगे, वह कुछ तो देगी। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र चौधरी के फंड के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है कि उसका क्या हुआ। इनको बताना चाहिए था कि महेन्द्र चौधरी फंड में इतना पैसा इक्ट्ठा हुआ है, इतना दे दिया और इतना बाकी है। इनको उस बारे में कुछ तो बताना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकद्दमे बना रहे हैं। आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जब आप यहां पर बैठेंगे और मैं वहां पर बैठूंगा तब पता चलेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपकी तीन महीने वाली बात गई, उसका क्या हुआ। जब आप सोनिया को बहकाकर आए थे।

चौधरी भजन लाल : यह तो आपको पता चल जाएगा एक साल ही रह गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : एक साल कोई नहीं लड्डू बरगे दो साल हैं, अभी बाकी आगे भी और पांच साल लेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में बहुत बुरे हालात हैं। अपनी बेटी अपना धन स्कीम थी, वह बंद कर दी गई है। दुलिना कांड हुआ और भी कई घटनाएं हुईं। आज प्रदेश के लोग इनसे बहुत परेशान हैं। मैं तो इनको यह कहना चाहूंगा की राज तो सदा किसी का रहना नहीं, परमात्मा को याद रखो। आपका राज तो अब रहना नहीं इसलिए परमात्मा को याद रखो ताकि परमात्मा के पास जगह मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ . . . . (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप साथ साथ अभिभाषण का समर्थन भी करो न।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने बहुत दुख के साथ, बड़े ही भारी मन से इस अभिभाषण को पढ़ा। मैं इसका विरोध करता हूं। (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे तो अब 15 मिनट ही रह गये हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कल जो सारे सदन के सामने सरकार का असत्य से भरा लेखा जोखा पढ़ा, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। पिछले एक वर्ष से हरियाणा प्रदेश की जनता का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। अध्यक्ष महोदय, महामहिम ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा है उसमें सबसे पहले उन्होंने एस०वाई०एल० कैनाल की बात कही है। काफी देर से लगातार सी०एम० साहब जी यह कह रहे थे कि 24 जुलाई, 1985 को जो राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ था उस पर किसके हस्ताक्षर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि 24 जुलाई, 1985 को जो राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ था क्या उसको हरियाणा सरकार मानती है या नहीं मानती है ? क्योंकि इस बात को लेकर बड़ा भारी झगड़ा है। इस समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर मोहर लगायी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे अपने भाषण में यह जरूर बताएं कि क्या राजीव-लौंगोवाल समझौते को यह सरकार मानती है या नहीं क्योंकि यह समझौता जो हुआ था वह केन्द्र की सरकार

ने उसी तरीके से करवाया था जिस तरीके से अब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने करवाया है। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० का जो मामला है वह केवल खुदाई का नहीं है। हम चाहते हैं कि यह बताया जाए कि 1972 से लेकर 1978 तक और 1978 से लेकर आज तक रावी व्यास का जो पानी है वह किस जिले में कितना कितना चल रहा है क्योंकि हमारे जिले के खिलाफ इस बारे में बार बार यहां पर चर्चा की जाती है। कैथल के इलाके में, कलायत के इलाके में, नरवाना के इलाके में या जींद के इलाके में, पानी कितना कितना चल रहा है। क्या सरकार यह भी बताएगी कि इसका बंटवारा किस किस हिसाब से हो रहा है। सरकार बताए कि कैथल के इलाके में, कलायत के इलाके में, नरवाना के इलाके में, सिरसा के इलाके में, हिसार के इलाके में एवं अहीरवाल के इलाके में और दक्षिणी हरियाणा के इलाके में कितना-कितना पानी दिया जा रहा है, यह बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात को लेकर, एस०वाई०एल० को लेकर कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस समय की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कपूरी के अंदर नहर की खुदाई का काम कांग्रेस की सरकार ने शुरू करवाया तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह खुदाई का काम बंद कब हुआ था ? देश की लोकसभा में इस बात का रिकार्ड है। माननीय श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी पंजाब में उस समय मुख्य मंत्री थे और सबसे ज्यादा नहर की खुदाई उस समय में हुई थी और वह कांग्रेस के राज में हुई थी। (विघ्न) 1987 में यह काम रुका था उस समय चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी उस समय मैं उनके साथ था और उस समय मुझसे यह गलती हो गई थी इसीलिए मैं यहां बैठा हूं। 1987 के बाद यह समझौता नहीं माना गया और उस समय की केन्द्र सरकार ने और पंजाब सरकार ने कहा कि ये लोग मानते ही नहीं हैं। उस समय काम बंद होने के बाद आज तक नहर की खुदाई का काम नहीं हुआ। इस सरकार ने साढ़े तीन वर्षों में कुछ नहीं किया। दीप जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और दीप जलाते जलाते हिसार में एक माननीय विधायक मेरे चाचा जी की पिटाई हो गई यह क्या सरकार है ? अगर आज तक पानी दिलाने का काम किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने किया है, लौंगोवाल जो शहीद हुए, उन्होंने किया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। न आज किया न कभी किया बल्कि काम रुकवाया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बारे में फैसला किया है, ये किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं। बार बार यह चर्चा चली कि कांग्रेस अध्यक्षा के यहां धरना देना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्षा के यहां धरना नहीं देना चाहिए था। केन्द्र सरकार के यहां धरना देना चाहिए था जिनकी केन्द्र में सरकार है उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने, क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि नहर की खुदाई का काम इतना आसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र की सरकार यह कह रही है उस पार्टी का अध्यक्ष यह कह रहा है कि नहर की खुदाई का काम इतना आसान नहीं है तो इससे ज्यादा और क्या बात होगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप लोग जो पंजाब सरकार के खिलाफ बार बार कह रहे हैं, क्या आपने पंजाब के मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई कंटैम्प्ट दायर की है अगर की है तो बताएं ताकि प्रदेश के लोगों को पता लगे। जब 15 जनवरी, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और राजीव लौंगोवाल एकोर्ड को माना और पंजाब सरकार से कहा कि नहर की खुदाई का काम करे तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उस वक्त पंजाब में मुख्य मंत्री कौन थे और वे कब तक थे यानि कि एक दोस्ती के नाते हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात किया गया है वह सामने जो सत्तापक्ष में बैठे हैं उनके द्वारा किया गया है। यह कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं हुआ वह इन लोगों

[चौधरी जय प्रकाश]

की वजह से हुआ है। कांग्रेस पार्टी आज भी पानी दिलाना चाहती है और कल फिर सत्ता में आई तो पानी मिलेगा अगर कांग्रेस नहीं आई तो पानी नहीं मिलेगा। अभी 2 मार्च को जिस व्यक्ति ने हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात किया उसको रोहतक में मंच के ऊपर बैठाया। ऐसे लोगों को मंच पर ले जाया जा रहा है जो हमें पानी नहीं दे रहे हैं। कई भाई कह देते हैं कि फैसला बहुत बढ़िया हुआ है। इस प्रकार ये लोग हार को भी जीत मानकर के मनाना चाहते हैं जनता इस बात को कभी भी नहीं मानेगी।

अब मैं कृषि के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। कृषि के बारे में दो माननीय सदस्य बड़ा कुछ कह रहे थे। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में गन्ने की प्रिक्योरमैंट कितनी हुई है और इस वर्ष आज की तारीख तक गन्ने की प्रिक्योरमैंट कितनी हुई है इस बारे में मिलों से पता लगाएं। हरियाणा प्रदेश में यमुनानगर का जो इलाका है वहां लाचार होकर के सरकार के निकम्मेपन की वजह से वहां के किसानों ने गन्ने की होली जलाई। किसानों का गन्ना 60-60 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लूटा जा रहा है। क्या सरकार आश्वस्त करेगी कि किसानों का गन्ना अच्छे भाव से लिया जाएगा और जो किसानों के साथ लूट हो रही है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। सरकार यह कह देती है कि कोऑपरेटिव मिल के दायरे में जो मिलें हैं उनमें पूरा दाम दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी बड़ी बेईमानी है। जीन्द के अन्दर जैसे एक पर्ची आती है 60 क्विंटल गन्ने की। कई बार किसान का 62-63 क्विंटल गन्ना चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार पता कराये कि जिन किसानों का जो ज्यादा गन्ना चला जाता है उस गन्ने की पेमैंट नहीं मिलती और वह गन्ना मिल में डलवा लिया जाता है। फिर सरकार कह रही है कि गन्ने के बढ़े भाव दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, जीन्द के इलाके से लेकर, रोहतक, सोनीपत से लेकर और अम्बाला के इलाके से होकर पंजाब में गन्ना जाता है और ये हिसाब लगायें कि कितना गन्ना प्रदेश से बाहर जा रहा है। यदि हरियाणा का गन्ना पंजाब में जाता है तो इसका मतलब हरियाणा प्रदेश की सरकार किसानों के गन्ने को लेने में राजी नहीं है, खुश नहीं है। मिल की क्रशिंग बहुत स्लो कर दी गई है। किसान बेबस होकर गन्ने को पंजाब और उत्तरप्रदेश में सस्ते भाव में देने को मजबूर है। (विघ्न) मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे 87 रुपये प्रति क्विंटल के दाम यमुनानगर की मिल में किसानों को दिए गये हैं, क्या जो बाकी का बैलेंस है, क्या हरियाणा की सरकार किसानों को देगी ? कहते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि पर आधारित है और ये किसानों की हमदर्द सरकार है लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश के शान्तिप्रिय किसानों को कंडेला, धुसकन और नगूरा में गोलियों से भुनवा करके उन किसानों को कहा कि ये असामाजिक तत्व हैं। इतना ही नहीं जब किसानों का दवाब आया तो किसानों की सरकार ने कहा कि ये तो कुछ लोगों के बहकावे में आ गये थे और ये तो पुलिस की गोली से मरे हैं। यह क्या सरकार है ?

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, वाईड अप कीजिए।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आपने आधा घण्टा बोलने के लिए कहा था, अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। यानी किस बात की सरकार है ये। 9 किसानों को गोलियों से मारा। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जहां किसानों को गोलियों से भूना गया। अध्यक्ष महोदय, गेहूं का सीजन चल रहा था तथा मुख्य मंत्री के और कृषि मंत्री के बार-बार ब्यान आ रहे थे कि अगले वर्ष गेहूं मत

बीजना सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी। इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज 4 रुपये किलो तूड़ी बिक रही है। लोगों ने सोचा था कि सरकार गेहूं खरीदेगी इसलिए फटाफट कम्बाईन से हारवैस्टिंग करा दी। आज गेहूं के भाव बढ़ गये व तूड़े के भाव बढ़ गये। (विघ्न) किसानों को मिल तो रहा है जो मोल ले रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई पोलिसी आई है क्या ? अध्यक्ष महोदय, कभी सरकार कहती है कि गेहूं ज्यादा हुआ है और आज की सरकार के गोदामों में गेहूं नहीं है। पहले कहती है कि गेहूं नहीं बीजना, अब कहती है कि अगले वर्ष गन्ना नहीं बीजना, गन्ना नहीं खरीदा जायेगा। ये किसानों की हमदर्द सरकार है। आज बिजली के दामों को ले लीजिए। कई भाई इस बारे में प्रचार करते हैं। जैसे रामपाल माजरा चीफ पार्लियामेंटरी सचिव जी कह रहे थे कि बिजली का इतना काम कर दिया। मैं चीफ मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1999 में जब यह सरकार आई उस वक्त बिजली के दाम क्या थे और आज बिजली के दाम क्या हैं ? उस वक्त किसानों के ट्यूबवैल्ज को कितनी बिजली मिलती थी और आज कितनी मिलती है ? यानी कि एक बात कहूं कि चन्द शहरों में दीपक की तरह जलती है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की हरियाणा में यह हालत है कि 15-15 दिन तक गांवों में बिजली नहीं आती और जब आती है तो बल्ब नहीं जलते वे टिमटिमाते हैं। बिजली नाम की चीज नहीं है। बिजली इतनी मंहगी है कि आम आदमी बिजली के कनेक्शन लेने ही बन्द कर देंगे और फिर सरकार का ब्यान आता है कि अगले वर्ष हम बिजली सरप्लस कर देंगे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ० जय प्रकाश : बिजली की हालत बहुत खराब है। जहां तक नहरों में पानी की बात है। ये समान बंटवारे का नारा लगाते हैं। जो दक्षिणी हरियाणा के लोग हैं लेकिन उनकी बात को मैं वाजिब मानता हूं। जिस दिन से यह सरकार सत्ता में आई है हमारे बरवाला में 35 दिन के बाद रजबाहे आते हैं। किसानों के लिए पानी नहीं है, किसानों के ट्यूबवैल्ज को बिजली नहीं है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की सरकार विकास दिवस मना रही है रोहतक में। इसी वजह से लोग रोहतक की बजाये झज्जर की ओर चले गये यही कारण था कि लोग इनकी रैली में नहीं पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात है शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से पिछले दो वर्ष से हम लगातार एक बात सुन रहे हैं कि 'विकास रोजगारोन्मुखी शिक्षा'। लेकिन इनकी शिक्षा विकास रोजगारोन्मुखी शिक्षा नहीं है। जिस दिन से यह सरकार आई है उस दिन से हरियाणा के क्लास-3 और क्लास-4 कर्मचारियों में यह भय है कि उनको यह सरकार नौकरी में रखेगी भी या नहीं। क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे कारपोरेशन चल रहे थे उनको इस सरकार ने तोड़ दिया और यह कह दिया कि ये घाटे में चल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार सोशल वैलफेयर के बारे में

[चौ० जय प्रकाश]

नफे-नुक्सान की बात करेगी तो वह सरकार जनता की भलाई नहीं कर सकती। पूरी दुनियां में शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त मिलती है जबकि हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा और चिकित्सा दोनों महंगे हैं। आज हरियाणा के अंदर सभी सरकारी हस्पतालों में पांच रुपये पर्ची बनवाने के लिये लिए जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब पांच रुपये की पर्ची होगी और दो रुपये की दवाई मिलेगी तो कौन जायेगा सरकारी हस्पतालों में। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकारी हस्पतालों पर करोड़ों रुपये लगे हुए हैं, आज उनमें कितने लोग ईलाज के लिए जाते हैं और प्राईवेट क्लिनिकों में कितने लोग ईलाज के लिए जाते हैं यह बताया जाये। इस बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि हरियाणा सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना चिंतन और मंथन कर रही है। आज हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को अनपढ़ बनाने में लगी हुई है। जो रैशनलाईजेशन की पालिसी है वह गलत है उसे पूरी तरह से लागू न करके सरकार ने ठीक काम किया। पहले एक अध्यापक 40 बच्चों के लिए होता था जबकि मौजूदा सरकार ने एक अध्यापक 60 बच्चों पर कर दिया यह बहुत गलत किया गया है। एक अध्यापक 60 बच्चों का एक साल तक नाम भी नहीं जान सकता। अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि ये बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। इन्फार्मेशन टैक्नालोजी-इन्फार्मेशन टैक्नालोजी हर जगह लिखा हुआ आज हम देखते हैं। रोटी खाने के ढाबे पर भी लिखा होता है इन्फार्मेशन टैक्नालोजी। लेकिन आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह इन्फार्मेशन टैक्नालोजी कहां है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं आज हरियाणा के अंदर कितने स्कूलों में कितने बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है और प्राईवेट सैंटरों में कितने बच्चे कम्प्यूटर शिक्षा सीख रहे हैं ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर की जो फीस है वह प्राईवेट सैंटरों से भी अधिक है और यही कारण है कि स्कूल में कम बच्चे कम्प्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं। प्राईवेट कम्प्यूटर सैंटर चाहे वे टाटा के हैं या रिलायंस के हैं उनमें कम्प्यूटर की फीस कम है और अच्छी शिक्षा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, कई गांवों की पंचायतों ने विवश होकर सरकारी स्कूलों में ताले लगा दिए हैं और हरियाणा सरकार कह रही है कि रोजगारोनुमुखी शिक्षा योजना से ये शिक्षा दे रहे हैं तथा इससे 75 हजार लोगों को रोजगार दिया जायेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 75 हजार लोगों को रोजगार दिया जायेगा दूसरी ओर सरकार ने 25 हजार कर्मचारियों की छंटनी कर दी।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी प्लीज अब आप बैठें।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट का समय और दें। अब मैं ला एंड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि क्राईम और क्रिमिनल वक्त-वक्त और परिस्थितियों के अनुसार बढ़ते-घटते रहते हैं। लेकिन कुछ क्राईम जो कहीं न कहीं अटैचमैंट से होते हैं उनकी अब बढ़ोतरी हुई है। इस बारे में सरकार से कहना चाहूंगा एक बार मैं पटना गया था वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक प्रैस कांफ्रैंस में कहा कि वे बिहार को क्राईम के मामले में हरियाणा नहीं बनने देंगे। यह बहुत शर्म की बात है कि बिहार वाले हमारे प्रदेश के बारे में ऐसी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में आज ला एंड आर्डर की ऐसी स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी अब आप बैठें। अब राव इन्द्रजीत जी बोलेंगे।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब समय कम है मैं कल बोलूंगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि सड़कें बनी हैं, मेरे हल्के में भी सड़कें बनाई गई हैं। लेकिन इसमें मेरा एक ऑब्जैक्शन है कि यदि कोई आदमी कर्जा लेकर के अपना ड्राइंग रूम बनाए तो वह घर कभी बस नहीं सकता। इतनी भारी मात्रा में लोन लेकर के जो सड़कें बनायी हैं, उन सड़कों पर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं। मैं ऐसी सड़क का नाम बताना चाहता हूं कि जहां पर ऐसे ही किसी ठेकेदार द्वारा काम किया गया है। रोहतक से लेकर नरवाना जीन्द तक जो नेशनल हाई वे नं० 73 की सड़क है यह आधे से ज्यादा कम्पलीट हो गई थी। अब उसको जाकर देखोगे तो उसकी पहले से भी खराब हालत है। इस तरह से ठीक काम न करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनकी जांच की जाये। ये सड़कें बार बार क्यों टूट रही हैं ? इन सड़कों को बनाये जाने का क्या क्राइटेरिया है। सरकार जो ठेके देती है यह उन लोगों को दिए जाते हैं जो सरकार के चहेते होते हैं। जो प्रोफैशनल ठेकेदार होते हैं उनको ठेके नहीं दिए जाते।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये।

चौ० जय प्रकाश : मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा। * * * * * *

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आप बगैर परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं होगी।

चौ० जय प्रकाश : स्पीकर साहब, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : राव इन्द्रजीत सिंह जी, अब आप बोलें।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, आप मुझे बोलने के लिए अन्दाजन कितना समय देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैम्बर्ज की संख्या के हिसाब से आपके छः मिनट बनते हैं। यदि आप ज्यादा समय लेंगे तो आपकी पार्टी के समय में से वह समय काट दिया जायेगा। (शोर एवं विघ्न)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, मैंने तो सिर्फ अन्दाजा ही पूछा है कि कितना समय आप मुझे बोलने के लिए देंगे।

श्री अध्यक्ष : पार्टी मैम्बर के हिसाब से हर मैम्बर को छः मिनट का समय बैठता है। आप पहले बोलना शुरु तो करें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : राव इन्द्रजीत सिंह जी आप स्पीकर पर समय की पाबन्दी नहीं लगा सकते।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब से मैं यह तो पूछ सकता हूं कि कितना समय मुझे अन्दाजन दिया जायेगा। इसके अन्दर आपको क्या आपत्ति है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : राव साहब आप तो सीजन्ड पोलिटिशयन हो। आप काफी समय से सदन में रहे हो।

राव इन्द्रजीत सिंह : अगर मैं सीजन्ड न होता तो फिर पूछता ही क्यों।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप बोलना शुरु करिए। यह स्पीकर साहब का अधिकार है, वह देखेंगे कि आपको कितना समय देंगे। ये देखेंगे कि इसमें आप क्या गैर जरूरी बात करते हो।

श्री अध्यक्ष : राव साहब आप कन्टीन्यू करें।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आप पहले इनकी बात तो सुनें।

राव इन्द्रजीत सिंह : मैं पूछ तो सकता हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब पर आप समय की पाबंदी करने के हकदार नहीं हैं।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, * * * *

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी ने जो कहा है वह रिकार्ड न किया जाये।

राव इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना) : स्पीकर सर, मैं गवर्नर महोदय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान एस०वाई०एल० का जिक्र किया। पिछले साल इन्हीं दिनों में बजट पेश किया गया था और जब चौधरी सम्पत सिंह जी बजट पेश कर रहे थे मैंने चश्मा लगा कर देखा कि कहीं पर एस०वाई०एल० का जिकर हो लेकिन एस०वाई०एल० का जिकर बजट में पिछले साल के दौरान नहीं हुआ। इस साल गवर्नर साहब ने कहा कि सरकार एस०वाई०एल० बनाना चाहती है और हमारा अधिकार है एस०वाई०एल० के पानी के ऊपर। स्पीकर सर, मैं मोटे मोटे तौर पर इस बात से सहमत हूं। हमारा अधिकार इस पानी के ऊपर है और इस सदन की जानकारी के लिए मैं इसकी कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूं। सबसे पहला समझौता जो प्रान्तों के बीच में हुआ एस०वाई०एल० के पानी के विषय में हुआ वह सन् 1955 के अन्दर हुआ। उस वक्त हरियाणा पंजाब का एक हिस्सा था। पंजाब, जे० एण्ड के० और राजस्थान के बीच में यह फैसला हुआ कि रावी ब्यास का पानी आज के दिन पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान से निकल कर अरब की खाड़ी के अन्दर जा रहा है। जब हिन्दुस्तान इस पानी को खरीदेगा तो इन तीन प्रान्तों का किस मात्रा के अनुसार हिस्सा होगा। उस टाईम राजस्थान का 8 एम०ए०एफ० हिस्सा दिखाया

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

गया था और पंजाब, जिसके अन्दर हरियाणा भी शामिल था, का 7.20 एम०ए०एफ० दिखाया गया था और इसी तरह से जे० एण्ड के० का भी कुछ हिस्सा दिखाया गया था। लेकिन जो सोचने की बात है वह यह है कि पंजाब को 7.20 एम०ए०एफ० मिला लेकिन इसके अतिरिक्त 1.3 एम०ए०एफ० पानी पैप्सू को भी मिला, जहां की नुमायंदगी मैं आज कर रहा हूं। 1.3 एम०ए०एफ० पानी पैप्सू को अलग से मिला था (विघ्न) सबसे पहले उस पानी पर हमारा अधिकार सन् 1955 के फैसले के अनुसार स्थापित हुआ। उसके बाद सन 1960 के अन्दर अयूब खान और श्री जवाहर लाल नेहरू जी के बीच इसके बारे में फैसला हुआ कि सन् 1970 के बाद जब हिन्दुस्तान पैसा पाकिस्तान को दे देगा और पानी खरीद लेगा तो सन 1970 से यह पानी हिन्दुस्तान के लिए होगा। तीसरा फैसला जो इस विषय पर हुआ वह सन 1976 में इन्दिरा गांधी जी के समय में हुआ जिसके तहत 3.5 हरियाणा को मिला और 3.5 पंजाब को मिला। चौथा फैसला इस विषय पर तीन मुख्य मन्त्रियों का हुआ जिसके अन्दर चौधरी भजन लाल जी का भी जिक्र था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच यह फैसला था। उसके अन्दर कांस्टीच्यूशनल तौर पर तीनों स्टेटों के मुख्य मन्त्रियों के उस पर हस्ताक्षर हुए और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसको रैटिफाई किया। क्योंकि उस समय मेरे बाउजी केन्द्र के अन्दर इरीगेशन मन्त्री थी इसलिए इसके बारे में कुछ ज्ञान मुझे भी है। इस विषय में मैं जो कहना चाहता था वह आज मैं नहीं कहूंगा लेकिन यह कहूंगा कि हरियाणा को 3.5 एम०ए०एफ० पानी दिया गया था। उसके बाद सन 1985 में राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ और उसके तहत इराडी ट्राईब्यूनल बना। जिसके माध्यम से 3.83 एम०ए०एफ० जैसे कि आप कह रहे थे, हमें मिला। उसके बाद सन 2002 के अन्दर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि पंजाब एक साल के भीतर-भीतर नहर बनाने का काम करे और पंजाब अगर न बनाए तो केन्द्र सरकार उसके बाद इस काम को करेगी। इस फैसले के अन्दर पहले ही यह नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार शायद पंजाब सरकार उसके ऊपर अमल नहीं करेगी और यदि पंजाब इस फैसले को नहीं मानता तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा निर्धारित नहीं की थी इसलिए पंजाब आराम से उस फैसले को टाल सकता था। आज के दिन केन्द्र के खेमे के अन्दर गेन्द है। सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट के मुताबिक आज भी हम केन्द्र को पाबन्द नहीं कर सके कि किस तरह से इस पानी को लाने के लिए वे व्यवस्था करेंगे या इस नहर को बनाएंगे। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह याचिका डाल कर या केन्द्र के पास अपील करके यह तय करती कि केन्द्र कितने साल में या कितने महीनें में इस पानी को हमारे प्रदेश के लिए उपलब्ध करवा सकेगा। स्पीकर सर, हैरत की बात यह है कि 5-6 फैसले जो मैंने आपको गिनाए पिछले 45-50 वर्षों के दौरान हो चुके हैं और हर फैसले में हरियाणा का हक माना गया है, अधिकार माना गया है लेकिन आज के दिन भी हम वही बात सुन रहे हैं जो कि आज से 50 वर्ष पहले हमारे बाबा जी ने सुनी थी या हमने पौलिटिक्स में दाखिला लिया था तब सुनी थी। इस समय को 30 वर्ष हो गए हैं और हमारे सिर के बाल भी सफेद हो गए हैं लेकिन रावी-ब्यास का पानी हमें आज तक नहीं मिला है। रावी-ब्यास का पानी हरियाणा में आया कब ? अगर मैं गलत नहीं हूं तो सन 1960 के फैसले के बाद हिन्दुस्तान को यह पानी मिला और हरियाणा की सरहद के अन्दर यह पानी सन 1977-78 में आना शुरु हुआ है। यह पानी हरियाणा का क्यों नहीं है क्योंकि यह रिपेरियन स्टेट नहीं है। जब पंजाबी सूबा बनने की बात आई तो यह कहा गया था कि हिन्दी भाषी और पंजाबी भाषी अलग अलग क्षेत्र हैं। उसके अन्दर जो डिवैल्पमैंट होगी वह इस आधार पर होगी। जो पंजाबी भाषी हैं उनमें इतना पानी दिया जाएगा और जो हिन्दी भाषी हैं उनमें इतना पानी

[राव इन्द्रजीत सिंह]

दिया जाएगा। अनफारच्युनेटली एक तीसरी बात उस पंजाब रि-आरगेनाईजेशन ऐक्ट के अन्दर हुई जिसके बारे में आप सबको ज्ञान होना चाहिए कि उसमें टोपोग्राफी को भी शामिल कर लिया गया। जो क्षेत्र आज के दिन हिमाचल प्रदेश के कहलाए जाते हैं उनका एक अलग स्थान बना दिया गया था। हरियाणा ने अलग सूबा नहीं मांगा था पंजाब ने अलग सूबा मांगा था। अगर उस हिसाब से जैसा पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली जगह बांटी गई थी, स्थान बांट दिए गए थे कि जितने पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं, हिन्दी स्पीकिंग एरियाज़ वे अलग अलग बांट दिए गए थे। तो हिमाचल का जो एरिया था वह हरियाणा के पास आना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो यह बात हमेशा के लिए खत्म हो जाती कि यह रिपेरियन स्टेट नहीं है क्योंकि सारे का सारा पानी हिमाचल से बहकर सारे प्रदेश में आ रहा है। स्पीकर महोदय, अनफारच्युनेटली यह नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इतने फैसलों के बावजूद जो हमारा पानी हमें नहीं मिल रहा है उसमें मुझे शुभा है। शुभा इस बात का है कि पानी देने की कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। वे यह कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को ऐसे ही चलने दिया जाए, सारी बात को बतंगड़ बना दिया जाए। 25 साल से बतंगड़ बना करके यह कह कह कर के हम यह बात करते आ रहे हैं। एक मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि पानी हम लेंगे दूसरे मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि पानी हम लेकर के आएंगे और तीसरे मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि नहीं हम पानी लेकर आएंगे। इसी तरह से पंजाब के मुख्य मन्त्री कहते हैं कि हम पानी बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरे मुख्य मंत्री जी चाहे वे पगड़ी बदल भाई बादल साहब हों, कहते हैं कि हम पानी नहीं जाने देंगे और तीसरा मुख्य मंत्री कहता है कि पानी हम नहीं जाने देंगे। क्या आपको यह कान्सपीरेसी नजर नहीं आती है कि इस तरह से खुद को सत्तासीन करने के वास्ते ये कर रहे हैं। लोगों के लिए जहां पर यह पानी पहुंचना है और जो एंड यूजर हैं उनको वंचित रख कर और खुद को कुर्सी पर स्थाई तौर पर स्थापित करने के लिए एक कान्सपीरेसी रच रहे हैं। इस कान्सपीरेसी को मैं आज आप सबके सामने सदन में रखना चाहता हूं कि इस बारे में विचार किया जाए। हम बहुत दिनों से पानी के आने का इन्तजार कर रहे हैं कि यह पानी हमारे पास आए। (शोर एवं व्यवधान) यह बात सबको पता है और सरकार इसका जवाब दे। लेकिन 1.8 MAF पानी आज के दिन हरियाणा को उपलब्ध है। (विघ्न) पंजाब में मेरी पार्टी से सम्बन्धित मुख्य मंत्री तो कह रहे हैं कि हम पानी नहीं देंगे। लेकिन हम यहां पर यह कह रहे हैं हम पानी लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहां पर जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि पिछले कुछ वर्षों से यह एक मुद्दे की लड़ाई बन गई है। पंजाब कहता है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम पानी लेकर के रहेंगे। लेकिन इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं करता है। (विघ्न) वे तो आपकी पार्टी के पगड़ी बदल भाई थे वे चले गए। (विघ्न) मैं कह चुका हूं कि ये साजिश थी। ये साजिश थी कि हमको इस पानी से वंचित रखा गया है। आज स्थिति क्या है जिस क्षेत्र के अन्दर टिब्बे थे, जहां पर रेत उड़ा करती थी आज के दिन वहां पर अगर किसी किसान को मुआवजा दिया जाता है तो वह 12 हजार, 15 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। लेकिन झज्जर, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ के क्षेत्रों के अन्दर जहां पर साहिबी नदी आया करती थी, बाढ़ आया करती थी और जब कृष्णा और दोहान नारनौल के अन्दर आया करती थी आज उस क्षेत्र के अन्दर मुआवजा दिया जाता है प्रति एकड़ केवल 400 रुपये। पिछले सैशन के दौरान मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमारे इलाके में कहर नहीं पड़ रहा है, हमारे यहां नुक्सान नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जहां पर फसल नजर नहीं आ रही हो वहां पर ये कहें कि नुक्सान नहीं हुआ है तो क्या कहा जा

सकता है। यह फसल इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग अमूमन मधवाड़ छोड़ देते हैं। स्पीकर सर, मधवाड़ इसलिए छोड़ देते हैं कि फसल अच्छी हो जाए। मुख्य मंत्री जी अभी यहां पर बैठे नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों के अंदर बरसात न होने की वजह से सरसों न बिजी गयी हो या जिन गांवों के अंदर जमीन से एक बूंद भी पानी न निकले और जहां पर न तो गेहूं की फसल हो या न ही सरसों की फसल हो, तो क्या वहां वे कम्पनसेशन देने की व्यवस्था करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, अब तो मधवाड़ भी नहीं है। मधवाड़ तब होती है जब रबी की फसल बोयी जाती हो। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं इस सरकार से चाहता हूं, अगर इनकी नीयत साफ हो, कि हमारे प्रदेश के अंदर जो पानी की व्यवस्था है उसको न्यायपूर्वक बांटा जाए। एक तरफ तो अम्बाला जिला है जहां पर टोटल हरियाणा का अवेलेबल वाटर जो कैनाल्ज वगैरा का है या जो पानी बहता है उसका पचास प्रतिशत अम्बाला के अंदर से होकर जाता है। चाहे घग्गर से पानी होकर जाए या यमुना से पानी होकर जाए लेकिन पचास प्रतिशत अम्बाला जिले से ही होकर गुजरता है लेकिन अम्बाला जिले को पानी कितना मिलता है मेरे ख्याल से एक परसैंट पानी भी अम्बाला जिले को नहीं मिलता है। इसी तरह से मेवात का एरिया है, फरीदाबाद का एरिया है, झज्जर का एरिया है, रोहतक का एरिया है, रिवाड़ी का एरिया है, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी या नारनौल का एरिया है अगर इन क्षेत्रों का पानी एक जिला या दो जिले लेकर जाएं तो क्या यह ठीक है ? इसके लिए क्या यह सरकार व्यवस्था बनाएगी कि 2 एम०ए०एफ० पानी जो आज के दिन हमारे पास उपलब्ध है वह उन क्षेत्रों के अंदर इस्तेमाल किया जाए जहां पर आज के दिन पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं, नहर के पानी की तो आप बात ही छोड़िए। स्पीकर साहब, इसी तरह से मैंने पिछले सैशन में पानी के रि-चार्जिंग की बात की थी। मुझे सरकार की नीयत साफ नहीं लगती कि यह पानी का बंटवारा इक्विटेबल रूप से करेगी। लेकिन एक चीज की मैं इस सरकार से उम्मीद कर सकता हूं कि जब बाढ़ आती है या जब बरसात आती है तो उस समय पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में या अरब की खाड़ी में चला जाता है इसलिए क्यों नहीं हमारे यहां पानी के रि-चार्जिंग की व्यवस्था कर ली जाती ? कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 90 फुट तक खोदो तो भी आपको पानी नहीं मिल सकता। इसलिए सरकार रि-चार्जिंग की व्यवस्था क्यों नहीं करती। इसी तरह से मुआवजे की बात आयी। गवर्नर साहब के अभिभाषण में कहा गया है कि इतना पैसा मुआवजे के लिए निर्धारित किया गया है। कहने के लिए तो यह अच्छी बात है लेकिन जब गांव के अंदर हम सुनते हैं कि एक गांव के अंदर नुक्सान के लिए केवल पचास हजार रुपये ही मिले तो इसको सुनकर बड़ा अचम्भा हो जाता है। अगर किसान को आपकी तरफ से एक एकड़ में नुक्सान के बदले में केवल तीन रुपये मिले, एक रूपया मिला, दस रुपये मिले या 15 रुपये मिले तो क्या आप किसान के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, बेइज्जत नहीं कर रहे हैं ? जबकि आप कहते हैं कि यह किसानों की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, फ्री पावर का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। जब फ्री पावर का जिक्र होता है तो मुख्य मंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैनीफैस्टो में दिखाओ कि कहां इस बारे में लिखा है अगर हमने मैनीफैस्टो में नहीं लिखा है तो आप फ्री पावर की चर्चा क्यों इस सदन में करते हो। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा की आम जनता मैनीफैस्टो नहीं पढ़ती। आप स्वयं राम कुमार कटवाल से पूछ लें कि मैनीफैस्टो में क्या लिखा है अगर वे बता दें तो आप कह देना। अगर कटवाल साहब ही नहीं बता सकते तो फिर जनता मैनीफैस्टो को क्या पढ़ेगी ? स्पीकर साहब, जो हमारे लीडरान हैं जनता उनकी जुबान को देखकर ही सरकार बनाती है। समस्या क्या है कि जब हम बन जाते हैं सरकार में आ जाते हैं तो जबान फिसल जाती है।

श्री अध्यक्ष : इन्द्रजीत सिंह जी, आप वाइंडअप करें।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कस्सी की बात छोड़ देता हूं, लैंड ऐक्वीजिशन की बात छोड़ देता हूं, जौब्स की बात छोड़ देता हूं लेकिन इस बात पर मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूं कि जो इन्होंने फैमिली प्लानिंग की चर्चा की है इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं की। (विघ्न) दूसरी इनकी सराहनीय बात यह है कि कई पार्टियों के लोग अपने आप को तीसमारखां समझने लगे थे और वह किस तरह कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी में गए और दूसरी छोड़कर तीसरी में गए और यह समझते थे कि सबसे ज्यादा अधिकार उनका है। जो एक दम इलैक्शन से पहले पार्टी बदल लेते थे। ऐसे लोगों की तादाद को इन्होंने कम कर दिया, यह बहुत अच्छा किया है इससे कम से कम स्थाई तो रहेंगे। हम मगौड़ों के मार्फत सरकार कभी नहीं बनाना चाहते हैं। आखिर में एक चीज और कहना चाहता हूं कि यह जो मुख्य मंत्री जी हमारी तरफ, हमारी पार्टी की तरफ, हमारी पार्टी के नेताओं की तरफ, हरेक सैशन के अंदर चाहे वह बजट सैशन हो या दूसरा कोई दो दिन का सैशन हो, जब तक मुख्य मंत्री जी यह न कह लें तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती कि तुम दोनों के बीच कितनी बड़ी खाई है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और बताना चाहता हूं कि सदन के अंदर हमारे नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हैं क्योंकि ये हमारी पार्टी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा नियुक्त किए गए थे।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपकी आपसी लड़ाई है। यह मैटर आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष के पास जाकर डिसकस करें। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रीज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात तो पूरी कर लेने दें। हमारी पार्टी के बुजुर्ग नेता चौधरी भजन लाल जी हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी इज्जत करते हैं लेकिन साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हुड्डा साहब या चौधरी भजन लाल जी पार्टी नहीं हैं। ये पार्टी के ओहदेदार अधिकारी जरूर हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी इनसे बड़ी है और इसके अंदर दरार नहीं डलनी चाहिए। हमारी पार्टी के अंदर दो फाड़ हिमाचल प्रदेश में थे। एक तरफ वीरभद्र सिंह थे और दूसरी तरफ विद्या स्टौक्स थीं लेकिन इसके बावजूद वहां हमारी पार्टी सत्ता में आई है। केरल में भी हमारी पार्टी शासन कर रही है वहां भी आपस में खाई थी, दरार थी। इसलिए मुख्य मंत्री जी विचार कर लें कि आने वाले समय के अंदर उनका क्या होगा ?

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय के लिए ढाई बजे तक बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय ढाई बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है। (विघ्न)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, हाउस को चलाने का ऐसा तरीका तो हमने कहीं नहीं देखा है। कल भी डिसकशन कंटीन्यू की जा सकती है। आज ही सबसे क्यों बुलवाने की चेष्टा की जा रही है ?

श्री धर्मबीर सिंह (तोशाम) : स्पीकर सर, कल जो माननीय बाबू परमानन्द जी ने इस सदन 14.00 बजे में जो अभिभाषण पढ़ा है मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न) यह सारा का सारा सदन आज से नहीं कई सालों से सबसे ज्यादा चिन्ता पानी की करता है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 1947 से लेकर आज तक की रिपोर्ट आई है कि सारे देश में नदियों का पानी या बारिश का पानी है उसका केवल 15 प्रतिशत पानी ही आज हिन्दुस्तान की धरती पर लगता है बाकी का 85 प्रतिशत पानी आज भी समुन्द्र में बेकार चला जाता है। इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि केन्द्रीय सरकार इस देश में जितनी नदियां हैं उनको आपस में जोड़ने का एक टाईम निश्चित करे और 2010 तक का इस देश की सारी नदियों को आपस में जोड़ दें। अब केन्द्रीय सरकार ने श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है जिसको कहा गया है कि इस देश की तमाम नदियों को आपस में जोड़ें। आयोग ने अपनी राय दी है कि हम 2016 तक देश की सारी नदियों को जोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। हमें शर्म आती है कि इस देश के प्रधानमंत्री पर, जो हाउस के नेता हैं, विपक्ष के नेता नहीं हैं वे कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है। जहां देश का बजट साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का आता है और उसमें एक भी पैसा देश की नदियों को जोड़ने के लिए आने वाले समय में नहीं दिया है और न ही इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। मैं सारे हाउस के सदस्यों के प्रार्थना करता हूं कि हाउस यूनानीमैसली एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजे कि इस साल के बजट में देश की नदियों को जोड़ने के लिए ज्यादा नहीं तो 20-30 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करे। (विघ्न) दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है बिजली बोर्ड के बारे में। स्पीकर सर, इस देश में बिजली की बड़ी भारी कमी है। जब भी हाईडल प्रोजैक्ट लगता है या दूसरे प्रोजैक्ट लगते हैं तो इससे एक तरफ तो प्रदूषण कम होता है और दूसरी तरफ आपके खनिज पदार्थ खत्म होते हैं, कोयले जैसे। इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है सर्वे में कि इस देश की नदियों में पानी की बहुत अधिक क्षमता है। आने वाले समय में 2010 तक 80 हजार मैगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें इन स्त्रोतों का प्रयोग करना चाहिये। (विघ्न) मेरे साथियों को इस बात से नाराज नहीं होना चाहिये कि आज की सरकार यह क्यों करे ? पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया। पिछली गलतियां हुई हैं तो आगे सुधार कर लेना चाहिए। (विघ्न) दूसरी तरफ एस०वाई०एल० का नाम लेते हैं। स्पीकर सर, एस०वाई०एल० का जिक्र पिछले 25 सालों से हो रहा है कि यह एस०वाई०एल० नहर बनेगी और सारा हरियाणा प्रदेश इसको बनाने के लिए एकजुट है लेकिन यह आज तक नहीं बनी है। आज के दिन पानी की समस्या सबसे ज्यादा भिवानी, महेन्द्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत और रोहतक आदि के इलाकों की है। आंकड़ों के हिसाब से यमुना और भाखड़ा से जो पानी हमें मिल रहा है उसका 70 प्रतिशत पानी डबवाली और टोहाना में चला जाता है। जे०एल०एन० में 14 क्यूसिक पानी चलता है और वह भी महीने में 15 दिन चलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि 700 क्यूसिक पानी तो उन 13 हल्कों में जाता है जहां पानी की बहुत कमी है और 7000 क्यूसिक पानी डबवाली और टोहाना के 13 हल्कों में जाता है जहां सेम की समस्या है। इस तरह से पानी का सही बंटवारा हमारे यहां नहीं हो रहा। हमारे वहां की जनता हमें कोसती है और पूछती है कि हम क्या कर रहे हैं। वे हमें कहते हैं कि हम विधान सभा में जाकर उनके हिस्से का पानी मांगें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि जिला जीन्द, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में सतही जल निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए 170 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे। इस बारे मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि एक

[श्री धर्मबीर सिंह]

तरफ तो इन चार जिलों में सेम की समस्या आई हुई है और उस समस्या को दूर करने के लिए 170 करोड़ 74 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है और दूसरी तरफ 10 जिलों में पीने के पानी की समस्या है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि जो पानी इस समय हमारे यहां आ रहा है और उसका अगर सही बंटवारा हो जाये तो सभी की समस्या दूर हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं खाद्य एवं आपूर्ति के बारे में कहना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि वर्ष 2002 में सरकारी एजेंसियों ने 75361 टन सरसों की रिकार्ड खरीद की है। स्पीकर सर, पिछले वर्ष सरकार ने सरसों के जो रेट फिक्स किए थे उस रेट से 200 रुपये प्रति क्विंटल कम के हिसाब से किसानों की सरसों सरकारी एजेंसियों ने खरीदी। जो लोग पहुंच वाले थे उनकी ही सरसों पूरे रेट पर खरीदी गई। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार से किसानों के साथ खरीद में भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी की फसल सरकारी भाव पर खरीदी जानी चाहिए। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त सरकार 2000 नये Sprinkler Sets खरीदने जा रही है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 20 साल पहले सिवानी और जूई के लिये करोड़ों रुपये के Sprinkler Sets खरीदे गये थे और वे आज यूज नहीं हो रहे। मैं कहना चाहूंगा कि नये Sprinkler Sets खरीदने की बजाय उन पुराने सैट्स को चालू किया जाना चाहिए और उन पर जो जनता का करोड़ों रुपया लगा हुआ है उसका यूज होना चाहिए। स्पीकर सर, सरकार कह रही है कि 20 हजार नये ट्यूबवैल के कनैक्शन दिए जायेंगे। इस बारे में कहना चाहूंगा कि गांवों में किसान ट्यूबवैल का कनैक्शन लेने के लिए 80-80 हजार रुपये बिजली बोर्ड में नई पालिसी के तहत जमा करवाते हैं और उन्हें तब भी जल्दी कनैक्शन नहीं मिलता। उन्हें बार-बार बिजली बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसानों ने जो कमाया था वह पैसा इस नई पालिसी के तहत कनैक्शन लेने में लगा दिया है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन किसानों ने नई पालिसी के तहत जल्दी कनैक्शन लेने के लिए पैसे जमा करवाये हैं उन्हें तुरन्त कनैक्शन दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा शायद मेरी इस बात से मेरी पार्टी के और सत्तापक्ष के भी कई सदस्य इससे सहमत न हों। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का गांवों और शहरों में बराबर बंटवारा होना चाहिए। गांवों में 15-15 दिन बिजली नहीं जाती और शहरों में हमेशा बिजली दी जाती है क्योंकि शहरों में बड़े लोग रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि गांवों में कट लगता है तो शहरों में भी कट लगना चाहिए और बिजली के मामले में भी गांव व शहर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि गांवों में आज भी 80 प्रतिशत लोग रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। स्पीकर सर, आज के दिन खेतीबाड़ी करने वालों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वोट लेते समय सभी पार्टियां कहती हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं लेकिन वोट लेने के बाद और सरकार बनने के बाद सभी उनको भूल जाते हैं और मौजूदा सरकार ने भी किसानों के साथ ऐसा ही किया है। आज जिस प्रकार डीजल, पैट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे खेती पर लागत बहुत अधिक हो गई है और किसान को फसल का उचित भाव नहीं मिलता। आज से ठीक 15 साल पहले जब गेहूं पैदा होता था उसका इतना पैसा बाजार में बेचने पर किसान को मिलता था आज अगर किसी किसान के पास नहरी पानी या ट्यूबवैल के लिए बिजली का कनैक्शन नहीं हो तो वह जब डीजल से ट्यूबवैल चलाकर गेहूं की पैदावार करता है तो उस किसान की गेहूं की फसल 4 ड्रम डीजल से कम में पैदा नहीं होती। इसके बाद जब किसान उस पैदा किए हुए गेहूं

को मण्डी में या बाजार में बेचकर आता है तो 2 ड्रमों के तेल के पैसे भी नहीं मिलते क्योंकि आज एक ड्रम डीजल साढ़े चार हजार रुपये में मिलता है। मेरा मतलब कहने का यह है कि जिस प्रकार से डीजल के ऊपर डेढ़ रुपया सड़कें बनाये जाने के नाम से प्राईमिनिस्टर ने लगा दिया और अब फिर 50 पैसे पर लीटर डीजल पर यह भार किसानों पर डाला गया है यह ठीक नहीं है। जो डेढ़ रुपये डीजल के रेट पर लीटर के हिसाब से केन्द्र सरकार ने बढ़ाए हैं उस के ऊपर भी सेल्ज टैक्स हरियाणा सरकार ने लगा दिया है। सरकार कहती है कि सड़कें ठीक करनी हैं। इस बारे में मेरा कहना है कि सेल्ज टैक्स को कम किया जाये ताकि किसानों को डीजल सस्ता मिल सके। एक तरफ भारत सरकार ने उसी पैसे से सड़कों का निर्माण किया जैसा कि आपके गवर्नर महोदय ने अभिभाषण में जिकर है जबकि दूसरी तरफ आपने हुडको से सड़कें बनाने के लिए लोन लिया है। स्पीकर साहब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो सड़कें प्रधानमंत्री जी ने बनवाई हैं उन पर टोल टैक्स लगाया जा रहा है। यह टोल टैक्स लोहारू में भी लगाया गया है। इसी प्रकार से गुड़गांव, सोहना व हरियाणा प्रदेश में दूसरी ऐसी 19 सड़कों पर टोल टैक्स लगाया जा रहा है। इस टोल टैक्स की आड़ में इतनी हेराफेरी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस टोल टैक्स को लेने में यह क्लीयर नहीं है कि किस किस से टोल टैक्स लिया जायेगा। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस समय जहां से भी टोल टैक्स लिया जा रहा है वहां पर जो जीप आती है, टाटा सूमो आती है या दूसरे जो हल्के व्हीक्लज आते हैं उनसे 50 रुपये प्रति व्हीकल्ज लिए जाते हैं। हो सकता है कि सरकार के नोटिस में यह बात न हो। मेरे ख्याल में सरकार ने टाटा 407, ट्रक व बसों पर इस प्रकार का टैक्स लगाया हो लेकिन वास्तव में वहां पर मौके पर जाकर देखें तो वहां पर जीप, कार, सूमो वालों से भी अवैध रूप से पैसा लिया जाता है। मैं बाई नेम कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान का बोर्डर है, लोहारू से आगे पीपल पर उस पर टोल टैक्स लगाया है। अगर मेरी बात ठीक न लगे तो इस बारे में मण्डोला जी से पूछ लिया जाये। ये भी इस बात को बता देंगे कि वहां पर अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है या नहीं।

श्री रणबीर सिंह : अभी मेरे भाई धर्मबीर जी ने जो लोहारू में टोल टैक्स लगने की बात कही है, इस बारे में मैं अपने साथी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि लोहारू में जीप, टाटा सूमो या जो छोटी गाड़ियां हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता।

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी आप बैठिये। आप इरीगेशन पर बहुत बोल चुके हैं।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, अब मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बुरा हाल है। सरकार गांवों में 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने की बात करती है। मैं आपको अपने हल्के के गांवों के नाम गिनवा देता हूं जहां पर लोग जोहड़ों का पानी पीते हैं। मैं पिछले तीन साल से लगातार कह रहा हूं कि भिवानी जिले में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। जिस ढाणी में ताऊ के नाम पर नलके के गीत गाये जाते थे आज वहां पर लोगों को पानी मोल लेकर पीना पड़ता है। जिस गांव की आबादी 10 हजार की है वहां के लोग भी जोहड़ का पानी पीते हैं। आजाद हिन्दुस्तान में हमें शर्म आती है जब हम यह बात सुनते हैं। हमारी कमेटी वहां पर मौके पर गई थी। किसी ने पूछ लिया कि क्या पानी मिलता है तो उन लोगों ने केवल एक ही बात कही कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट स्वच्छ जल तो नहीं पिला सकता लेकिन कम से कम जोहड़ों में तो पानी डाल दो ताकि हम उससे लेकर पानी पी सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मबीर जी आप बैठिये।

श्री धर्मबीर सिंह : एक बात मैं खेलों के बारे में कहना चाहूंगा। यह बात ठीक है कि खेलों को प्रोत्साहन मिला है। इस सरकार के बनने के बाद खेलों को काफी बढ़ावा मिला है। स्पीकर साहब, वैसे तो दुनिया के कुछ देशों में खासतौर पर 10-15 देशों में सारा पैसा एक ही गेम ने खा लिया। इस हिन्दुस्तान का सारा पैसा भी केवल इसी गेम ने खा लिया। मैं चाहता हूं कि इस गेम पर पाबंदी लगायी जाये ताकि पैसा हर खेल के लिए बंट कर आ जाये।

श्री अध्यक्ष : वह कौन सा गेम है।

श्री धर्मबीर सिंह : वह गेम क्रिकेट का है। इस क्रिकेट पर बैन लगवाओ ताकि वह पैसा बाकी स्पोर्टस को भी मिल जाए। स्पीकर साहब, एक विभाग ऐसा है जिसमें सिर्फ एक समुदाय यानि बाल्मीकि समुदाय काम करता है। इस काम को और कोई दूसरा समुदाय काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कमेटी के अन्दर उन कर्मचारियों को छः छः महीने की तनख्वाह नहीं मिलती।

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी अब आप बैठें।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। * * * *

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठें। धर्मबीर जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री सुभाष गोयल (नगर विकस राज्य मन्त्री) : धर्मबीर, जी आप गलत कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा। ऐसी कोई कमेटी नहीं है जहां पर कर्मचारियों के पिछले 6 महीने से तनख्वाह न दी हो। आप गलत कह रहे हो।

राव नरेन्द्र सिंह (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के अन्दर सबसे पहले मुख्य चर्चा एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में आई। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा के लोगों के लिए यह नहर एक जीवन रेखा है। इस नहर को पूरा करने के लिए हम सभी हरियाणा के राजनीतिक दलों को, पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर इस नहर के निर्माण के लिए, एकजुट हो कर प्रयास करने चाहिएं और केन्द्र सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस नहर का निर्माण कार्य पूरा करवाए ताकि वह जल जो हरियाणा को मिलना है वह शीघ्र हरियाणा को मिल सके। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ जिला हरियाणा के आखिरी छोर है जहां से मैं सम्बन्ध रखता हूं। वहां पर सरकार को पानी की स्थिति को देखना चाहिए। आप महेन्द्रगढ़ जिले में जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां का किसान बहुत ही बहादुर है। किसान खुद तो खेती करता है उसके साथ साथ उसके परिवार में उसका भाई या उसका बेटा भी देश की सेवा सरहद पर जा कर करता है। अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि आज वहां पर खेती के लिए पानी की बात को तो छोड़िये किसानों को पीने के लिए पानी उस इलाके के लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र नांगल चौधरी ब्लॉक व नारनौल ब्लॉक के अन्दर निजामपुर का इलाका है दोहान पच्चीसी का इलाका है जहां के 25 गांवों के लोगों ने आम चुनाव सन् 2000 के अन्दर वोट नहीं

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डाले और विधान सभा चुनाव का भी बहिष्कार किया। यह बहिष्कार इसी बात को ले कर किया गया कि आजादी के 50 वर्ष के बाद भी इन्हें पीने का पानी नहीं मिला तो फिर वोट डालना बेकार है, इसलिए हम चाहते हैं कि एस०वाई०एल० नहर को बनवाया जाए। सरकार एस०वाई०एल० कैनाल के निर्माण पर अरबों रुपये खर्च कर चुकी है लेकिन हरियाणा को अपना पानी का हिस्सा नहीं मिल पाया है। पंजाब के ऐरिया में नहर का निर्माण करने के लिए तथा अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं क्योंकि उसका पानी बह कर पाकिस्तान जा रहा है लेकिन हरियाणा में वह पानी नहीं आ रहा है। स्पीकर सर, पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मण्डल इस मुद्दे को ले कर माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला। इसके लिए बड़ा भारी जनसमूह राम लीला मैदान में भी इकट्ठा हुआ। (विघ्न)

मुख्यमन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला) : यह पूरा प्रतिनिधि मण्डल था या आधा अधूरा प्रतिनिधि मण्डल था ? (विघ्न)

राव नरेन्द्र सिंह : वह पूरा प्रतिनिधि मण्डल था और उसमें हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। हो सकता है हमारी पार्टी के कुछ लोग किसी कारण से उस दिन न आ पाए हों लेकिन यह कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल था जिसमें हमारे विधायक, किसान और दूसरे लोग भी शामिल थे। हम सभी प्रधान मंत्री जी से मिले तथा बोट क्लब पर रैली भी की। हमने प्रधान मन्त्री जी से मिल कर कहा कि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हरियाणा के लोग हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और हम चाहते हैं कि हमें भी और लोगों की तरह हमारे हिस्से का पानी मिले। प्रधान मंत्री जी ने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। (विघ्न) मैं समझता हूं कि इस के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मैं हरियाणा के मुख्यमन्त्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज केन्द्र में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की सरकार है और उस सरकार में आपकी भी हिस्सेदारी है क्योंकि आपके सांसद भी उसमें शामिल हैं। मुख्य मन्त्री जी, मेहरबानी करके आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर केन्द्र सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करें ताकि प्रधान मंत्री जी यह महसूस करें कि वास्तव में हरियाणा के लोग उस पानी के बगैर जिन्दा नहीं रह सकते ताकि वह पानी हम लोगों को मिल सके। स्पीकर सर, दूसरे विकास का मुद्दा है और सूखे का मुद्दा है। पिछले दिनों हरियाणा के अन्दर बहुत भयन्कर सूखा पड़ा और सारी फसल खराब हो गई थी। सरकार ने खुद इस बात को माना है और मुख्यमन्त्री जी ने सारे हरियाणा को सूखाग्रस्त क्षेत्र डिक्लेयर किया है। इस बात पर किसानों को बहुत उम्मीद थी कि हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं, वे उनकी बड़ी मदद करेंगे। पता नहीं हमारे लोगों को इनसे कितनी बड़ी उम्मीद थी और वे सोचते थे कि सरकार हमारी काफी मदद करेगी। स्पीकर सर, आपको शायद इसकी रिपोर्ट मिल गई होगी कि जो राहत राशि वहां पर बांटी गई थी वह इतनी कम थी कि यह राहत एक मजाक बन कर रह गई। गांवों के बहुत से लोगों ने इस राहत राशि को लेने से मना कर दिया। किसी के हिस्से में 5 रुपये किसी के हिस्से में 10, 15 या 20 रुपये ही राहत राशि के आए जिससे यह राहत राशि एक मजाक बन कर रह गई। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि किसान के पास पशुधन है और पशुधन के लिए चारा चाहिए जो कि बहुत महंगा हुआ है। चारे को ले कर हमारे एक सदस्य साहेबान बोल रहे थे कि महंगे चारे से किसानों को फायदा ही हुआ है। लेकिन जो खरीद रहा है वह पैसे वाला खरीद रहा है। बिना पैसे वाला कोई चारा नहीं खरीदता है। (विघ्न)

[राव नरेन्द्र सिंह]

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सूखे के मामले पर जो हरियाणा सरकार ने जो एक पालिसी निर्धारित की है वह पालिसी बहुत गलत निर्धारित की है। हमें पिछले दिनों पार्लियामैंट में जाने का मौका मिला। मैं और कैप्टन अजय सिंह यादव जी वहां पर गए थे। वहां पर केन्द्रीय मंत्री माननीय अजीत सिंह जी से भेंट हुई। हमने उनके सामने भी यह बात रखी कि चौधरी अजीत सिंह हरियाणा के अन्दर बड़ा भारी सूखा पड़ा हुआ है आप हमारी कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने हमें कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो कभी किसी प्रकार की मांग नहीं रखी है, आपके मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कोई सूखा नहीं है और आप लोग कहते हैं सूखा है। इसके साथ ही उन्होंने हमें कहा कि आपका सूखा राहत कोष आपके पास है, आपको उसको यूज करना चाहिए। अगर वह खाली होगा तो और पैसे भेज दिए जाएंगे। स्पीकर सर, हमने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा और उसमें 241.34 लाख रुपये की राशि राहत के लिए बांटी गई लिखा गया है लेकिन यह जो राहत राशि बांटने के लिए क्राईटेरिया निर्धारित किया गया है उस पर हमें आपत्ति है और यह गलत तरीके से बांटी गई है। किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए था, उसको जो फायदा होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। हरियाणा का किसान समझता था कि सूखे की वजह से बिजली का बिल माफ होगा। कोआप्रेटिव बैंकों और लैंड मॉर्टगेज बैंको का ऋण माफ होगा। वह समझता था कि उसको इस सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि हरियाणा के किसानों को इनमें से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाई। हरियाणा के लोग इस बारे में जरूर जानना चाहते हैं कि केन्द्र से हरियाणा गवर्नमैंट को सूखे के नाम पर कितनी राशि मिली है और कितनी इस सरकार ने बांटी है और कहां कहां पर बांटी है। इस बारे में जो विवरण है वह सरकार अपने जवाब में जरूर दे। स्पीकर सर, इसी के साथ हमारे मुख्य मंत्री जी अभी सदन में उपस्थित हैं मैं आपके माध्यम से इनसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा रबी, गेहूं और सरसों की फसल है, उसको बिजली कम मिलने की वजह से, नहरी पानी खेतों में न जाने की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जिला महेन्द्रगढ में 50 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिन गांवों की जमीन खाली पड़ी हुई है और उस जमीन पर किसान खेती नहीं कर सका है। मैं स्पीकर सर, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन किसानों के लिए जो अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पाए हैं और जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए सरकार अवश्य कोई मदद डिक्लेयर करे। इसी के साथ आप उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की कोई टीम वहां पर भेजे चाहे उसमें अधिकारियों को भेजें, चाहे सदन के प्रतिनिधियों को भेजें। वे जाकर वहां पर देखें कि वहां पर क्या पोजीशन है और वहां के किसानों का किस तरह से भला हो सकता है।

स्पीकर सर, इसी प्रकार से मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर के बारे में कहना चाहता हूं और इस बारे में हमारे साथी श्री धर्मपाल सिंह जी ने भी विस्तार से बताया है। मेरा भी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि एस०वाई०एल० को बनने में समय लग जाएगा इसलिए जो मौजूदा पानी है उसका आप समान बंटवारा करें ताकि जो हरियाणा के अन्दर आज जो पानी की पोजीशन बनी हुई है उसको ठीक किया जा सके। आज किसी क्षेत्र में तो सेम है और किसी क्षेत्र में भयंकर सूखा है। मेहरबानी करके जो मौजूदा पानी का जल स्तर है उस पानी का समस्त हरियाणा में समान बंटवारा हो ताकि बाकी किसान भी खेती कर सके और उन लोगों को पीने का पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप समाप्त करें।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, इसी प्रकार से बिजली के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। पिछले दिनों इस सरकार की तरफ से बिजली के बारे में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं आई कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और कुछ समय बाद हरियाणा दूसरे प्रदेशों को भी बिजली देने लग जाएगा। लेकिन हकीकत में आज देहातों में 4 घंटे और 5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जा रही है। इस बारे में मैं सरकार से जरूर निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें। आज बच्चों की परीक्षा का समय चल रहा है, इसको देखते हुए स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए शाम को और सुबह को हर हालत में बिजली उपलब्ध करवाई जाए। खासकर शाम को जब किसान का खाने का वक्त होता है उस समय भी बिजली चली जाती है इस बारे में भी ध्यान रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, हम सुना करते थे कि मुख्य मंत्री जी पहले अपनी स्पीचों में यह कहा करते थे कि शाम को जब किसान रोटी खाने लगता है, उस समय बिजली नहीं होती है और बिल्ली आकर किसान की रोटी छीन लेती है। मेरा मुख्य मंत्री जी से यह कहना है कि मुख्य मंत्री आज फिर से वही समय हरियाणा के अन्दर चल रहा है। मेहरबानी करके आप ऐसा कुछ करें ताकि वह समय दोबारा से हरियाणा में न रहे। हर हाल में किसान को खाना खाते वक्त और बच्चों को पढ़ाई के वक्त, बिजली बराबर मिल सके।

इसी के साथ स्पीकर सर, मैं बेरोजगारी की तरफ भी इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस सरकार के बनने से पहले जो इलैक्शन का पीरियड था उस वक्त सरकार की तरफ से आज के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने के बाद ये 70 हजार लोगों को रोजगार देंगे जो काम बंसी लाल की सरकार छोड़ कर गई है। इस बारे में हम और हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि इस सरकार के बनने के तीन साल के समय के दौरान हरियाणा के कितने लोगों को रोजगार दिया गया है और जिलेवाइज कितना कितना हिस्सा उनके हिस्से में आया इस बात को भी जरूर बताया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें हमारे स्थानीय नौजवानों को लगाया जाना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि इनमें हमारे नौजवान ही लगेंगे ताकि वे भी अपना गुजारा कर सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप एक मिनट में वाईड अप करें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों केन्द्र की सरकार ने जो गेहूं और सरसों के भाव डिक्लेयर किए थे क्या उनके बारे में सरकार ने कुछ सोचा है। हरियाणा में आज जो सरकार काम कर रही है वह अपने आप को किसानों की सरकार कहती है। जब यह किसानों की सरकार है और मौजूदा जो ये भाव घोषित हुए हैं उसके लिए सरकार को चाहिए कि वह ये भाव बढ़ाने के लिए केन्द्र की सरकार पर दबाव डाले। जब यह मौजूदा सरकार आयी थी तो उस समय 1999 में डीज़ल का भाव दस रुपये लीटर था और आज डीज़ल का भाव 21 रुपये हो चुका है। डीज़ल तो किसान के ही काम की चीज है। इसी तरह से खाद के रेट भी मौजूदा केन्द्र की सरकार ने बढ़ाए हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रयास इस बारे में हमारी सरकार के स्तर पर होने चाहिए थे वह नहीं हुए हैं। केवल अखबारी बयान देने से काम नहीं चलता है। हरियाणा के एक प्रतिनिधि मंडल को इस बात को लेकर प्रधानमंत्री पर जितना दबाव डालना चाहिए था उतना दबाव हम उन पर नहीं डाल पाए। मैं सरकार से जानना

[राव नरेन्द्र सिंह]

चाहता हूं कि जो डीजल, खाद एवं सीमेंट के रेट बढ़े हैं उनके बारे में यह मौजूदा सरकार क्या कर रही है और जिन चीजों के दाम केन्द्र सरकार ने कम किए हैं उनके बारे में मौजूदा सरकार का क्या विचार है ? इसी तरह से सड़कों का जिक्र आया। मैंने इस बारे में बहुत सारे क्वैश्चन भी लिखकर दिए हुए हैं। सड़कों का, खास तौर पर ग्रामीण सड़कों का और शहरी सड़कों का, भी बहुत बुरा हाल है। राजस्थान के कोटपुतली बोर्डर से नांगल चौधरी होकर जो सड़क भिवानी को, रोहतक को आती है उसकी भी बहुत बुरी हालत है उस पर ट्रैफिक नहीं चल सकता। सारा ट्रैफिक झज्जर से होकर निकलता है इसलिए सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं स्थानीय समस्याओं का भी जिक्र करना चाहूंगा। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जिनके नाम आये हैं उन्हें आप आज जरूर बुलवाएं।

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्र सिंह जी, आप बैठिए। अब शेर सिंह जी बोलेंगे। अगर शेर सिंह जी नहीं बोलना चाहते तो अनिता यादव बोलेंगी। (विघ्न) अब शेर सिंह जी बोलेंगे। इनके बाद अनिता यादव एवं राव दान सिंह बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, इनकी तरफ से बोलने वालों के नाम आये हुए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ घंटे तक उदयभान जी बोलते रहे तब आपने कुछ नहीं कहा। अब तो कोई समय नहीं है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, जो नाम आपके सामने आये हुए हैं आप उनको बुलाएं। आपकी फ्राखदिली की हम दाद देते हैं। आपने खूब बोलने का समय दिया। जो बोलना चाहें उनके आप नाम बोलें और जो नहीं बोलना चाहें वह चाहें तो जा सकते हैं। (विघ्न) सदन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अब तो समय हो गया है। पांच मिनट में अब क्या बोलेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिए। शेर सिंह जी बोलने के लिए खड़े हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लोगों के खून पसीने की कमाई बर्बाद करने के लिए नहीं है। हाउस पर लोगों के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। (विघ्न)

चौ० जय प्रकाश : स्पीकर साहब जो सिस्टम होता है आप उसके हिसाब से हाउस चलाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अध्यक्ष हैं। यहां पर लोगों की बात नहीं सुनी जाती। इस प्रकार से चालाकी करना प्रजातंत्र में अच्छी प्रथा नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी, अब आप बोलें। जो नाम मेरे पास आए हैं उनमें से ही मैं बुला रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी सदन में ऐसी कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। (शोर एवं व्यवधान)

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह (जुलाना) : स्पीकर सर, आज पानी के ऊपर काफी चर्चा हुई है और जो आंकडे दिये गये हैं मैं कहना चाहता हूं कि आज आंकड़े देने का समय नहीं है। हम सभी हरियाणा वासी सच्चे हरियाणा वासी हैं और हम सभी एस०वाई०एल० का पानी आज चाहते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब यह बात रही कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है जरा उसको याद करना है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें एक शब्द है 'शीघ्र से शीघ्र' भारत सरकार पानी लाएगी। वह जो 'शीघ्र' वर्ड है उसका मतलब ऐक्सपीडियशली है। वह कितने दिन का है कब तक है यह तय करना इस सरकार का काम है क्योंकि आगे फिर इलैक्शन आ जाएगा और फिर ये नारा लगाएंगे। यह जो 'शीघ्र' वर्ड है वह एक आदमी के लिए एक दिन हो सकता है दूसरे आदमी के लिए दस दिन भी हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि जिस केन्द्र सरकार की ये सपोर्ट कर रहे हैं उनसे ये पूछें कि कौन सी डेट तक पानी दिया जाएगा। इसमें शक की बात नहीं है कि पानी हम चाहते हैं। दूसरा सवाल 'जय जवान जय किसान' का है और इसमें कोई शक नहीं है कि किसान और जवान ही देश को जिंदा रखते हैं। यह जिस किसी ने भी कहा था ठीक ही कहा था। किसान देश के लोगों का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। जब यह सरकार आई थी तो जवानों के बारे में बहुत से नारे लगाए गए थे। कारगिल का जो युद्ध हुआ था वह हुआ नहीं था बल्कि वह कराया गया था। अपनी जमीन पर उनको बुलाकर लड़ाते हैं और कहते हैं कि हमने युद्ध जीता है। मैं हरियाणा सरकार की दाद देता हूं कि शुरु में तो इन्होंने शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये बगैर भेदभाव के दिये लेकिन बाद में उनको भूल गए। उस समय तो उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है लेकिन बाद में उन जवानों को भूल जाते हैं। पिछले साल इन्होंने यह कह दिया कि 10 लाख रुपये नहीं दिये जाएंगे। यह तब दिये जाएंगे जब अंतरराष्ट्रीय लड़ाई होगी। यह लड़ाई कब होगी यह तो हम जानते नहीं है लेकिन जवान इस देश की रक्षा करने के लिए शहीद होते जा रहे हैं। यह ख्याल करना सरकार का काम है उसमें भी यह सरकार भेदभाव करती है। यह सरकार उनमें भी भेदभाव करती है जो हमारे आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के जवान शहीद होते हैं, उनको ये ढाई लाख रुपये देते हैं। हरियाणा की जो पैरा मिलिट्री फोर्सिज हैं उनमें हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको ये भूल चुके हैं। जो कि देश के लिए लड़ते हैं उनको एक धेला भी नहीं दिया जाता है तो मैं हरियाणा सरकार से यह

[श्री शेर सिंह]

निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी शहीद होने पर ढाई लाख रूपया जो राशि अन्य शहीदों को दी जाती है वह मिलनी चाहिए। किसान जो खेत उगाता है और खाना देता है उसके साथ साथ वह जवान भी पैदा करता है। आज किसान भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहता है। देश की रक्षा यदि कोई करता है तो वह जवान करता है। अगर जवान दुखी होगा चाहे वह सीमा पर हो, शहर में हो या गांव में हो तो उसमें अनुशासन ठीक नहीं रह सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है इस बारे में कोई भी जिक्र गवर्नर एड्रेस में नहीं किया गया है। अगर जवानों को नौकरी का प्रावधान नहीं किया गया वे नहीं चाहते कि उन्हें नौकरी सरकारी ही मिले। लेकिन उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी और उनकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा तभी हम कह सकते हैं कि यह एक कल्याणकारी सरकार है। अनइम्प्लायमेंट पर हरियाणा सरकार को काफी तवज्जो देने की जरूरत है। बल्कि जो लोग नौकरी से निकाले गये हैं उनको नौकरी देनी चाहिये थी लेकिन उनको नहीं दी। जो लोग एडॉक पर लगे हुये हैं और जिनको 10 साल हो गये हैं उन पर हर दम तलवार लटक रही है, उनके बच्चे भी हो गये हैं और छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं लेकिन उनको रात दिन डर लगा रहता है कि कल शायद कहीं उनकी नौकरी छूट न जाये। अगर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ इस तरह की बात हो तो वे काम के प्रति कैसे वफादार हो सकते हैं, इस बारे में आप सोच सकते हैं। अब मैं किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। किसान को भाव देने के बारे में शेखियां मारते हैं कि हमने इतना दे दिया, उतना दे दिया। आप उसकी लागत को तो देखें। आप उनकी इनपुट और आउटपुट को देखें। किसान की जरूरत की हर चीज के दाम कितने महंगे हो चुके हैं। अगर इनपुट और आउटपुट की रेशो को देखें तो किसान घाटे में जा रहा है। अब कीमत लगा दी जाये किसान की। पहले किसान बैल से खेल जोतता था लेकिन आज वह ट्रैक्टर से खेत जोतता है। ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई है। ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिये गये हैं। जब से यह सरकार आई है डीजल कितनी बार बढ़ा है 9 रुपये से लेकर आज 21 रुपये तक डीजल की कीमत हो गई है। हर किसान के लिए एक बड़ी दुखदायी बात है। डीजल से ही वह अपना पानी देता है। जहां पानी नहीं है वहां ट्यूबवैल से पानी देना पड़ता है। हर जगह बिजली नहीं जाती। हमें मालूम है कि कितनी बिजली मिलती है खेतों में। जीन्द शहर में मैं देखता हूं वहां कितनी बिजली शहर में आती है। कभी आती है कभी नहीं आती। गांव में जब बिजली आती है तो कभी 6 घण्टे दी जाती है और यह न मालूम कब जायेगी और कब आयेगी और अचानक चली भी जाती है तो आधे घण्टे बाद आती है। जब तक नाली यहां तक पहुंचती है तब तक पानी बन्द हो जाता है तो इसकी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। आज गेहूं का भाव देखिए। 580/- रुपये क्विंटल गेहूं का भाव 1996 में था और अब 610/- रुपये क्विंटल है। सरसों का 1996 में 1900/- रुपये प्रति क्विंटल था और आज 950/- से 1350/- रुपये प्रति क्विंटल है। कपास जो 2600/- रुपये प्रति क्विंटल पहुंच चुकी थी आज 1300/- से 1700/- रुपये प्रति क्विंटल है। बासमती जो 2500/- रुपये प्रति क्विंटल बिकती थी आज 1200/- से 1500/- और 1800/- रुपये तक बिकती है।

श्री अध्यक्ष : बासमती तो 2200/- रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : लेकिन 2500/- रुपये तक तो नहीं पहुंची है।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल में आपके यहां बासमती नहीं होती।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, साउथ हरियाणा में बासमती कहां होता है, जीन्द में कहां बासमती होता है।

श्री अध्यक्ष : जब बासमती होगी तभी बिकेगी, जहां गन्ना होगा वहां गन्ना बिकेगा। आप शार्ट करें।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली के भाव का आपको पता ही है पहले क्या थे और अब क्या हैं। डोमस्टिक बिजली का भाव 4/- रुपये प्रति यूनिट और खेती के लिए बिजली का भाव 50 से 80 पैसे प्रति यूनिट है और बिजली कितनी मिलती है वह सभी को मालूम है।

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी जल्दी समाप्त करें।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी की बात है, इस बारे में सभी सदस्यों ने जिक्र किया। मैं अपने एरिया जुलाना की नहरों के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे एरिया में सुन्दर ब्रांच और दूसरी ब्रांचें बीचों बीच जाती हैं। मेरे एरिया में कितने रजबाहे हैं उन रजबाहों में पानी कभी नहीं जाता बल्कि उनकी मोरियां भी छोटी कर दी गई हैं। 7-8 रजबाहे उनमें ऐसे हैं जहां पानी कभी नहीं आता। उनके नाम लूंगा तो टाईम लगेगा आप वैसे ही हमें टाईम थोड़ा देते हैं। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आपकी रिहायश तो गुड़गांव में है।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की रिहायश भी तो चौटाला में थी। अपना घर मैं कहीं भी बना सकता हूं लेकिन मैं रहता जींद में हूं चौधरी साहब। मेरे आदरणीय मुख्य मंत्री जी की कोठियां तो कई हो सकती हैं मेरा तो एक ही घर है। इनके तो कई घर हैं और मैं तो जींद में किराये के मकान में रहता हूं सरकार चाहे तो अपनी सी०आई०डी० से मालूम कर सकती है। यह सब को मालूम है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लेकिन आप जुलाना में तो जाते नहीं है। (विघ्न)

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट्रीज के बारे में जिक्र करना चहता हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, शेर सिंह जी से आप पूछे कि इनके यहां मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटरी का उद्घाटन किया था या नहीं और आज वह चल रही है या नहीं ।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे भी मैं बताऊंगा। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के हुआ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहा रामकली माईनर का उद्घाटन किया था और वह बन भी गया लेकिन पानी आगे नहीं पहुंचा। पानी आगे इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि इस माईनर की जितनी सतह होनी चाहिए थी उतनी नहीं बनाई गई बल्कि उसे कम कर दिया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं शेर सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि वह माईनर रबड़ से बना है या ईंट से। रबड़ से बने हुए को ही कम या ज्यादा किया जा सकता है न कि ईंट से बने हुए को। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मैं शेर सिंह जी को कहना चाहूंगा कि ये पुलिस में रहे हैं और ये यहां सदन में पुलिस वालों जैसी बातें न किया करें।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मैं पुलिस में नहीं रहा और न ही मैं पुलिस वालों जैसी बातें कर रहा हूं। मैं बोर्डर फोर्स में रहा हूं और बोर्डर वाले चैकिंग करते हैं। मेरे अंदर पुलिस वाली आदत बिल्कुल नहीं है, पुलिस के साथ ताल्लुकात मुख्य मंत्री जी के ज्यादा रहे हैं, मेरे नहीं।

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी प्लीज आप वाईड अप करें।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इतनी जल्दी वाईड अप करूं तो आपने मुझे बोलने के लिए समय ही क्यों दिया ? (शोर एवं व्यवधान) अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रामकली माईनर रबड़ से थोड़ी ही बना है कि उसकी सतह कम कर दी गई। इस बारे मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो बनाने वाले हैं वे पैसा खा जाते हैं। बनाने वालों ने उस माईनर की सतह को दो फिट कम कर दिया। ठेकेदार अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह कम या ज्यादा किया जाता है। (विघ्न) मेरे कहने का मतलब यह है कि यह माईनर सैटीसफैक्शन के मुताबिक नहीं बनाया गया और इसी कारण पानी नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया गया है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि शिक्षा ठीक होगी तो समाज की व्यवस्था भी ठीक होगी। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी, प्लीज आप मेरी बात सुन लें उसके बाद आप कह लेना। हमारे जो स्कूल्ज हैं उनमें जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए यानि जरूरत की जो चीजें होनी चाहिएं वे नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मैं रैशनलाईजेशन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।

हम भी चाहते हैं कि रैशनलाईजेशन होना चाहिए लेकिन मौजूदा सरकार ने जो रेशनलाईजेशन किया है वह बिल्कुल गलत किया है। रैशनलाईजेशन के तहत अब जो पोस्टिंग की गई हैं वे बिल्कुल गलत की गई है। क्योंकि यह समय बच्चों की पढ़ाई का है और ऐसे समय में बदली करना बहुत गलत है, इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि अब बच्चों के पेपरों का समय है। यदि सरकार ने रेशनलाईजेशन करना ही था तो जून और जुलाई के महीने में करना था जब नया सैशन शुरू होता है। इसके अतिरिक्त रेशनलाईजेशन के तहत जो पीरियड एक अध्यापक के लिए लगाये गये हैं वे भी गलत लगाये गये हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि यदि किसी स्कूल किसी क्लास में 6 सैक्शन हैं और 87 पीरियड एक हफ्ते में एक टीचर को लगाने हैं तो वह कैसे सभी पीरियड लगायेगा क्योंकि एक टीचर को ज्यादा से ज्यादा दिन के 9 पीरियड अलाउड किया ये गये हैं इस हिसाब से हफ्ते में यदि छः दिन स्कूल लगे तो 54 पीरियड एक टीचर के बनते हैं और 54 पीरियड ही एक टीचर लगा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि मौजूदा सरकार ने जो रेशनलाईजेशन किया है यह सिर्फ अपने भाई बन्धुओं को ठीक जगह लगाने के लिए किया है। इसे लागू करते समय सरकार ने बच्चों के भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब भी कई जगह टीचर नहीं हैं, किसी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा दिया और उसकी जगह उसी विषय का दूसरा टीचर लगा दिया यह इनका सही तरीका नहीं है। जो ऐंड-हाक टीचर हैं जिनके बारे में पहले भी बताया गया है उनको लगे हुए 9-9 साल हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : स्पीकर साहब, मुझे थोड़ी देर और बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आप पहले ही बहुत बोल लिए हैं।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा और बोल लेने दीजिए। आपकी इजाजत से मैं सड़कों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ सड़कें बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। इन बनी हुई सड़कों के बारे में मेरा कहना है कि जब सड़कें बन जाती हैं तो एक रात के बाद ही वे उखड़ जाती हैं। स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से इन सड़कों के बारे में एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। मेरा कहना है कि जो सड़कें बनती हैं उनके लिए कोई न कोई प्रायरिटी जरूर निर्धारित की जाये। सड़कों की रिपेयर हुई है इसमें कोई शक नहीं है। (विघ्न) मेरे हल्के में जितनी भी सड़कें बनी हैं वे बनने के बाद टूट जाती हैं। किसी भाई ने रोहतक वाली रोड़ का जिकर किया था। उन्होंने कहा था कि यह रोड जीन्द तक जब बन रही थी तो आगे आगे वह बन रही थी तो पीछे पीछे टूट रही थी। इसी प्रकार से जो सड़कें टूटी हुई हैं अगर उनके नाम मैं बताऊंगा तो उनको बताने में बहुत टाईम लग जायेगा। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आप अपने हल्के में जाया भी करो।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अगर मैं नहीं जाता तो शायद मेरे हल्के में कोई नहीं जाता। मेरे हल्के की जिम्मेवारी मेरी है, आपकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: शेर सिंह जी, अब आप बैठिये।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : स्पीकर साहब, जुलाना के अन्दर एक बस स्टैण्ड बनाया गया था। यह बस स्टैण्ड हरिजनों की जमीन लेकर बनाया गया था। इस बस स्टैण्ड के लिए साढ़े तीन एकड़ जमीन हरिजनों की ली गई थी। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इन लोगों को आज तक उस जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन लोगों का मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जुलाना में एक कालेज की सख्त आवश्यकता है। खासतौर पर जुलाना में एक लड़कियों के कालेज की बहुत आवश्यकता है। मैं एक बात जनसंख्या के बारे में कहना चाहूंगा। जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में एक पोस्टर एम०एल०ए० होस्टल में लगा हुआ है। उसमें लिखा है कि 500, 200 और 200 रुपये तब मिलेंगे जब शादी होने के बाद दो साल हो जायेंगे। इसमें लिखा है कि शादी के 2 साल बाद 500 रुपये, 200 रुपये और 200 रुपये मिलेंगे देवी रूपक योजना के तहत। दो साल की जो शर्त लगी है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस स्कीम को स्पष्ट करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : शेर सिंह जी, आपकी उम्र ढल गयी है। इस बारे में मैं जरा थोड़ा सा आपको बता दूं। इस स्कीम का यह मतलब है कि 6 महीने के अन्दर आप्रेशन होने के बाद यदि बच्चा दूसरा पैदा न हो तो, इसलिए यह शर्त लगा दी है। बाकी सरकार का फैसला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस फैसले के तहत 1300 केसिज की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और काफी सारा पैसा इस स्कीम के लिए दिया जा चुका है।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : चौधरी साहब, आपकी बात ठीक है। यह अच्छी बात है कि सरकार जनसंख्या पर कन्ट्रोल करने के लिए यह कदम उठा रही है और एक अच्छा नमूना सरकार पेश कर रही है। दो साल का मतलब यह है कि अगर शादी हुई तो एक साल तीन महीने तक उसको इन्तजार करना पड़ेगा और उसके बाद जब बच्चा होगा तो दो साल के बाद उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : ठीक है, स्पीकर साहब, अगर आप बोलने के लिए समय नहीं दे रहे तो मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्रीमती अनिता यादव (साहलावास) : स्पीकर साहब, आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं तहेदिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। समय का ध्यान रखते हुए कछ ही मिनटों में मैं अपनी बात रखूंगी। मैं माननीय साथियों को बताना चाहती हूं कि मैं अपनी बात अपने क्षेत्र तक सीमित रखूंगी। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनने का कष्ट करें। अगर किसी भाई ने कोई बात कहनी है या पूछनी है तो बाद में पूछें क्योंकि समय की पाबंदी है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि पिछली बार भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कह रही है कि हम महिलाओं का भी सम्मान करते हैं लेकिन मुझे बडे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले सत्र के दौरान भी मुझे बोलने का समय नहीं मिला था। अब भी मुझे लगता है कि कुछ ही मिनट बोलने के लिए मिलेंगे क्योंकि हाउस का समय समाप्त होने मे कुछ ही समय बचा है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से कहना चाहती हूं कि यहां पर सभी सम्मानित साथियों ने एस०वाई०एल० कैनाल का जिकर किया है। किसी ने कहा कि बादल की सरकार की वजह से यह नहर नहीं बनी। किसी ने कहा कि एग्रीमेंट पर देवीलाल जी के सिगनेचर थे तो दूसरी तरफ हमारी पार्टी कहती है कि चौधरी भजन लाल जी ने दस्तखत किए थे। इस मुद्दे पर मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि अगर सरकार किसानों की हितैषी है, किसानों के हित का दम्भ करती है तो मेरा कहना यही है कि प्रदेश का जो टोटल पानी है उसमें से समानान्तर पानी का बंटवारा पूरे प्रदेश में होना चाहिए। क्या सरकार ऐसा करेगी ? यदि करेगी तो ऐसा कब तक होगा, क्या इसके लिए सरकार कोई समय सीमा निर्धारित करेगी। दूसरे इसी के बीच में डीजल और पैट्रोल के भाव अभी सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने बढ़ाए हैं। सैन्ट्रल गवर्नमैंट में स्टेट गवर्नमैंट की पार्टी का सांझा होने के नाते इस तरह से जो डीजल और पेट्रोल के रेट्स बढ़ाए गए हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार अपने एम०पीज० की सुपोर्ट विदड्रा करवा कर केन्द्र सरकार पर कुछ दबाव तो डाल सकती है। अगर इसी तरह से रेट्स बढ़ते जाएंगे तो आगे चल कर किसानों का क्या होगा । (विघ्न) ठीक है मेरा राजनैतिक अनुभव कम है मुझे राजनीति में आए बहुत कम समय हुआ है। राजनीति में मैं नई हूं लेकिन मैंने अभी तक हमेशा अखबार के माध्यम से 50 पैसे से 30 पैसे या 20 पैसे पेट्रोल और डीजल के भाव प्रति लीटर बढ़ते देखे हैं लेकिन अब की बार तो सारी सीमाएं ही टूट गई हैं। डेढ़ रुपये प्रति लिटर के हिसाब से जो तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है उसके बारे में हरियाणा सरकार की नीति और नीयत क्या है मैं आपके माध्यम से उसकी जानकारी चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, महिला होने के नाते मैं शिक्षा पर ज्यादा बल देती हूं क्योंकि हमारे समाज को शिक्षा की बहुत जरुरत है (विघ्न) मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप अपने सदस्यों को समझा कर रखें कि ये मुझे बीच में बोलते हुए टोके नहीं (विघ्न) इनका यह क्या तरीका है (विघ्न) । मैं आप सब का सम्मान करती हूं लेकिन मैं किसी से भी डरती नहीं हूं मेहरबानी करके मुझे डिस्टर्ब न करें (विघ्न) मैं तो परमात्मा से डरती हूं और अपने माननीय मुख्यमन्त्री जी का भी आदर करती हूं। आप लोगों को मुझे बीच में डिसटर्ब नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगी । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, आप किसी भी मेम्बर से सीधे बात न करें आप चेयर को सम्बोधित करके बोलें। अब आप कांटीन्यू करें।

श्रीमती अनिता यादव : मुख्य मंत्री जी, आप अपने लोगों को समझा कर रखें कि वे बार बार मुझे डिस्टर्ब न करें। (विघ्न) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कह रही थी और शिक्षा के बारे में मेरी कुछ रिक्वैस्ट भी थी। जब से मैं विधायक बनी हूं तब से आज तक मैं देख रही हूं कि मुख्य मंत्री जी इन्फर्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी पर जोर देते रहे हैं और कम्पयूटर शिक्षा पर बल देते रहे हैं लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोसली गांव चार हजार की आबादी का एक गांव है जिसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। इन 36 बिरादरी के लोगों में घुमन्तु जातियों के लोग भी शामिल हैं। वहां पर करीब अढ़ाई सौ वोट लुहार जाति के हैं। स्पीकर सर, बड़े दुख: की बात है कि वहां पर एक प्राईमरी स्कूल तक नहीं है। मैंने यह बात हाऊस में पहले भी रखी थी और अब फिर आपसे अनुरोध है कि प्राईमरी स्कूल के सारे नॉर्म्ज वहां पर पूरे हैं और ग्राम पंचायत सरकार को प्राईमरी स्कूल खोलने के लिए जमीन देना चाहती है। वहां पर प्राईमरी स्कूल के सारे नॉर्म्ज कम्पलीट हैं इसके बावजूद भी वहां पर प्राईमरी स्कूल का कोई प्रावधान नहीं है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वहां पर नॉर्म्ज पूरे नहीं भी है तो भी कोसली मे नॉर्म्ज पूरे करके प्राईमरी स्कूल बना दिया जाए। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय बअुवा गावं का स्कूल बहुत पुराना है और वहां पर हमने 10 जमा दो का लड़कियों का स्कूल खोलने की मांग रखी थी। यह स्कूल जमा दो के लिए सारे नॉर्म्ज पूरे करता है लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बात पर मुझे टाल दिया कि उसका रैजोल्यूशन पहुंचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को प्रार्थना करना चाहूंगी कि 2001 का रैजोल्यूशन आया हुआ है। आपकी सरकार 1999 में बनी थी और 1999 से लेकर 2002 तक सारे रैजोल्यूशन भी भेजे जा चुके हैं लेकिन बअुवा गांव का गर्ल्ज स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है। हालांकि इस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी कहा था। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार इस स्कूल को अपग्रेड करेगी या नहीं यदि अपग्रेड करेगी तो कब तक करेगी ?

इसी तरह से बिरोहड़ गांव में लड़कियों का स्कूल है जो कि मातनहेल ब्लॉक में लगता है। उस स्कूल के सभी नार्मर्ज पूरे हैं, उससे 24' x 20' के कमरे हैं और उसमें जितने स्टूडैंट्स की संख्या होनी चाहिए उतने ही स्टूडैंट्स हैं। इस सब के बावजूद भी इस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी की और इनकी सरकार की लड़कियों के लिए अगर कोई अच्छी नीति है तो मैं आपके माध्यम से इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि यह गांव बहुत बड़ा गांव है और इस गांव से लड़कियां पढ़ने के लिए दादरी जाती हैं जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप इस स्कूल को अपग्रेड करने का कष्ट करें। स्पीकर

[श्रीमती अनिता यादव]

सर, रिवाड़ी जिले के दर्जनों स्कूल अपग्रेड हुए हैं लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे यहां पर कोई स्कूल भी अपग्रेड नहीं हुआ है। एम०एल० रंगा साहब थोड़ी देर पहले सुबह से यहां चश्मा लगाकर बैठे हुए थे उनके क्षेत्र में 10 सीनियर सकैण्डरी स्कूल, 9 हाई स्कूल और 5 मिडिल स्कूल अपग्रेड हुए हैं। स्पीकर सर साहलावास क्षेत्र के लोगों ने इनैलो को भी वोट दिए हैं लेकिन उन लोगों का बैडलक्क है कि एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं और मुख्य मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि अगर वहां पर महिलाओं को देखकर ही स्कूल अपग्रेड कर देते तो हमारे साथ न्याय हो जाता।

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनके वहां पर नार्मज पूरे नहीं होंगे तभी अपग्रेड नहीं हुआ होगा। हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्कूल नार्मज पूरे करते हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारे रैजोल्यूशंज की कापियां शिक्षा मंत्री जी को भिजवा देती हूं। ये 2001 की पास की हुई रैजोलयूशंज की कापियां हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर स्कूल अपग्रेड नहीं हुए हैं। (विघ्न) माननीय स्पीकर सर, पिछली बार भी हमें इस तरह से गुमराह किया गया था लेकिन अब यह रैजोल्यूशन मेरे पास है और मैं जो कुछ भी बोल रही हूं उसमें से ही बोल रही हूं। रैजोल्यूशन पास होने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा किया जाता है, यह बहुत ही बुरी बात है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, आप सभी जानते हैं कि दक्षिणी हरियाणा में बिजली, पानी, रोडज़ और परिवहन का बहुत बुरा हाल है। मैं इनके बारे में भी कहना चाहूंगी। माननीय परिवहन मंत्री श्री अरोड़ा जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। इस बारे में मैंने पिछली दफा भी रिक्वैस्ट की थी कि हमारे यहां पर यातायात साधनों की बहुत कमी है। हमारे यहां से लड़कियां कालेजों और स्कूलों में पढ़ने के लिए रिवाड़ी, दादरी और झज्जर जाती है। वहां जाने के लिए लड़कियां बसों और जीपों में लटक कर जाती हैं अगर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो मैं आपको दिखा सकती हूं, मैंने उसकी फोटोग्राफ निकलवा रखी है। उनको सदन के पटल पर रख सकती हूं। मेरी परिवहन मंत्री श्री अरोड़ा जी से प्रार्थना है कि वे टूटी हुई बसों को ही हमारे क्षेत्र में भेज दें। अगर ये ऐसा कर देंगे तो उन बसों से हमारे क्षेत्र की लड़कियां दूसरे क्षेत्रों में पढ़ने के लिए आराम से जा सकेंगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगी कि रिवाड़ी जिले को छोड़ कर बाकी सभी जिलों में डाईट और जे०बी०टी० ट्रेनिंग सैन्टर्ज हैं। लेकिन रिवाड़ी जिला एक ऐसा जिला है जहां पर इस किस्म का कोई भी टैक्नीकल एजुकेशन का या दूसरा कोई ट्रेनिंग सैन्टर नहीं है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में नाहड़ के खंड में गांव खुर्शीद नगर आता है। इसकी सैंकड़ों एकड़ भूमि ग्राम पंचायत के अधीन है और उसको वहां के लोग देने को तैयार हैं। अगर मुख्य मंत्री जी की इस तरफ नजरें इनायत हो जाएं तो हमारे इलाके का सुधार हो सकता है। बॉगर एरिया की वजह से हमारे जो लड़के और लड़कियों की शादियां होनी बंद हो गई थीं, अगर हमें एजुकेशन पूरी मिल जाए तो हमारे बच्चों के रिश्ते फिर से होने शुरू हो जाएंगे। इससे मैं समझती हूं कि हमारा दरिद्र भी दूर हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप वाइन्ड-अप करें।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। यह तो आई०जी० वाली बात हो गई कि अगर मुझे बिठाना ही था तो मुझे खड़ा ही क्यों किया। मैं बैठी हुई तो थी। अध्यक्ष महोदय, कम से कम मेरे जो टॉपिक हैं, जो प्वायंट हैं उनके बारे में मुझे तो बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप जल्दी वाईड-अप करें।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि हरियाणा सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए बड़ी सचेत है और इसके लिए हरियाणा सरकार की मैं सराहना भी करना चाहूंगी। यह सरकार लड़कियों की फ्री एजुकेशन और उनकी ड्रैसिज पर भी बहुत ध्यान दे रही है। इसके साथ ही मेरे हल्के में कोसली स्टेशन पर एक डी०ए०वी० संस्था है उस के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि वह संस्था बहुत महंगी है और मेरे हल्के में रहने वाले मां-बाप अपनी लड़कियों को 200-500 रुपये देकर पढ़ा नहीं सकते हैं। वे लोग बहुत गरीब हैं और डी०ए०वी० संस्था बहुत महंगी है वे लोग अपनी लड़कियों को अधिक नहीं पढ़ा सकते जिस के कारण उन लड़कियों की शादियां जल्दी करवा देते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि ऐसे कोई नार्मज बनाए जाएं ताकि उस संस्था को गवर्नमैंट संस्था में बदल दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो लड़कियों की शिक्षा में काफी हद तक प्रोग्रैस हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पानी के बारे में कहना चाहूंगी। मेरे साल्हावास में एक नाहड़ ब्लाक है और वहां पर 5-6 जगहों पर वाटर शैड स्कीमज़ बनी हुई हैं। उनके नाम भी मेरे पास हैं जैसे खुर्शीद नगर में है, कानड़वास में है, मातनहेल में है और गुड़यानी में है। इन पर हरियाणा गवर्नमैंट के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। उन पर करोड़ों रुपए लगने के बाद भी आज तक वहां पर वाटर शैड स्कीम लागू नहीं हुई है और न ही वह कामयाब हुई है। हमारी समस्या ज्यों की त्यों ही है। अध्यक्ष महोदय, हम वाटर सप्लाई के एस०डी०ओ० से मिले थे और उन्होंने कहा कि पीने के पानी के चार 15.00 बजे टैंकर आपके रेलवे स्टेशन पर भिजवा देंगे। मालनहेल में भी और दूसरे गांवों में भी इसी तरह की समस्या है। मेरे कहने का भाव यह है कि जो वाटर शैड स्कीमज़ के तहत करोड़ों रुपये की राशि हरियाणा सरकार द्वारा खर्च की गयी है उसका सदुपयोग होना चाहिये। खुर्शीदनगर, झाड़ीदा, कानड़वास जैसी जो वाटर शैड की स्कीम्ज हैं जोकि ठप्प पड़ी हैं उनको चलाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम महिलाओं को काफी हद तक पानी की सुविधा हो सकती है। आज महिलाएं काफी दूर-दूर तक जाकर पानी का एक घड़ा लेकर आती हैं और अपने परिवार का एवं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। महिला सशक्तिकरण दिवस के नाते मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इन स्कीम्ज को पुन: लागू करवाया जाए। इसी तरह से बिजली के बारे में आप सभी जानते हैं कि कहने के लिए तो कह देते हैं कि बिजली की उपलब्धता 43 प्रतिशत अधिक हुई है। गवर्नर महोदय के अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र किया गया है लेकिन मेरा रैजीडैन्स चूंकि सब डिवीजन पर है इसलिए इस नाते मैं सरकार को और मुख्य मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि हमारे यहां के उस एस०डी०ओ० की यह हालत है कि जब ट्रांसफार्मर जल जाता है और जब हम नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए जाते हैं तो वह कहता है कि कल आना, परसों आना और जब हम परसों जाते हैं तो वह कहता है मैं क्या करूं मेरे एम्प्लायी मानते ही नहीं हैं और न ही हमारे पास इसे ले जाने के लिए कोई साधन है। वहां के पावर स्टेशन की यह हालत है कि 28-28 दिन तक वहां पर जले हुए ट्रांसफार्मर पड़े रहते हैं। अगर वहां लोग अपने ट्रैक्टर लेकर जाते भी हैं तो वह ऐसे ही लौटकर आ जाते हैं। इस कारण कभी वहां एस०डी०ओ० पिट जाता है और कभी दूसरे लोग पिट जाते हैं। इस तरह का माहौल हमारे यहां बिजली का है और इसका असर आज की जैनरेशन पर विशेष रूप से स्टुडैन्टस पर पड़ रहा है। वहां पर बिजली जीरो पावर में आती है। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सरकार ने सड़कों का बहुत अच्छा जाल बिछा रखा है लेकिन तीन

[श्रीमती अनिता यादव]

चार सड़कें जो टूटी हुई हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। मेरा निवेदन है कि लोन्द्राली से गुंडाहेड़ा तक एक किलोमीटर की सड़क, रेलवे स्टेशन से जुड़डी की दो किलोमीटर तक की सड़क को ठीक करवाया जाए। नाहर से सादत नगर सड़क पर कच्ची मिट्टी डाली हुई है इसको भी ठीक करवाया जाए। तुमाना से श्यामनगर तक की सड़क पर भी डेढ़-डेढ़ फुट के गढ्ढे हैं। इसी तरह से सुधराना से गिलोड गोरिया एवं खानपुर खुर्द तक की सड़कों में बहुत गढ्ढे हैं इनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। इसी तरह से साल्हावास से बुहरावास एवं लिलेहड़ी तक जो सड़क जाती है, क्या सरकार उसकी भी इन्वैस्टीगेशन करवाएगी कि बनने के बाद उसमें इतनी जल्दी गढ्ढे क्यों पड़ गए। इसी तरह से मैं हरिजनों के बारे में बात जरूर कहना चाहूंगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, आप बैठिए। अब दान सिंह बोलेंगे।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी अब कोई बात रिकार्ड न की जाए।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस अभिभाषण को पढ़ते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने कल्पना चावला जी का जिक्र किया। यह वाकई में एक हृदय विदारक हादसा था। इससे पूरे राष्ट्र की भावना जुड़ी हुई थी खास तौर से युवा वर्ग की। इसलिए न केवल प्रदेश और देश बल्कि पूरी दुनिया ने इस बात का शोक मनाया। कल्पना चावला हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया के छात्रों की एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थीं और आज यदि उसकी याद में हम कुछ करते हैं तो वह कम से कम उसके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एस०वाई०एल० का जिक्र किया। पिछले 36 साल से जब से हरियाणा बना है तब से एस०वाई०एल० का जिक्र होता रहा है। यहां का किसान पानी की समस्या से जूझता रहा है और खास तौर पर वह क्षेत्र जहां से मैं विधायक हूं। हरियाणा का आम आदमी कहता है कि एस०वाई०एल० उनकी जीवन रेखा है। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी दुखती रग है कि जब भी इसका जिक्र आता है तब दोनों प्रदेशों के लोगों में राजनीतिक गर्मी आ जाती है और हर आदमी अपने अपने अधिकारों की लड़ाई की बात करता है अगर यह लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो वह पानी खेतों में तो नहीं आएगा लेकिन हमारी आंखों में पानी जरूर आ जाएगा। मेरा सभी राजनीतिक दलों के प्रधानों से निवेदन है कि राजनीतिक स्वार्थों से और निजी हितों से ऊपर उठकर प्रदेश की इस समस्या को इन विषम परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। आज दक्षिणी हरियाणा के अंदर पानी की कमी की वजह से नांगल चौधरी के दोहान पच्चीसी के 25 गांवों ने चुनावों का बायकाट किया था। हमारे यहां के लोगों को पीने के पानी की समस्या ने परेशान कर रखा है और बड़ी विचित्र बात यह है कि आजादी के 55-56 साल के बाद भी कोई सरकार वहां लोगों को मूलभूत सुविधायें प्रदान नहीं कर पाई है। 25 गांव चुनावों का इसलिए बहिष्कार करते हैं क्योंकि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ 20 गांवों के लोग इसलिए चुनावों का बहिष्कार

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करते हैं कि वहां सेम की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है इससे वहां पर इस सेम की समस्या से निपटा जा सकेगा। दोनों तरह की समस्याओं का कोई न्यायसंगत समाधान निकाला जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। आज जो वर्तमान में पानी उपलब्ध है उसका न्यायोचित बंटवारा किया जाए ताकि हमारी प्यासी जमीन को पानी मिले। आज जब भी सूखे की बात आती है तो आम आदमी कहता है कि राजस्थान के जैसलमेर में और बाड़मेर में सबसे ज्यादा सूखा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में नांगल चौधरी और नांगल खैर में भी इससे कम खराब स्थिति नहीं है जहां मीलों तक हरा पत्ता तक देखने को नहीं मिलता। इस समस्या का गंभीरता से समाधान होना चाहिए। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** पिछले साल पूरा प्रदेश सूखे की भयंकर चपेट में रहा और जब किसी से राम नाराज हो जाता है तो राज की तरफ नजर जाती है। वह सोचता है कि राम की तरफ से इंसाफ नहीं मिला तो राज की तरफ से ही इंसाफ मिल जाए लेकिन अफसोस यह रहा कि राज से भी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। वहां के लोगों को 180 रुपये प्रति मन के हिसाब से तूड़ी लेनी पड़ी और जबकि वहां के लोग उस मार को सहन करने की स्थिति में नहीं थे और उन्हें इसके लिए अपने पशुधन को औने पौने दामों में बेचना पड़ा लेकिन वहां सरकार की तरफ से एक तिनका भी चारा नहीं पहुंचाया गया। सूखा राहत के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सरकार द्वारा 3, 4 और 5 रुपये जो मुआवजा किसानों को दिया गया उसका जिक्र किया है जो मैं समझता हूं कि किसान के साथ एक बहुत ही बड़ा मजाक है। मुख्य मंत्री जी जो स्वयं एक किसान के बेटे हैं और अपने आपको किसानों का नेता कहते हैं और जिन्होंने किसानों को अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाकर राज प्राप्त किया है। एक सभा के अंदर अखबार के माध्यम से मुझे यह पढ़ने के लिए मिला कि दक्षिणी हरियाणा के किसान दो रुपये का बाजरा बिजाई करके चार हजार रुपये की मांग करते हैं यह न्याय संगत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे यहां पैदा ही बाजरा होता है तो हम माल्टा और किन्नू कहां से लगा देंगे। कम से कम उन किसानों के दर्द को समझना चाहिए और उन्हें जो न्यायोचित मुआवजा बनता है वह देना चाहिये था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद आता है शिक्षा का मसला । शिक्षा एक ऐसा गहना है जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति का रूप निखार देता है। उसके व्यक्तित्व को बढ़ा देता है। अगर किसी प्रदेश के नागरिक शिक्षित हैं तो बहुत बड़ी धरोहर साबित होते हैं। खासतौर से मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगा कि अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो शिक्षा उस तक सीमित नहीं रहती बल्कि परिवार के बाकी लोगों तक और समाज तक पहुंच जाती है। उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है उनके लिए जितने शिक्षा के साधन जुटाये जायें उतने ही कम हैं। आज अभिभाषण के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया गया कि हरियाणा में एक और विश्वविद्यालय चौधरी देवी लाल जी के नाम से सिरसा के अन्दर खोला जा रहा है। इस बात की हमें खुशी है कि वहां पर एक और विश्वविद्यालय खोला जा रहा है ताकि वहां के लोगों को और शिक्षित किया जा सके। लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि दक्षिणी हरियाणा में मेवात और अहीरवाल का क्षेत्र है और जिसे पिछड़ापन के नाम से जाना जाता है वहां पर आज भी शिक्षा के नाम पर कोई विश्वविद्यालय नहीं खोली गई है। हिसार जैसे पुराने जिले में दो-दो विश्वविद्यालय हैं और अब एक सिरसा में भी खोला जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में पहले से ही है, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय भी हिसार में है। दूसरी तरफ रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद के अन्दर कोई विश्वविद्यालय नहीं है। हम तो अपेक्षा करते थे कि उधर चौधरी देवी लाल जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोला जायेगा

[राव दान सिंह]

तो दक्षिणी हरियाणा में भी राव तुलाराम जी के नाम से एक विश्वविद्यालय देकर हमारी जो न्यायोचित मांग और मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, वह हमें दिया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आगे हमारे दुख को बढ़ाने के लिए एक और बात सुनने को मिली है वह यह है कि महेन्द्रगढ़ जिला को एम०डी० यूनिवर्सिटी से हटाकर सिरसा के साथ जोड़ा जा रहा है। एम०डी० यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र से 100 किलोमीटर के फासले पर है और सिरसा 250 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। इससे आर्थिक रूप से उन अभिभावकों और छात्रों पर पड़ेगा इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हो सके तो हमारे यहां विश्वविद्यालय खोला जाये वरना हमारे जिले की एफिलिएशन सिरसा की बजाए एम०डी० यूनिवर्सिटी के साथ ही रखी जानी चाहिये। हमारे साथ तो वही हुआ, **"चौबे जी गये थे छब्बे जी बनने लेकिन दूबे जी बनकर ही रह गए"** इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र पर पूरा ध्यान देकर हमारी इन समस्याओं को देखा जाये और उनको सुना जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद आता है जनसंख्या का सवाल। आज पूरे राष्ट्र की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वह है जनसंख्या की। क्योंकि आज एक हाथ के लिए हम साधन जुटाते हैं और 999 हाथ बेरोजगारों के लिए खड़े हो जाते हैं। इस समस्या के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो 2020 में हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जायेगा और हमारी समस्याओं में दिन रात का इजाफा हो जायेगा। चाईना जैसे कण्ट्री ने जो हमेशा जनसंख्या में सबसे आगे था उसने जनसंख्या पर नियन्त्रण किया है। सरकार ने एक नया फार्मूला देकर के इस बारे में थोड़ी गम्भीरता दिखाई है उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं लेकिन वह काफी नहीं है इसके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के साथ साथ इसके लिए कुछ लिमिटिड कोअर्सिव मैथड अपनाकर जिनके कारण दबाव बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बात की जाती है, वे अवश्य अपनाने चाहियें ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : दान सिंह जी आप वाईड-अप कीजिए।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि की बात आती है भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहां का किसान खून के आंसू रोता है क्योंकि उसकी इनपुट ज्यादा है और कमाई कम है। कमाई कम इसलिए है कि जो उसकी लागत में आता है चाहे खाद हो, चाहे डीजल हो, यूरिया हो उनकी कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और जो उसकी फसल आती है उसके भाव घटते जा रहे हैं। इसलिए एक सामंजस्य आपस में नहीं बैठ पा रहा है। इसलिए आज कृषि घाटे का व्यवसाय बनकर रह गया है। इसलिए सरकार को चाहिये कि चाहे कृषि के लिए वह सबसिडी दे या केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि इस तरह की चीजें जो कृषि के काम में आती हैं उन के इस तरह से भाव न बढ़ने दिये जायें। तब जाकर किसान की बात आगे चल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई का सवाल है दक्षिणी हरियाणा के अन्दर स्प्रिंकलर सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए वहां पर बिजली की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। अगर इस साल भगवान नहीं सुनता तो एक विषम परिस्थिति और कठिन परिस्थियों से लोगों को गुजरना पड़ता। यह तो ऊपर वाले ने साथ दे दिया जिसकी वजह से हमारे यहां बिजली की कमी को ज्यादा महसूस नहीं किया गया। इसलिए भविष्य में इस समस्या को समझते हुए सरकार को वक्त रहते हुए इस समस्या के समाधान की ओर सोचना चाहिए। उसके

बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र करना चाहूंगा सड़कों का। जहां तक सड़कों का सवाल है कुछ काम सड़कों का सरकार ने अवश्य किया है इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मुख्य सड़कें हैं जैसे हांसी से भिवानी दादरी होते हुए महेन्द्रगढ़ आने वाली और नारनौल से कोटपुतली को जाने वाली सड़क है उसका न तो लेवल है और वह एक साइड से आधी है हर रोज इतने भारी वाहनों को वहां से आना जाना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाईंड अप कीजिए।

राव दान सिंह : उस सड़क पर एक्सीडैंट्स की अगर रेशो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 4-5 एक्सीडैंट्स प्रतिदिन की एवरेज आती है इसके लिए सरकार तुरन्त प्रभाव से उसकी तरफ ध्यान देकर उस सड़क को चौड़ा करवाये और उस सड़क की कारपैटिंग भी करवाई जाये ताकि वह सड़क चलने लायक बन सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जन-स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दान सिंह जी अब आप समाप्त करें।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि हमारे वहां 70 लीटर पानी की बात तो दूर आज के दिन वहां दो दिन में या एक दिन बाद लोगों को पीने का पानी मिलता है। इस समय मार्च का महीना है जब अब यह हालात हैं तो सरकार को सोचना चाहिए कि मई और जून के महीने में, जब महेन्द्रगढ़ और नारनौल में लू चलेंगी, तब वहां की जनता का क्या हाल होगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि समय रहते पीने के पानी का उपाय, वहां के लोगों के लिये किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। (विघ्न) महेन्द्रगढ़ में सी०एच०सी० बना हुआ है लेकिन वहां पर एक भी लेडी डाक्टर नहीं है। पता नहीं कितनी ही महिलाओं ने वहां प्रसूति के दौरान अपनी जानें गवाई हैं इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि महेन्द्रगढ़ के सी०एच०सी० में लेडी डाक्टर की व्यवस्था की जाए ताकि वहां की जनता को इस समस्या से समाधान मिल सके। इस बारे में मैं पहले भी कई बार अनुरोध कर चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त नगरपालिका और नगर विकास के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ में नगरपालिका है और गोयल साहब भी वहां पर दो-तीन बार गये हैं। महेन्द्रगढ़ नगरपालिका के लिए जो ग्रांट दी जाती है वह पैसा तो कर्मचारियों की सैलरी में ही पूरा हो जाता है। महेन्द्रगढ़ में रात की बात तो छोड़ें दिन में भी चलना मुश्किल होता है। स्वयं मुख्य मंत्री जी भी वहां गये थे। गऊशाला रोड़ के बारे में पिछली दफा भी मैंने लिखकर दिया था लेकिन वह रोड़ आज तक नहीं बनी है। उपाध्यक्ष महोदय, हम मुख्य मंत्री के अलावा और किसके पास जायें। मैं मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह गऊशाला रोड़ जल्दी से जल्दी बनवायें ताकि वहां के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि सरकार शिक्षा की तरफ काफी ध्यान दे रही है पता नहीं मुख्य मंत्री जी की हमारे से क्या नाराजगी है। हमारे वहां कनीना शहर में लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से पैसा एकत्रित करके लड़कियों के कालेज के लिए एक बिल्डिंग बना दी है लेकिन वहां पर लड़कियों के कालेज के लिए सरकार एन०ओ०सी० न देकर हमारे वहां की लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से

[राव दान सिंह]

हो सकती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कनीना में कालेज के लिए एन०ओ०सी० दे दी जाये ताकि वहां की लड़कियां भी पढ़कर आगे बढ़े और कल्पना चावला की तरह प्रदेश का नाम रोशन करें। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि तथ्यों के तोड़ने-मरोड़ने से काम नहीं चलेगा बल्कि असलियत में काम करके दिखाने होंगे। धन्यवाद।

श्री कंवर पाल (छछरौली) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के कार्य "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत किए हैं और जो कार्य सरकार ने किए हैं वे अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। जहां तक बिजली की बात है इस बारे में बहन अनिता यादव जी ने कहा कि एक-एक महीने तक ट्रांस्फार्मर नहीं बदले जाते, वे बिल्कुल गलत बात कह रही थीं। आज हमें महसूस हो रहा है कि ट्रांस्फार्मर बड़ी आसानी से बदले जा रहे हैं। एक समय था जब ट्रांस्फार्मर बदलवाने में लोगों की जूतियां टूट जाती थीं लेकिन ट्रांस्फार्मर नहीं बदला जाता था। आज केवल एक बार जाने से ही ट्रांस्फार्मर बदल भी दिया जाता है और यदि नया ट्रांस्फार्मर लगाना हो तो वह भी एक बार जाने से ही लग जाता है। इस तरह से काम बड़ी जल्दी से हो रहे हैं और मुख्य मंत्री जी की यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, जो पैसा मुख्य मंत्री जी "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत देकर आते हैं उस पैसे से भी जल्दी से काम हुए हैं वह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ मुख्य मंत्री जी ने जो इतनी दरियादिली दिखाई है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद, करता हूं और मेरी एक मांग भी है अपने हल्के के लिए। छछरौली एक बड़ा ग्रामीण हल्का है। वहां पर कोई कालेज नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब भी वहां पर आते हैं तो हर बार मेरी मांग होती है और मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि वहां पर लड़कियों का कोई कालेज नहीं है इसलिए वहां पर एक लड़कियों का कालेज अवश्य खोला जाये। हमारे हल्के की यह जायज डिमांड है इसलिए मुख्य मंत्री जी हमारी इस मांग को पूरा करने की कृपा करें। मेरे हल्के में एक माण्डेवाला बांध बन रहा है। इस बांध के पूरा न बनने की वजह से मेरे हल्के की काफी बड़ी जनसंख्या को खतरा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि जब मैंने पिछली बार इनके सामने मांग रखी तो इन्होंने इसमें व्यक्तिगत इन्ट्रैस्ट लिया। मैंने भी इनके सामने इस समस्या के बारे में एक बार नहीं दस बार अनुरोध किया और हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए इन्होंने इसे पूरा करवाने की पूरी कोशिश की। मैं बताना चाहूंगा कि सी०डब्ल्यू०सी० की वजह से यह काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अब मुझे पता चला है कि 3 लाख क्यूसिक पानी का कोई फैसला हुआ है। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं। इसी प्रकार से मेरे हल्के की एक सड़क है बीकेड़ी। मैं बताना चाहता हूं कि आज से 30 साल पहले जब यह सरकार बनी थी तब से लेकर आज तक किसी सरकार ने इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया था यानी इस पर कोई काम नहीं करवाया। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आज इस सड़क पर काम लगा हुआ है। आज से पहले किसी भी सरकार ने इस सड़क की चिन्ता नहीं की। मैं बताना चाहता हूं कि इस सड़क पर करीब 100 स्टोन क्रैशर पड़ते हैं और यह रोड सिंगल है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सिंगल रोड को डबल रोड बनाया जाये। इसी प्रकार से मेरे हल्के की 5 पुलियां और पुल

माननीय मुख्य मंत्री जी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत मन्जूर करके आये थे और मुझे कोई शंका नहीं कि यह काम नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम होगा और निश्चित रूप से होगा। क्योंकि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि काम न हो। लेकिन मेरा अनुरोध है कि यदि यह काम जल्दी हो जाये तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहां पर सभी कांग्रेसी एम०एल०एज० एस०वाई०एल० नहर का जिकर कर रहे थे। इस मुद्दे पर इनकी एकता और गंभीरता का पता इसी बात से चलता है कि सभी 20 के 20 विधायक इस मामले में इकट्ठे नहीं हैं। एक दिल्ली में रैली करता है तो दूसरा रोहतक में रैली करता है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि पानी दे कौन नहीं रहा। केन्द्र सरकार नहीं दे रही या स्टेट गवर्नमैंट लेना नहीं चाहती। आज तक ये कहते रहे हैं कि चौटाला साहब और बादल साहब की मिलीभगत के कारण पानी नहीं मिला। पहले कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था जबकि आज कोर्ट का फैसला आ गया है। आज उस कोर्ट के फैसले को कौन नहीं मान रहा। कांग्रेस नहीं मान रही या हरियाणा सरकार नहीं मान रही या केन्द्र सरकार नहीं मान रही। इन लोगों की एक परम्परा ही है कि जब इनके हितों पर आंच आयी तो इन्होंने यानि कांग्रेस ने कभी कोर्ट का फैसला नहीं माना, चाहे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहा हो या चाहे कर्नाटक की सरकार रही हो और चाहे आज पंजाब की सरकार हो। खाद के मूल्य बढ़ाये जाने पर ये कहते हैं कि हमें उनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। मै इनसे कहना चाहता हूं कि अगर हरियाणा के हित इनको प्रिय हैं तो इन लोगों को जोर शोर से कहना चाहिए कि हरियाणा को पानी दो अगर पानी नहीं देते तो हम आपकी पार्टी को यानि कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं, हम कांग्रेस में नही आयेंगे। इनको कहना चाहिए कि हम ऐसी निकम्मी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी पार्टी में हम नहीं रहेंगे जो हमारे हितों पर कुठाराघात करती हो। (शोर एवं विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अन्दर एक बहुत बड़ी समस्या गन्ने की है। उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा रेट हरियाणा के किसानों को मिल रहा है। कहीं पर 104 रुपये, कहीं पर 106 रुपये और कहीं पर 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट मिल रहा है लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में, अम्बाला में, यमुनानगर में और कुछ इलाका कुरुक्षेत्र का भी है जिसमें प्राइवेट मिलें लगी हुई हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें गन्ने का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। मेरी सरकार से मांग है कि गन्ने का हमें पूरा मूल्य मिलना चाहिए। इस बारे में हम माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले तो इन्होंने कहा कि यह तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने मिल वालों के लिए फैसला किया है कि वह इतना पैसा देंगे लेकिन उन पर कोई रोक नहीं लगायी गई जिससे जो प्राईवेट मिलें गन्ना पीड़ रही हैं निश्चित रूप से उन मिलों को भी घाटा होगा। जब उस घाटे की भरपाई सरकार करेगी तो फिर हमारे घाटे की भरपाई क्यों नहीं हो सकती। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये। वहां पर किसानों ने आंदोलन किया है, स्ट्राइक की है, मिल के सामने शांतिप्रिय तरीके से भूख हड़ताल की है। इन लोगों ने शांतिप्रिय तरीके से रेट बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। लेकिन दुःख इस बात का है कि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया यानि कोई चिन्ता नहीं की। मैं इसलिए यह बात रख रहा हूं कि यदि लोग तोड़फोड़ करेंगे तो सरकार उनकी बातें सुनेगी और जब रेट बढ़ाने के लिए और अपनी मांग मनवाने के लिए लोग शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करेंगे और अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो भविष्य में इसके परिणाम गंभीर होंगे। इससे लोगों में एक मैसेज जाएगा कि जो लोग तोड़फोड़ करेंगे उनकी बात सुनी जायेगी और जो लोग शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन करेंगे सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस

[श्री कंवर पाल]

तरह का जो भेदभाव हो रहा है यह नही होना चाहिए और हमें जो कम पैसा मिल रहा है उसका ध्यान रखा जाये क्योंकि हम भी हरियाणा के किसान हैं। एक डोल के साथ लगते किसान को तो 100 रुपये का भाव मिलता है और दूसरे डोल के साथ लगने वाले किसान को 93 रुपये मिल रहे हैं। हमारे साथियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है मैं समझता हूं इस मामले में भेदभाव न किया जाये और इस भेदभाव को समाप्त किया जाये ।

दूसरा मेरा एक और अनुरोध है कि रॉयल्टी का जोन सिस्टम डिवैल्प किया है और सरकार कह रही है कि उससे उनकी आमदनी बढ़ी है। निश्चित रूप से आमदनी बढ़ी है इसमें कोई शंका नहीं है। जितनी रॉयल्टी हमारे यहां पर पहले होती थी उससे लगभग चार गुणा आमदनी सरकार की बढ़ रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मेरा मानना है यह पैसा हम दोबारा वहीं पर खर्च करते हैं। जैसे रॉयल्टी के रेट्स बढ़े हैं वहीं बजरी ज्यादातर सरकार इस्तेमाल करती है। कहीं पर कटी हुई बजरी है तो कहीं पर स्टोन क्रशर की है वह भी सरकार ही इस्तेमाल कर रही है। जब उसका रेट बढ़ा है तो सरकार जो ठेके देती है या किसी काम का ठेका देती है तो काम के रेट्स बढ़ते हैं इस प्रकार लगभग वहीं पैसा सरकार से दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी बात मेरी यह है कि क्रैशर जोन बनने से केवल एक दुकानदार बचा है उसी के पास चीजें हैं और उसी से आप खरीद रहे हैं। मुझे इस बात का नहीं पता हो सकता है सरकार से कोई गलती हुई होगी लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। कोई भी हाईऐस्ट रेट निश्चित् नहीं हुआ। कोई ऐसा रजिस्टर रेट निश्चित नहीं हुआ कि इससे जयादा आप नहीं लगा सकते हैं। अकेले दुगना होने की वजह से रेट इतने बढ़ गए हैं कि जहां 300 रुपये रेट था वहां पर 600 हो गया और जहां 600 था अब 1200 हो गया है। यदि इसी तरीके से चला तो कल यह दो हजार या तीन हजार भी हो सकता है। सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इस पर दोबारा से गौर किया जाए और इसके बारे में नियम निश्चित कर दें कि इससे जयादा रेट नहीं लगा सकते। इससे सरकार को भी लाभ होगा और जो उपभोक्ता है उसको भी लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक मांग पापलर के बारे में भी है। सरकार की मांग है और सरकार की इच्छा भी ऐसी रहती है कि ग्रीनरी बढ़नी चाहिए। मेरे हलके में पापलर की बहुत बड़ी फसल होती है। जैसे हरियाणा में गेहूं और धान हो रहा है, हमारे यहां उसी तरह से पापलर की फसल हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इसको देखा है और वे बहुत खुश भी हुए थे और उन्होंने मुझ से कहा कि तेरे हल्के में तो बड़ी ग्रीनरी है लेकिन आज स्थिति यह है कि पापलर का रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया है और इसके बावजूद भी सरकार जोर दे रही है पेड़ लगाने पर। हमारे यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई है सरकार उसका समाधान करे। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर जा कर झूठ कहते हैं कि हमारे टाईम पर पापलर का रेट 500 रुपये होता था अब इस सरकार में यह रेट कम हुआ है। हमारी सरकार आएगी तो हम इसके रेट फिर बढ़ा देंगे लेकिन कोई योजना इनके पास है नहीं रेट बढ़ाने की और न इनके पास काई सुझाव है कि ये कैसे रेट्स बढ़ाएंगे। उस टाईम तो पापलर ही कम पैदा होता था इसलिए उसका रेट ज्यादा था। (विघ्न) मांगे राम जी, आजकल वहां पर पोपुलर बहुत ज्यादा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में फैक्टरियां लगा रहे हैं कोई न कोई तरीका निकाल कर उस क्षेत्र में भी कोई फैक्टरी वगैरा लगवा दें जिससे किसानों को पोपुलर का सही रेट मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : कंवर पाल जी , अब आप वाइंड अप करें।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा एक अनुरोध है कि हमारे यहां पर गऊसदन है और उसमें लगभग 250 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी अनुरोध किया था कि उसका उपयोग हो सकता है। आज के दिन वहां पर लगभग 6-7 गाय हैं लेकिन उस जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा। मेरा अनुरोध है कि इस जमीन को ठीक करके वहां पर गौशाला खोल दी जाए वहां पर डी०सी० को उसका चेयरमेन बना दिया जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाऊस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बड़ी संख्या में पशु भी रखे जा सकते हैं और उस जगह का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। डिप्टी स्पीकर सर, हमारी कमेटी अभी महाराष्ट्र में गई थी और वहां की कमेटी की हमारी कमेटी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा कि आपको विधायक निधि कितनी मिलती है। हमने बड़े फख्र से कहा हमारे यहां पर विधायक निधि की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे मुख्य मंत्री जी जिस हल्के में भी जाते हैं वहां पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसके बाद वहीं पर पैसा बांटते हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि आपको विधायक निधि कितनी मिलती है मैंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरोड़ा साहब, आपने कहा था कि पक्षपात करके विकास करते हैं जब कि हमने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है (विघ्न) उन्होंने मुझे कहा कि जब आपके पास विधायक निधि ही नहीं हैं तो सारा साल आपका विधायक करता क्या है तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जगह ऐसा होगा। आपके नेतृत्व में अच्छा काम भी हुआ है। मैं इस बात से खुश हूं कि मुख्यमंत्री जी काम करने के लिए पर्याप्त पैसा देते हैं और कोई काम नहीं बचता है लेकिन जो 10-20 हजार रुपये के छोटे-छोटे काम हैं वे रह जाते हैं। जब मुख्य मंत्री जी से कोई पैसा मांगने जाएगा तो वह सोचेगा कि 5-7 लाख रुपए मांगेगा 10-20 हजार रुपए क्या मांगने हैं। जो छोटे छोटे काम हैं उनके लिए अगर विधायक नीधि मिले तो वे सब छोटे छोटे काम हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाइंड-अप करें।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी मांग है। गांवों में गरीब हरिजन भी रहता है और दूसरे लोग भी रहते हैं। उनके पास घर तो जैसा तैसा है लेकिन उनके पास कोई दूसरी जगह नहीं है। उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। पहले भी सरकारों ने उनको बाड़े काटकर दिए थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन गरीब लोगों का इस देश और हरियाणा प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ा हाथ है, तो उन गरीब आदमियों की प्रगति के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको

[श्री कंवर पाल]

छोटे-छोटे बाड़े काट कर दिए जाएं ताकि वे वहां पर गोबर, कूड़ा कर्कट डाल सकें । इन शब्दों के साथ ही मैं अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में अपना अभिभाषण रखा है उसे देखकर मन को बहुत तकलीफ हुई। मुझे इस बात का बेहद दु:ख होता हैं कि आज वे पिछड़े हुए राज्य जिसका हिन्दुस्तान के नक्शें पर कहीं कोई नामोनिशान नहीं हुआ करता था वहां पर अच्छी लीडरशीप की वजह से बहुत तरक्की हो रही थी और हरियाणा जैसा प्रदेश जिसका इस देश में ही नहीं दुनिया में नाम हुआ करता था, आज तानाशाही की वजह से प्रगति में बहुत पिछड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महादेय, यहां एस०वाई०एल० के बारे में कई माननीय साथियों ने चर्चा की है। आज एस०वाई०एल० का पानी लाने का मुद्दा नहीं रह गया है। बल्कि एस०वाई०एल० वोट बनाने का मुद्दा बन चुका है। इस पार्टी एस०वाई०एल० में से वोट निकालने में लगी हुई है। पानी लाने में किसी पार्टी की कोई रुचि नजर नही आती है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि इस एस०वाई०एल० को बनाने में प्रदेश का और देश का बहुत खर्चा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सैन्टर गवर्नमैंट के खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया है। उन्होंने कहा कि इराडी ट्रिब्यूनल इतने सालों से बिना कोई काम किए तनख्वाह ले रहा है। पब्लिक का करोड़ों रूपया उस पर खर्च हो रहा है। आज हरियाणा की सरकार की पार्टी एन०डी०ए० की सरकार में पार्टनर है। इससे पहले चौधरी देवी लाल जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और देश के उप-प्रधान मंत्री भी रहे हैं । उस वक्त से ही इराडी ट्रिब्यूनल के रिक्त पदों का सिलसिला चला आ रहा है लेकिन आज तक इराडी ट्रिब्यूनल के पदों को भरने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वह सारे का सारा मुख्य मंत्री जी के गृह जिले को जा रहा है। इन्हें तो इसी बात में फायदा है कि यदि एस०वाई०एल० न भी बने तो इनके खेतों में कम से कम पानी तो लगता रहेगा। इसलिए इनको एस०वाई०एल० बनने से या न बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा नुक्सान गुड़गांव, फरीदाबाद, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और नारनौल के किसानों को हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं किसान परिवार से सम्बन्ध रखता हूं और किसानों का भला चाहता हूं आज पंजाब में जाकर देखें कि उन्होंने पंजाब में कांट्रेक्ट फार्मिंग का इतना अच्छा प्रचार किया और वहां पता नहीं कितने हजार एकड़ भूमि कांट्रेक्ट फार्मिंग में अनुबंधित की है। उन्होंने फसल बदलाव को इतना बढ़ावा दिया है कि आने वाले दिनों में पंजाब देश का कृषि के मामले में अग्रणी राज्य बनेगा। आज हरियाणा में फसल चक्र के नाम पर हमारी धरती का उपजाऊपन खत्म हो रहा है। आज हमारे किसान फसल चक्र में बदलाव न होने की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। हमारी सरकार की इस बारे में कोई नीति नहीं है। अगर यह सरकर किसानों का हित चाहती है तो फसल चक्र में बदलाव के बारे में इनको शिक्षित करने के बारे में प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी हंसी आती है जब यह सरकार गेहूं और धान के एम०एस०पी० का बहुत प्रचार करती है कि मैंने बढ़वा दिया मैंने घटवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस हरियाणा में और भी बहुत सी फसलें पैदा होती हैं उनका भी एम०एस०पी० होता है जैसे सरसों, बाजरा, दालें एवं तिलहनें इस तरह की फसलें हैं। क्या मुख्यमंत्री जी या इनका कोई मंत्री बताएगा कि आज तक ये किसी मंडी में जाकर इसको

देखने गए कि जो इन फसलों का एम०एस०पी० फिक्स हुआ है क्या उस पर कोई एजेंसी खरीद कर भी रही है या नहीं। लेकिन इस ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। इसका नतीजा यह है कि सरकार, प्रशासन और किसान केवल धान और गेहूं के पीछे ही पड़े हुए हैं जबकि सरकार के पास इनको रखने के लिए जगह भी नहीं है। अगर सरकार किसान का हितैषी बनना चाहती है तो उसको दालें, तिलहनों एवं बाजरा जैसी फसलों पर भी ध्यान देना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लिए सोयाबीन की फसल वरदान साबित हो सकती है इसलिए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी सोयाबीन की फसल का कोई जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज की दुनिया के अंदर सबसे जयादा अगर जरूरत और मांग है तो वह सेहत के लिए सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों की है। मध्यप्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान जैसे प्रदेशों ने सोयाबीन की खेती को बढ़ावा दिया है और किसान को सबसिडी दी है एवं उसकी उत्पादित फसल को उन्होंने खरीदा है। लेकिन हरियाणा में सोयाबीन का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि आज हरियाणा में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज हरियाणा के अंदर मात्र एक परिवार का राज चल रहा है । * * * इसी तरह से चाहे सरकार का मामला हो, चाहे विधान सभा का मामला हो जैसे आज सुबह से बिठा रखा है यह कोई तानाशाही है क्या यह कोई तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह विधायकों के बारे में कहा गया है वह रिकार्ड न किया जाए। दलाल साहब, आप ये शब्द बोलें जो ठीक हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा में पिछले दो सालों से जे०बी०टी० में कोई एडमिशन नहीं हुई है क्या यह कोई घर की हुकूमत है। बच्चे जो जे०बी०टी० में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको दाखिला दिया जाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उसको इसका कारण बताना चाहिए। पिछले दो वर्षों से हरियाणा में जे०बी०टी० में कोई दाखिला नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि इसमें सरकार की नीयत में बदनीयत छिपी हुई है। यह इन जे०बी०टी० सैंट्रर्ज को खत्म करके अपने अपने चहेते इलाकों में ले जाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम के अभिभाषण प्रदेश की जनता के हिसाब से तैयार हुआ करते हैं कि किस प्रदेश में कहां सिंचाई पर पैसा लगाना है, किस प्रदेश में कहां शिक्षा पर खर्च करना है, कहां पी०डब्ल्यू०डी० की सड़कों को ठीक करना है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमत्री के इलाके के अलावा कोई और जगह पर हरियाणा में काम करके दिखाएं। मुझे अफसोस होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों पर कि उनको यहां पर खम्भे पर लिखा हुआ पढ़ाया जाता है। सर, हम हमेशा के लिए विधायक बनकर नहीं आये हैं, सरकार हमेशा के लिए बनकर नहीं आयी है, मुख्यमंत्री जी हमेशा के लिए बनकर नहीं आये हैं हमेशा के लिए ये हरियाणा के मालिक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारें आयी हैं और जाती रही हैं। बड़े-बड़े शहनशाह और तानाशाह हुए हैं वह हरियाणा की धरती पर धूल चाटते हुए नजर आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मेवात डिवैल्पमैंट एजैंसी में करोड़ों रुपये का घपला हुआ है मौहम्मद इलियास जी सो रहे हैं इनको जागना चाहिए अगर ये नहीं जागे तो जनता इनको जगा देगी। उपाध्यक्ष महादेय, आप तो उसी इलाके के रहने वाले हैं मेवात डिवैल्पमैंट एजेंसी के बारे में मैं आपको बताता हूं।

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पशु पालन राज्य मंत्री (चौ० मोहम्मद इलियास): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से पूछना चाहता हूं कि जब तीन साल पहले इनकी सरकार थी और जब ये खुद उसमें मंत्री थे तो उस समय अरबों का इसमें घोटाला हुआ था और उस समय हम इस बारे में चीखते-चीखते हार गए लेकिन उस सरकार में हमारी सुनने वाला कोई नहीं मिला। जबकि ये आज की सरकार की बात करते हैं मैं इनको बताना चाहूंगा कि गुड़गांव की ग्रीवैंसिज कमेटी में जब एक पब्लिक कम्पलैंट आयी थी तो फौरन मुख्यमंत्री जी ने उस पर ऐक्शन लिया और वहां जो ए०सी०ओ० लगा हुआ था उसके खिलाफ बाकायदा कार्यवाही हुई थी। ये ऐसे कैसे कह सकते है कि इस सरकार में कोई करप्शन की बात हो रही है या कोई घपला हो रहा है। इनको अपनी सरकार के बारे में बात करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, आप जल्दी वाईंड आप करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारी सरकार के वक्त कोई घपला हुआ है तो ये हमारे खिलाफ कार्यवाही करें इनको रोकता कौन है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से इस अभिभाषण में हैल्थ के बारे में भी चर्चा की गयी है। सर, जब तक इस हरियाणा में और खासकर गांवों मे रहने वाले लोगों को आयुर्वेद की शिक्षा के बारे में या आयुर्वेद की दवाईयों के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक हरियाणा के लोगों की सेहत ठीक नहीं हो सकती। मेरा हैल्थ मिनिस्टर साहब से अनुरोध है कि वे आयुर्वेद के बारे में जरूर कोई प्रोग्राम लेकर आएं। सहकारिता के क्षेत्र में उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस बात का दुख है कि आज पूरे देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा ब्याज की दर हरियाणा का कोऑपरेटिव बैंक वसूल करता है। मैंने पिछले दिनों एक प्राइवेट मैंबर का बिल दिया और एक ऐप्लीकेशन दी कि किसान जो मूलधन लेता है उससे मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूला जाता है इस बारे में मेरा कहना यह है कि मूलधन से ज्यादा ब्याज किसी भी हालत में नहीं वसूला जाना चाहिए। हरियाणा में अब वह भी होने लग रहा है। संपत सिंह जी इस बारे में आप अपना कोई प्रोग्राम लेकर आएं। इसी तरह से एस०सीज० और एस०टीज़० की बात कही गई। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप वाइंड अप करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो गरीब दलित वर्ग के लोग हैं जो हरिजन हैं, पिछड़ी जातियों से हैं उनको दबाया जा रहा है उनके बारे में इस अभिभाषण में कोई रिलीफ की बात नहीं की गई है और उनके लिए निकाले हुए पदों पर सरकार के चहेतों को गलत व गैर कानूनी तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं और तो और इंदिरा आवास योजना जो हरिजनों के लिए होती है उस पर भी अपने चहेतों को ऐडजस्ट करने में लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय, हमारे फरीदाबाद जिले की ग्रिवैंसिज कमेटी के इन्चार्ज हैं और आज सदन में बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कल हमारे फरीदाबाद जिले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने करोड़ों रुपये का ठेका इनके रिश्तेदार को कानूनों को ताक पर रखकर पुलिस की मौजूदगी में 250-300 सिपाहियों को खड़ा करके जबरदस्ती दिलवाया और सरकार को लाखों रुपये का चूना लगवाया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुख्य मंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? अगर मेरी बात झूठ हुई तो जो सजा यह सदन कहेगा वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। (विघ्न) बताइए, मुख्य मंत्री जी आप क्या कोई आश्वासन देते हैं ये नीचे गर्दन

करके बैठने से काम नहीं चलेगा। आप बताएं कि जो मैं कह रहा हूं वह गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। इस तरीके से यह सरकार हरियाणा प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है हमारे जिले में जो हमारे हिस्से का पानी आगरा नहर से आता है उस हिस्से को कम कर दिया गया है आज हमारे इलाके का किसान पानी के लिए तरसता रहता है। (विघ्न) कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कोई नोटिस नहीं है। * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : अब कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान) मांगे राम जी, आपकी पार्टी द्वारा जो लिस्ट सुबह दी गई थी उसमें से सारे बोल चुके हैं। एक लिस्ट अभी और आई है।

श्री मांगे राम गुप्ता : सर, वह लिस्ट कल के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन अभी तो सदन का समय चल रहा है।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का टाइम डेढ़ बजे तक था। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना.

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : एक दो सदस्य आपके बोलने वाले इस समय सदन में नहीं है इसलिए मांगे राम जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ता : मैं तो आज नहीं बोलूंगा। मैं तो कल बोलूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आपको बोलने का समय दिया जा रहा है आप बोल नहीं रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि काल करन्दा आज कर, आज करन्दा अब।

श्री मांगे राम गुप्ता : समय देने का यह क्या तरीका है। हम कोई पब्लिक स्पीच देने नहीं आए हैं कि चाहे जो कुछ बोल दें। हमने यहां बोलकर के कोई नंबर नहीं बनाने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आप बोलें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री लछमण दास अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : कल तो चेयर की मर्जी है टाइम मिले या न मिले। कोई सदस्य एक इश्यू पर एक ही बार बोल सकता है।

श्री भागी राम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि गांव में अगर कोई भैंस न बोले तो हम इलियास जी वाला इजैंक्शन लगवाया करते हैं अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो इनको इलियास जी वाला इजैंक्शन लगवाकर बुलवा लें।

श्री मांगे राम गुप्ता : इलियास तो हमारा चेला है हमने इसको भेज रखा है थ्यारै लगायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम गुप्ता जी, आपने कुछ बोलना है।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पब्लिक स्पीच देना नहीं चाहते। पब्लिक स्पीच के लिए तो एक घण्टा चाहिये लेकिन जो आपने प्रोग्राम दिया है और जिस चीज पर हम बोलना चाहते हैं तो उसके मुताबिक हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम आया है।

श्री मांगे राम गुप्ता : यह तो सात तारीख के लिए है। कुछ तो डैकोरम रखा जाये हाउस का। डिप्टी स्पीकर सर, यह तो कोई तरीका नहीं है। आपने बी०ए०सी० में प्रोग्राम पास किया है हमने तो नहीं किया। हम आपके प्रोग्राम के मुताबिक बैठे हैं हमने तो प्रोग्राम नहीं बनाया। हम तो आपके प्रोग्राम के मुताबिक बैठे हैं यह हमारा फर्ज नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कल से आपके नेता कह रहे थे कि सबको बोलने का मौका दिया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी फ्राखदिली की दाद देनी पड़ेगी कि आप खुलकर समय दे रहे हो। मेरा आपसे यह अनुरोध है जो इस सम्मानित सदन का सदस्य नहीं बोलना चाहे तो उसके लिए आप इनसे लिखित में ले लो कि फिर समय नहीं मांगेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आज हम समय दे रहे हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, लिखित में देने की जरूरत नहीं है अगर आप बोलने का समय नहीं देना चाहते तो हम नहीं बोलेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मांगे राम गुप्ता जी, आप एफ०एम० रहे हो, आपको पता है कि सैशन पर करोड़ों रुपये हर रोज खर्च होता है और पब्लिक मनी का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा हो। आप तो वैसे भी बनिया समाज से हो आप तो बोलिए कुछ न कुछ।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आप फ्राखदिली से कह रहे हो, हाउस आपने बुलाया है। बी०ए०सी० कमेटी में आपने प्रोग्राम दिया है। उसके मुताबिक हम आपके पाबंद होकर बैठे हैं। वरना हमें डेढ़ बजे उठकर चले जाना चाहिए था। हम आपका सम्मान करते हैं, चेयर का सम्मान करते हैं। हम डेढ़ बजे से चार बजे तक बैठे हैं। यह कोई तरीका नहीं है। डिप्टी स्पीकर सर, हमारे से लिखवाने की जरूरत नहीं है। हम हाउस में जो बात कहते हैं वे बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। नहीं बुलवाना चाहते तो न बुलवाएं लिखवाने की क्या जरूरत है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम गुप्ता जी, मैं आपको बोलने के लिए ही कह रहा हूं, बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं।

श्री मांगे राम गुप्ता : हमें यहां बोलकर बहुत बड़े नम्बर नहीं बनाने।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मांगे राम गुप्ता जी, आप और हम सारे इस सदन के सदस्य थे। हम रो-रो के मर जाया करते थे। हमें समय नहीं मिलता था। आपको इस चेयर की दाद देनी चाहिए। आपको समय दे रहे हैं और आप बोल नहीं रहे हैं। आपको खुलकर समय दिया है। जो भी सदस्य बोले हैं उनको खुलकर समय दिया है। अब अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो फिर हाउस को एडजर्न करवाने के लिए हम उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : डिप्टी स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी फ्राखदिली से कह रहे हैं। आपको बड़ी फ्राखदिली दिखा रहे हैं। आपको समय देना है तो दलाल साहब को समय दो। जो सदस्य बोलना चाहता है उसकी तो आप घंटी में गूंठा दे रहे हो। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप दलाल साहब के कब से वकील बन गये।

श्री मांगे राम गुप्ता : यह हमारा कुलीग है, विधायक है, विधानसभा का सम्मानित सदस्य है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पार्टी की बात करो। उनको पहले समय दिया जा चुका है।

श्री मांगे राम गुप्ता : जो सदस्य बोलना चाहता है उसको आप समय नहीं दे रहे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मांगे राम गुप्ता जी, समय तो सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को दिया जाता है। एक अकेली पार्टी का एक अकेला विधायक और उसको इतना समय दिया इसके लिए आप उनकी सराहना नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को एडजर्न करें।

Mr. Deputy Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 7th March, 2003.

*15.50hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 7th March, 2003)

36721—H.V.S.—H.G.P., Chd.